HP/129/SML/2019-2021 Title Code : HPBIL00313 RNI Reference No. 1328500 16-30 अप्रैल, 2019

द रीव टाइम्स
The RIEV Times

हिमाचल, वर्ष 1/ अंक 19/ पृष्ठ: 16 मूल्य: ₹ 25/-

मौसम का हाल

मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में मौसम आगामी दिनों में करवट बदलेगा। अगले सप्ताह में मैदानी, कम ऊंचाई वाले और चोटियों पर 15,16,17,18 अप्रैल को वर्षा तुफान और गरज के साथ छीटें पड़ेगें । 19 अप्रैल के बाद मौसम शुष्क रहेगा तथा गर्मी बढ़ने के आसार है।

www.therievtimes.com स्वतंत्रता का एक मायने यह भी है कि यह हमें बेहतर होने का अवसर प्रदान करती है : डॉ॰ एल.सी. शर्मा

द रीव टाइम्स में अन्दर पढ़ें.....

- पृष्ठ 2... बढ़ते कदम
- पृष्ठ 3 से 6...ज़िलावार ख़बरें
- पृष्ठ 7...जलियांवाला बाग शताब्दी वर्ष
- पृष्ठ 8...संपादकीय: Exercising Unconstitutional Rights
- पृष्ठ 9...अभिव्यक्ति: अश्वथामा हतो नरो वा कुंजरो
- पृष्ठ 10...प्रादेशिक हिमाचल संपूर्ण
- पृष्ठ 11...राष्ट्रीय समाचार
- पृष्ठ 12...अंतर्राष्ट्रीय समाचार
- पृष्ठ 13...समसामयिक
- पृष्ठ 14...योजनाएं -अनुभव, स्वरोजगार, युवा आजीविका
- पृष्ठ 15...प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण योजना
- पृष्ठ 16...सर्विस सेवा ऐसोसियेट की भर्तियां....प्रशिक्षण एवं रोजगार

THE RIEV TIMES
OFFICIAL MEDIA PARTNER
krishi & Wellness
INDIA 2019 EXPO
Linking Agriculture, Food & Wellness
06-07-08 August 2019
Pragati Maidan, New Delhi, India

द रीव टाइम्स
आपकीआवाज़हींहै
हमारीआवाज़

उत्तर प्रदेश में कौशल विकास में आईआईआरडी दे रहा प्रशंसनीय सेवाऐं
प्रशासनिक मुख्य न्यायमूर्ति इलाहाबाद ने प्रदान किए नियुक्ति पत्र

द रीव टाइम्स (हेम राज चौहान)
आईआईआरडी द्वारा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार के द्वार खोले हैं। इसके तहत विभिन्न ट्रेड में युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है और साथ ही प्रशिक्षण के उपरांत उन्हें नियुक्तियां भी प्रदान की जा रही हैं। सेन्ट ऐन्ड्यूज डिग्री कॉलेज में विधिक साक्षरता शिविर में प्रशासनिक मुख्य न्यायमूर्ति इलाहाबाद उच्च न्यायालय जस्टिस गोविंद माथुर ने इन युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर आईआईआरडी की टीम और अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे ।

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में आईआईआरडी द्वारा विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भारत सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना से युवाओं को न केवल प्रशिक्षण प्राप्त हो रहा है बल्कि प्रशिक्षण उपरांत विभिन्न सेक्टर में नियुक्तियां भी प्रदान की जा रही है। इसी के तहत इस कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश ने इन युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। उन्होंने आईआईआर्रडी की सेवाओं को भी सराहा और युवाओं को भी भविष्य के लिए शुभकामनाऐं दी।

इसी प्रकार इस बार यह सम्मान युवाओं को इलाहाबाद प्रशासनिक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा प्रदान किया गया है । इस अवसर पर एपीएम आनंद यादव, एमआईएस प्रबन्धक अभय श्रीवास्तव, अवनीश चंद्र, क्षमा कपूर, अरुण शर्मा, भूपेन्द्र श्रीवास्तव, आईआईआरडी की ओर से अमित श्रीवास्तव भी मौजूद रहे ।

इससे पूर्व भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आईआईआरडी से प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। उन्होंने इसे मोदी सरकार की उपलब्धि बताते हुए कहा था कि देश में युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार के द्वार खुले हैं और आईआईआरडी के माध्यम से इन युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण के बाद नियुक्तियां प्रदान की जा रही है ।

देश के अन्य राज्यों में भी देंगें युवाओं को प्रशिक्षण

आईआईआरडी प्रबन्ध निदेशक डॉ० एल. सी. शर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश ही नहीं भारत के अन्य राज्यों में भी युवाओं के लिए भारत सरकार के सौजन्य से प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार मुहैया करवाया जाऐगा। आईआईआरडी द्वारा इसके लिए अथक प्रयास जारी रहेंगे ।

उत्तर प्रदेश के समाचार पत्रों में छाया रहा आईआईआरडी का नाम

कौशल विकास के छात्रों को मिला नियुक्ति पत्र

गोरखपुर। सेन्ट एण्ड्यूज डिग्री कॉलेज में विविध सेवा शिविर में मुख्य अतिथि प्रशासनिक न्यायमूर्ति इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लगे स्टालों में कौशल विकास आईआई आरडी के तहत प्रशिक्षण प्राप्त विभिन्न जनपदों के छात्रों को नियुक्ति पत्र दिया गया इस अवसर पर एपीएम आनंद यादव एमआईएस मैनेजर अभय श्रीवास्तव अवनीश चंद्र क्षमा कपूर अरुण शर्मा भूपेंद श्रीवास्तव की मौजूदगी में कार्यक्रम संपन्न हुआ।

चिफली राजनीति में डांवाडोल अनिल शर्मा
इधर चला मैं उधर चला...की पशोपेश स्थिति में धर्मसंकट बरकरार

हेम राज चौहान

हिमाचल प्रदेश की राजनीति में अनिल शर्मा ने सियासी पैंतरेबाजी से गर्माहट तो ला ही दी है । पिछले कुछ दिनों से जो सियासी ड्रामा प्रदेश की राजनीतिक मंच पर चल रहा है उसका सूत्रधार मंडी का पंडित सुखराम परिवार ही है और इसकी पटकथा भी बखुबी तराश कर लोगों के सामने लाई गई है । कांग्रेस पार्टी का परिवार सियासी उठापठक में बीजेपी का हो जाता है और मंत्री पद भी ग्रहण कर लेता है । उसके बाद लोकसभा के लिए फिर से टिकट की मांग बीजेपी के पास रखता है जो पूरी न होने पर फिर से परिवार के मुखिया कांग्रेस में न केवल घर वापसी कर लेते हैं बल्कि टिकट भी लेकर आ जाते हैं । कांग्रेस के दिग्गज मुंह देखते रह गए । इसी उहापोह में प्रदेश सरकार के ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा अपना धर्मसंकट कुछ कम करते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं । लेकिन सियासी दांवपेच में संतुलन बिठाना मुश्किल हो रहा है । मंत्री पद तो त्याग दिया लेकिन बीजेपी की सदस्यता नहीं छोड़ने के पीछे दुविधा को समझा जा सकता है। मतदाता अब पहले जैसे भी नहीं रहे हैं कि चुनाव निशान देखकर ही वोट करते हैं। अब व्यक्ति आधारित राजनीति का बोलबाला भी है जिसमें उम्मीदवार को भी देखा जाता है । हालांकि हिमाचल प्रदेश में राजनीति का प्रारुप भिन्न और शांत ही रहा है लेकिन इस बार के लोकसभा के चुनावों में मंडी संसदीय सीट पर जो कुछ घटित हुआ और हो रहा है उससे राष्ट्रीय स्तर पर हलचल देखी जा रही है । पंडित सुखराम हिमाचल में राजनीति के चाणक्य कहे जाते रहे हैं । वीरभद्र सिंह से उनका 36 का आंकड़ा भी जगजाहिर है, ये अलग बात है कि पुत्र-पौत्र मोह में गले लगाने की विवशता तो है ही । अनिल शर्मा किसी भी सूरत में अपने पुत्र आश्रय को मंडी से सांसद बनाकर इस बाजी को जीतना चाह रहे हैं जिसके लिए उन्होंने अपना मंत्री पद तो गवांया ही साथ ही उनकी विधायकी पर भी अब तलवार लटक रही है ।

मंत्री पद त्यागा, BJP नहीं छोड़ी....अनिल शर्मा

अनिल शर्मा ने कहा है कि उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन वह बीजेपी में बने हुए हैं। अनिल शर्मा मंडी लोकसभा क्षेत्र के मंडी से विधायक हैं और पार्टी चाहती थी कि वह लोकसभा प्रत्याशी राम स्वरूप शर्मा के पक्ष में प्रचार करें । शर्मा ने कहा कि वह अपने आपको मंडी से दूर रखेंगे और ना तो वह बेटे के पक्ष में और ना ही बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करेंगे ।

बेटे का प्रचार करने के लिए अनिल ने छोड़ा मंत्री पद: कौल सिंह

कार्यकर्ता सम्मेलन में कौल सिंह ने कहा कि बेटे का प्रचार करने के लिए अनिल शर्मा ने मंत्री पद छोड़ा है। सम्मेलन में उन्होंने सीएम जयराम की कार्यप्रणाली पर निशाना साधा।

सीएम पर दे मारा इस्तीफा, विधायकी से हटाए तो रौद्र रुप देखने को रहें तैयार: आश्रय

आश्रय ने भी धमकी भरे लहज़े में भाजपा को चेताया है। उन्होंने एक कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा भाजपाई कहते हैं कि अनिल शर्मा सत्ता के लालची हैं। लेकिन उन्होंने इस्तीफा सीएम और सरकार के मुंह पर फेंककर मारा है। अगर भाजपाइयों को तकलीफ है तो पार्टी से निकालकर देखें और फिर सुखराम का रौद्र रूप देखने को मिलेगा।

भाजपा महामंत्री ने साधा निशाना, बोले पेंडुलम की तरह न झूलें अनिल शर्मा

भाजपा महामंत्री और पार्टी के चुनाव प्रबंधन के संयोजक चंद्रमोहन ठाकुर ने कहा कि अनिल शर्मा पेंडुलम की तरह न झूलें। वह भाजपा से विधायक बने हैं और विधायकी छोड़कर उन्हें फ्रेश मेंडेट लेना चाहिए।

चंद्रमोहन ठाकुर ने स्पष्ट कहा कि अनिल शर्मा की वर्तमान में स्थिति आधे कांग्रेसी और आधे भाजपाई जैसी है । ऐसे में उन्हें न तो भाजपा मानेगी और न ही शायद कांग्रेस मान्यता दे सकती है। अनिल शर्मा में अगर थोड़ी भी नैतिकता बची है तो वह विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दें।

भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष गणेश दत्त ने भी कहा कि अनिल शर्मा को बंद कमरे में बेटे के लिए प्रचार करने के बजाय विधानसभा की सदस्यता छोड़कर खुले में प्रचार करना चाहिए। दोनों नेताओं ने एक संयुक्त प्रैस वार्ता में ये बातें कही है।

रीव फीड सप्लिमेंट अब देश के बाहरी राज्यों में भी बिकेगी
हरियाणा और पंजाब में डेयरी फार्म की मिली सराहना

द रीव टाइम्स
हेम राज चौहान

मिशन रीव ने हिमाचल प्रदेश में दुधारु पशुओं में गुणवत्ता और मात्रा में वृद्धि हेतु रीव फीड सप्लिमेंट किसानों एवं पशुपालकों के लिए उपलब्ध करवाया जिसके सफल परिणाम प्रदेश के विभिन्न ज़िलों से सामने आए हैं । इसके बाद अब रीव फीड सप्लिमेंट दुग्ध उत्पादक राज्यों में अव्वल हरियाणा व पंजाब में भी अपनी गुणवत्ता के साथ उपलब्ध करवाया जाऐगा । इस बाबत मिशन रीव की ओर से एक टीम मिशन रीव की गवर्निंग काऊंसिल के सदस्य आन्नद नायर एवं मुकुल सक्सेना की अगुवाई में हरियाणा और पंजाब के दुग्ध डेयरी फार्म, पशुपालकों एवं गऊशालाओं के पदाधिकारियों एवं सेवाकर्मियों से मिले तथा रीव फीड सप्लिमेंट को लेकर चर्चा की ।

गांव वासियों को गांव में ही रोजगार मुहैया करवाना 'आई.आई.आर.डी.' संस्था का उद्देश्य : दत्ता/नायर

लुधियाना, 10 अप्रैल (स.ह.): चंडीगढ़ रोड पर जमालपुर व पोंगुआ गोशाला (गौ सेवा समिति) द्वारा गांव में रोजगार मिशन को लेकर प्रोग्राम का आयोजन किया गया।

प्रोग्राम में 'आई.आई.आर.डी.' संस्था के जितेंद्र दत्ता, अमरेंद्र नायर, मुकुल सक्सेना, भूपिन्द्र सिंह के नेतृत्व में रोजगार मोहिन्दपाल सिंह, कोषाध्यक्ष डी.एन. जोशी, सुदर्शन शर्मा बाबजी, प्रेम नागर, आर.के. शर्मा, नवीन बजाज, प्रदीप मित्तल, करतूत राम पोंगुआ, सुरिन्द्र कुमार, राम गुप्त, के.के. गर्ग ने उनका स्वागत किया।

नायर व दत्ता ने कहा कि उनकी संस्था उद्देश्य गांव में लोगों को मिशन के साथ जोड़कर गांव में ही रोजगार मूलीय कारबारों और मुर्गीफार्मों का किस तरह लाभ उठाया जाना चाहिए बारे जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि गांव के लोगों के लिए संस्था द्वारा कई तरह के प्रोजैक्ट तैयार करके रोजगार के अवसर पैदा किए गए हैं, जिनका लाभ उठाकर करीब 60,000 गांव वासी कमाई खुश हैं। साथ ही में संस्था द्वारा सुपर फूड के नाम से मशहूर (हरी कोई) लियमलीन पशुओं की खुराक तैयार की गई है, जो अन्य जानवरों को भी दी जा सकती है। एम.पी. जैन ने कहा कि संस्था द्वारा ऐसी छोटी जीजों से गांव में लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना प्रशंसा योग्य है, जबकि अब पंजाब व हरियाणा के लोगों को गांव में रोजगार मिशन बारे जागरूक किया जा रहा है।

पंजाब केसरी ई-पेपर Thu, 11 April 2019 https://epaper.punjabkesari.in/c/38428972

विस्तृत विवरण पृष्ठ 2 पर पढ़ें...

FLAT/PLOT FOR SALE
IN SHIMLA & CHANDIGARH
BUY 2 BHK FLAT
WITH PLOT
NEAR BY CHANDIGARH
JUST FOR Rs. 25,00,000/-
Call: 70182-01049/80911-27000

अब पंजाब – हरियाणा में भी रीव फीड सप्लीमेंट देगा मिशन रीव

हिमाचल में मिल चुके हैं, बेहतरीन परिणाम

द रीव टाइम्स ब्यूरो, शिमला

हिमाचल में मिशन रीव की सेवाओं के बाद अब आईआईआरडी की ओर से देश के दूसरे राज्यों में भी इस मिशन के तहत सेवाएं दी जा रही है। इसी कड़ी में हरियाणा व पंजाब में मिशन रीव के तहत पशुधन के माध्यम से आय कमाने वाले पशुपालकों को सेवाएं पहुंचाने की शुरूआत की गई है। हरियाणा में आईआईआरडी के अधिकारियों ने पशुपालकों की समस्या जानने के लिए उनके साथ विशेष सभाओं का आयोजन किया और बेहतर दुग्ध उत्पादन और पशु स्वास्थ्य को लेकर पशुपालकों को पेश आ रही विभिन्न समस्याओं के बारे में भी बात की।

इस दौरान मिशन रीव के तहत उपलब्ध करवाए जा रहे रीव फीड सप्लीमेंट की जानकारी भी पशुपालकों को दी गई। आईआईआरडी के तहत फ्लायर ग्रुप के निदेशक आन्नद नायर ने बताया कि हिमाचल में भी रीव फीड सप्लीमेंट के काफी सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इस सप्लीमेंट से जहां पशुओं के दूध देने की क्षमता में बढ़ोत्तरी हुई वहीं पशुओं के स्वास्थ्य में भी सुधार देखा गया। हिमाचल में रीव फीड सप्लीमेंट के बेहतरीन परिणाम के बाद अब इसे हरियाणा के पशुपालकों को भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

इसी कड़ी में मिशन रीव की टीम ने सबसे पहले फ्लायर ग्रुप निदेशक आन्नद नायर तकनीकि विशेषज्ञ रितेश दत्ता की अगुवाई में सोनीपत स्थित डेयरी धमार्थ गऊशाला सिसाना का दौरा किया और वहां पर रीव फीड सप्लीमेंट की जानकारी दी। यहां पशुपालकों ने बताया कि उन्हें बाजार से काफी महंगे दामों पर फीड लानी पड़ती है और परिणाम भी उस हिसाब से नहीं मिल पाते। लेकिन रीव फीड सप्लीमेंट बाजार में मिलने वाले दूसरे सप्लीमेंट के मुकाबले बहुत किफायती है और इसके लाभ भी अधिक प्रतीत हो रहे हैं।

इसके बाद लुधियाना जमालपुर गौशाला में भी रीव फीड सप्लीमेंट की जानकारी दी गई। इस दौरान गौशाला के चेयरमैन मोहिंद्र पाल जैन ने मिशन रीव के कांसेप्ट को पूरी तरह समझा और मिशन रीव को अनोखा करार देते हुए इसकी जमकर सराहना की। इसी तरह हरियाणा में विभिन्न स्थानों पर रीव फीड सप्लीमेंट के बारे में पशुपालकों को विस्तार से बताया गया। अधिकतर पशुपालकों ने इस सप्लीमेंट के बारे में जानकर इसे बाजार में मिलने वाले दूसरे सप्लीमेंट से बेहतर करार दिया।

MISSION RIEV

Ruralising India- Empowering Villages

कि दुनिया देखती रह जाए

LIVESTOCK FEED SUPPLEMENT

क्यों खास है रीव फीड सप्लीमेंट

मिशन रीव फीड सप्लीमेंट दुध उत्पादन बढ़ाने का सफल एवं अचूक उपाय है जिसके नियमित सेवन से दुधारू पशु का दूध एवं फैट बहुत ही कम समय मे बढ़ जाता है।

यह एक प्राकृतिक उप्ताद है जो पानी पर जमने वाली काई से तैयार की जाती है। पानी पर जमने वाली काई में प्रकृति में पाये जाने वाले भरपूर खनिज शामिल होने के कारण यह पशुओं को बिना नुकसान पहुंचाये दूध एवं फैट बढ़ाने में सहायता करता है। फीड सप्लीमेंट को नियमित तौर पर पशुओं को देने से सेहत तथा बीमारियों से लड़ने की ताकत मिलती है जिससे पशु जल्दी बीमार नहीं पड़ता तथा पशुओं की आने वाली नस्ल तंदरूस्त तथा हृष्ट-पुष्ट रहती है। इस सप्लीमेंट को देने के बाद पशु की खुराक पर भी असर देखा गया है। यह हरे चारे की कमी को भी पूरा करता है। पशु के दूध देने के समय मे भी सुधार आता है और पशु लंबे समय तक दूध देता है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है।

उपयोग की विधि

रीव फीड सप्लीमेंट को पशु आहार के साथ मिला कर दिया जाता है यह एक पाउडर के रूप होता है जिसे दुधारू पशु के दिन मे दिये जाने वाले दूध की मात्रा के हिसाब से पशु आहार मे मिला कर दोनों समय पर दिया जाता है। इसे पशु आहार में मिलाने से पहले कम से कम 3–4 घण्टो तक तक पानी मे भिगो कर रखे। इसे गाय व भैंस को लगातार देने के चौथे दिन से ही दूध तथा फैट में बढ़ोतरी होना शुरू हो जाती है।

रीव फीड सप्लीमेंट की प्रयोग विधि

गाय के लिए

अगर गाय दिन भर मे 10 किलो दूध देती है तो पूरे दिन में 10x5 ग्राम = 50 ग्राम रीव फीड सप्लीलमेंट को पशु आहार में मिला कर दोनों समय; (25x25) ग्राम देना है।

भैंस के लिए

अगर भैंस दिन भर मे 10 किलो दूध देती है तो पूरे दिन में 10x7 ग्राम, 70 ग्राम रीव फीड सप्लीलमेंट को पशु आहार में मिला कर दोनों समय (35X35) ग्राम देना है।

बकरी के लिए

बकरी का दूध बढ़ाने हेतु 10 ग्राम दिन के हिसाब से दी गई खुराक ही पर्याप्त है।

ध्यान देने योग्य बातें

रीव फीड सप्लीमेंट को बेहतर परिणाम हेतु इसे पानी मे 3–4 घण्टे पहले भिगो कर रख दे और इसे पशु आहार के साथ अच्छी तरह से मिला कर पशु को दे।

अगर भूलवश इस मिश्रण को पानी मे भिगोये हुए 7–8 घण्टे या इससे अधिक समय हो गया हो तो इसे पशु को ना दे।

दूध नही देने वालो पशुओं तथा ताजे ब्याये पशु को रीव फीड सप्लीमेंट नही दे। ताजे ब्याये पशुओं (गाय, भैंस एवं बकरी) को 15 दिनों के बाद ही रीव फीड सप्लीमेंट देनी चाहिए।

(रीव फीड सप्लीमेंट भेड़, मछली, मुर्गी तथा घोड़े के लिये भी तैयार की जाती है।)

नोटः कृपया नमी से दूर रखें।

आयोजकः फ्लायरज़ ग्रुप प्रा.लि. फोनः 0177-2640761

ई-मेलः anand@iirdshimla.org

निर्माताः- ट्रांसटेक ग्रीन एनर्जी प्रा.लि. प्लॉट नं 3, आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर-302021

गर्मियों के लिए तैयार शिमला

उपायुक्त ने पानी की उचित व्यवस्था करने के दिए निर्देश

द रीव टाइम्स ब्यूरो, शिमला

उपायुक्त शिमला राजेश्वर गोयल ने निर्देश दिए हैं कि गर्मियों में शिमला शहर और आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छ तथा सुचारू जलापूर्ति देने के लिए नगर निगम शिमला और संबद्ध विभाग बेहतर समन्वय स्थापित कर कार्य करें। हाल ही में जलजनित रोगों से बचाव तथा सुचारू जलापूर्ति के संबंध में आयोजित बैठक के दौरान राजेश्वर गोयल ने कहा कि जिला प्रशासन व नगर निगम द्वारा लोगों को समुचित एवं स्वच्छ जलापूर्ति सुनिश्चित बनाने के लिए विशेष प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि रिसाव वाली मुख्य ट्रंक लाईनों को बदलने का कार्य लगभग पूर्ण कर लिया गया है, जिससे पेयजल लाइन में हो रहे रिसाव में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि गिरी, गुम्मा व अश्वनी खड्ड जल स्त्रोतों में पानी की उपलब्धता व उचित संग्रहण क्षमता को बनाने के लिए चौक डैम और वर्षा जल संग्रहण ढांचे निर्मित किए जा रहे हैं, ताकि शिमला शहर में पानी की उपलब्धता की कमी को दूर किया जा सके। इसके अतिरिक्त विभिन्न अन्य क्षेत्रों से जलापूर्ति योजनाओं को सुचारू बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सर्दियों में हुई पर्याप्त बर्फबारी एवं वर्षा के कारण भी विभिन्न जल स्त्रोतों में पानी उचित मात्रा में उपलब्ध है। राजेशवर ने नगर निगम को निर्देश दिए कि वे विभिन्न वार्डों के लिए समय सारिणी निर्धारित कर समान जल वितरण सुनिश्चित किया जाए।

फेसबुक फ्रेंड ने लगाई 10 लाख की चपत

रीव टाइम्स ब्यूरो, शिमला

शिमला का एक व्यक्ति फेसबुक फ्रेंड के धोखे का शिकार हुआ है। फेसबुक फ्रेंड के झांसे में आकर इस व्यक्ति ने उसके खाते में 10 लाख की राशि जमा कर दी। इस बाबत पीड़ित ने शिमला सदर थाने में शिकायत दर्ज करवाई। मामला दर्ज करने के बाद पुलिस इसकी जांच में जुट गई। पुलिस से प्राप्त जानकारी के तहत शिमला के एक व्यक्ति को फेसबुक पर डेविड नाम के व्यक्ति के एकाउंट से फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। फेसबुक फ्रेंड बनने के बाद डेविड ने उसे शिमला में जमीन खरीदने संबंधित चर्चा की। कुछ समय के बाद डेविड ने फेसबुक पर उन्हें सूचित किया कि उसने उन्हें कोई महंगा गिफ्ट भेजा है। इतना ही नहीं पीड़ित का आरोप है कि उसे मुंबई एयरपोर्ट से गिफ्ट के बाबत फोन आया था। उसे फोन पर कहा गया कि गिफ्ट रिलीज करने के लिए उसे खाते में धनराशि जमा करनी होगी। पीड़ित भी इस झांसे में आ गया और उसने भी बताए गए एकाउंट में 10 लाख रूपए जमा कर दिए। जब उसके बाद बाद भी उसे गिफ्ट नहीं मिली तो उसे लगा कि उसके साथ बड़ा धोखा हुआ है। उसने सदर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर इसकी छानबीन शुरू कर दी है। उल्लेखनीय है कि शिमला में इस तरह के कई मामले प्रकाश में आ चुके हैं। फेसबुक फ्रेंड के झांसे में आकर कई लोग लाखों रूपए गंवा चुके हैं। हालांकि पुलिस द्वारा जनता को इस तरह के फेसबुक फ्रेंडों से बचने की सलाह दी गई है। मगर इसके बावजूद भी शहर के कई लोग इस तरह के झांसे में आ रहे हैं।

राजधानी के मंदिरों में रही नवरात्रों की धूम

रामनवमी पर हुआ भंडारे का आयोजन

द रीव टाइम्स ब्यूरो, शिमला

राजधानी शिमला के शक्तिपीठों में भगवती दुर्गा के नौं रूपों की की पूजा-अर्जना बड़ी धूमधाम से की गई। मंदिरों में विशेष प्रकार से पूजा-पाठ किया गया। हिंदु साल के पहले महीने चैत्र नवरात्र के पहले दिन से ही सभी मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। हिंदू पंचांग के मुताबिक चैत्र नवरात्र से ही नए साल की शुरूआत होती है। नवरात्र के पहले दिन से ही शिमला के शक्तिपीठों में भक्तों की खूब भीड़ लगी रही। वहीं, दूसरी तरफ राम मंदिर में इस मौके पर सुंदर पाठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिरों को रंग-बिरंगे कृत्रिम फूलों व लाइटों से सजाया गया है। मंदिर परिसर इतने सुंदर लग रहे थे कि प्रवेश करते ही श्रद्धालु मां की भक्ति में सराबोर हो जाते। ऐसे में भक्तों द्वारा मां के जयकारों से सारा माहौल भक्तिमय भाव में डूबा हुआ नजर आया।

मंदिर परिसर में भी भक्तों की सुरक्षा के मद्देनजर विशेष प्रावधान किए गए हैं। भक्तों को मंदिर में किसी तरह की कोई समस्या न हो इसे देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है, जिसके तहत मंदिर परिसर में हाइटेक कैमरे व पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं।

केलांग-उदयपुर रुट पर दौड़ी एचआरटीसी

द रीव टाइम्स ब्यूरा लाहौल स्पीति

केलांग-उदयपुर रूट पर पांच माह बाद एचआरटीसी की बस सेवा बहाल हो गई है। यहां एचआरटीसी के दौड़ते ही जहां लोगों ने जश्न मनाया, वहीं अब असानी से लोग उदयपुर से केलांग पहुंच सकेंगे। एचआरटीसी के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही लाहुल के अन्य रूटों पर भी बसें दौड़ा दी जाएंगी। निगम के अधिकारी सिर्फ घाटी की सड़कों की बहाली का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में पांच माह बाद जहां केलांग से उदयपुर रूट पर एचआरटीसी की बस सेवा बहाल हुई है, वहीं लोगों ने भी राहत की सांस ली है। ऐसे में जनजातीय जिला लाहुल-स्पीति के लोगों के अब अच्छे दिन आ गए हैं। घाटी में पांच महीने बाद एचआरटीसी की बसें दौड़ना शुरू हो गई हैं। लाहुल घाटी में बस सेवा शुरू होने से लोगों की अधिकतर परेशानियां दूर हो गई हैं। हालांकि चंद्रा वैली अभी भी बर्फ की कैद में है, जिस कारण यहां एचआरटीसी की बस सेवा बहाल नहीं हो पाई है। केलांग-उदयपुर सड़क पर बस को एसडीएम केलांग अमर नेगी द्वारा हरी झंडी दिखा रवाना किया गया। अड्डा प्रभारी सोहन यांबा के मुताबिक उदयपुर से केलांग की तरफ लगभग 70 व केलांग से उदयपुर की तरफ 25 यात्रियों एचआरटीसी बस में सफर किया।

शिक्षा निदेशालय के बाहर अभिभावकों का धरना

द रीव टाइम्स ब्यूरो, शिमला

छात्र अभिभावक मंच ने निजी स्कूलों की मनमानी व भारी फीसों के खिलाफ शिक्षा निदेशालय शिमला के बाहर हल्ला बोला। प्रदर्शन के दौरान ही निदेशक ने मंच पदाधिकारियों को बातचीत के लिए बुला लिया। इसके बाद एक प्रतिनिधिमंडल निदेशक उच्चतर शिक्षा से मिला। प्रतिनिधिमंडल में बिंदु जोशी, फालमा चौहान, भावना, जसबीर कौर, कौशल्या, रमा रावत, मीना, कलावती, रंजना वर्मा, बबली, कुसुम, कौशल्या, लक्ष्मी, पन्ना, श्याम, निशा, सुजाता, राखी, सुमन, रोहित चौहान, जसबीर कौर, भावना, रोशनी, पूनम शामिल रहीं। मीटिंग करीब एक घंटा चली। बैठक में निदेशक उच्चतर शिक्षा के साथ सभी संयुक्त शिक्षा निदेशक भी शामिल रहे। निदेशक उच्चतर शिक्षा ने मंच पदाधिकारियों को आश्वासन दिया कि अब निजी स्कूलों के प्रबंधन से बातचीत का समय खत्म हो चुका है। अब एक्शन का समय है।

हिंद सेवा संगठन ने उद्घोष संस्था के लिए दान की कुर्सीयां

द रीव टाइम्स ब्यूरो, शिमला

सामाजिक कल्याण में सेवारत संस्था उद्घोष ने हिंद सेवा संगठन एव चेयरमैन हिंद सेवा संगठन सुषमा शर्मा का संस्था के लिए सहयोग हेतु आभार व्यक्त किया है। संस्था की संस्थापक सदस्य सीमा चौहान ने यहां जारी एक प्रैस विज्ञप्ति में बताया कि उद्घोष संस्था द्वारा शिमला में एक पुस्तकालय जनसेवा में चलाया जा रहा है। इस पुस्तकालय के अलावा बुजुर्गों के लिए बैठक स्थल का भी संचालन संस्था द्वारा किया जा रहा है । इस पुस्तकालय के लिए हिंद सेवा संगठन की चेयरमैन सुषमा शर्मा और आईआईआरडी के प्रबंध निदेषक डॉ० एल सी शर्मा ने कुर्सीयां दान की है। एक सादे समारोह में ये संस्था के चेयरमैन हेम राज चौहान ने प्राप्त की । सीमा चौहान ने हिंद सेवा संगठन का आभार जताया तथा कहा कि सुषमा शर्मा और डॉ० एल सी शर्मा इस प्रकार से सामाजिक कार्यो में हमेशा जुड़े रहते हैं और उद्घोष की सामाजिक सेवाओं में भी उन्होंने सहयोग दिया है। चेयरमैन एचएसएस सुषमा शर्मा ने बताया कि उद्घोष संस्था युवाओं, महिलाओं एवं बुजुर्गों के उत्थान में प्रशंसनीय कार्य कर रही है। शिमला में बुजुर्गों एवं बच्चों-युवाओं के लिए पुस्तकायल इस संस्था द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें बैठने के लिए कुर्सीयों की आवश्यकता थी जो कि हमारे राष्ट्रीय संगठन एचएसएस ने पूरी करने का वादा किया था। इस संस्था के लिए भविष्य में ही सहयोग जारी रहेगा तथा उनके सामाजिक कार्यों में योगदान दिया जाता रहेगा।

एचपीयू में छात्र खूनी संघर्ष पर राज्यपाल को सौंपी रिपोर्ट

द रीव टाइम्स ब्यूरो, शिमला

शिमला-हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने 24 मार्च को हुए खूनी हमले की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंप दी है। यह रिपोर्ट एचपीयू ने बंद लिफाफे और सील करके राज्यपाल को दी है। अब राज्यपाल ही एचपीयू में छात्रों के बीच हुए हमले में शामिल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश जारी करेंगे। बताया जा रहा है कि राज्यपाल पूरी रिपोर्ट का कुछ दिन अवलोकन करेंगे। एचपीयू की हाई पावर कमेटी ने राज्यपाल को सीसीटीवी फूटेज के साथ ही कमेटी के सभी सदस्यों द्वारा पूछताछ कर बनाई गई रिपोर्ट सौंपी है। सूत्रों की मानें तो एचपीयू की हाई पावर कमेटी द्वारा बनाई गई रिपोर्ट में दोनों छात्र संगठनों के नेताओं के नाम शामिल है। हालांकि विश्वविद्यालय के पूख्ता सूत्रों के मूताबिक राज्यपाल को सौंपी गई रिपोर्ट में अभी भी पूरे तथ्य प्रशासन नहीं जुटा पाया है। बताया जा रहा है कि हाई पावर कमेटी की जांच अभी पूरी नहीं हो पाई थी। प्रशासन को जल्दबाजी में ही आधी - अधूरी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपनी पड़ी। हांलाकि सूत्र बताते है कि अभी तक की रिपोर्ट में लगभग एचपीयू के 21 छात्र नेताओं की पहचान की गई है, जिन्होंने एचपीयू के माहौल को खराब किया है। हांलाकि विश्वविद्यालय का दावा यह भी है कि राज्यपाल से कोई भी निर्देश न आने तक खूनी हमले की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाएंगा।

उल्लेखनीय है कि छात्र गुटों के बीच 24 मार्च को हुई खूनी झड़प मामले की रिपोर्ट सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर और पूरा इग्जैमिन करने के बाद राज्यपाल को सौंपी गई है। बता दें कि एचपीयू में छात्रों के बीच हुए खूनी हमले के बाद कैंपस में माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण बना हुआ है। इसी मामले के बाद विश्वविद्यालय ने बीते 26 मार्च को सर्कुलर जारी कर कई कड़े निर्देश छात्र नेताओं को जारी किए थे। इसके बाद राज्यपाल ने भी रिपोर्ट तलब की थी। समय सीमा में विश्वविद्यालय प्रशासन रिपोर्ट सबमिट नहीं कर पाया, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने राजभवन से जांच रिपोर्ट व अन्य जानकारी भेजने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था। अब जब एचपीयू ने रिपोर्ट तैयार कर राज्यपाल को सौंप दी है तो अहम रहेगा कि अब राज्यपाल इस मामले पर क्या कदम उठाने के निर्देश प्रशासन को देते है।

छितकुल सड़क मार्ग दो महीने से बंद

द रीव टाइम्स ब्यूरो, किन्नौर

इस वर्ष अधिक बर्फबारी होने से किन्नौर के अनेक संपर्क सड़क मार्ग कई दिनों से बंद पड़े है। चीन सीमा से सटा किन्नौर जिला का अंतिम गांव छितकुल को जोड़ने वाला संपर्क सड़क मार्ग मार्ग तो पिछले दो महीनों से बन्द पड़ा है। छितकुल सम्पर्क मार्ग पर बीते दो महीनों से हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस नही चलने से यहां के ग्रामीणों को खासी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। छितकुल गांव के पूर्व पंचायत प्रधान मुकेश नेगी ने बताया कि छितकुल गाँव मे 22 जनवरी के बाद अभी तक बस सेवा ठप्प पड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा दो जेसीबी मशीन छितकुल संपर्क सड़क मार्ग पर से बर्फ हटाने के लिए भेजा गया। जिस मे से एक मशीन तो मस्तरंग नामक स्थान के आसपास खराब पड़ी है जबकि दूसरी जेसीबी मशीन दो महीनों से बर्फ हटाने का कार्य तो कर रहा है लेकिन मार्ग बहाल होने में देरी हो रही है। उन्होंने बताया कि छितकुल सड़क मार्ग लंबे समय से अवरुद्ध होने से छितकुल तक बस सेवाएं पूरी तरह ठप पड़ी हुई है। मस्तरंग नामक स्थान तक आईटीबीपी के वाहनों के अलावा दूसरे वाहन नहीं चल पा रहे है। उन्होंने बताया कि छितकुल गांव मे संपर्क मार्ग के बंद होने के कारण गांव के बड़े बुजुर्ग व मरीज सहित छोटे बच्चों को रकच्छम तक पैदल सफर करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि यदि समय रहते छितकुल गांव तक पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा सड़क को नही खोल पाती है तो विवश हो कर ग्रामीणों को सड़को पर उतरना पड़ेगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम डिप्पो रिकांगपिओ के अड्डा प्रभारी गोपाल नेगी ने बताया कि बर्फबारी के बाद छितकुल में बसों की आवाजाही बंद है अभी बसों को केवल रकच्छम तक भेजा जा रहा है जब छितकुल का संपर्क मार्ग बहाल हो जाएगा उसके बाद बसों को छितकुल भेजा जाएगा।

विकास को लेकर कोमली बैक में महापौर ने की बैठक

द रीव टाइम्स ब्यूरा शिमला

नगर निगम शिमला के अंतर्गत वार्ड अनाडेल के कोमली बैंक में पार्षद एवं महापौर कुसुम सदरेट ने वार्ड की समस्याओं को लेकर सभा आयोजित की। इसमें कोमली बैंक के स्थानीय निवासियों ने भाग लिया तथा अपनी समस्याओं से महापौर को अवगत करवाया । बैठक उद्घोष सभागार में आयोजित की गई जिसमें 70 लोगों ने भाग लिया । इस बैठक में कोमली बैंक में मूलभूत समस्याओं को लेकर महापौर को ज्ञापन भी सौंपा गया । स्थानीय महिलाओं ने कहा कि उनके लिए उज्जवला योजना और ग़रीबों को शहरी आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है । इसके लिए अनेक पात्र महिलाऐं इस कार्यक्रम में उपस्थित थीं तथा उन्होंने कहा कि हमारे पास न तो अपना घर है और न ही केन्द्र सरकार की उज्ज्वला योजना से उन्हें लाभ प्राप्त हुआ। सभा में बी पी एल परिवारों की ग़रीब महिलाओं ने भी भाग लिया तथा उन्होंने अपनी समस्याओं से महापौर को अवगत करवाया ।

कोमली बैंक में कुछ महीनों पहले 50 लाख से अधिक की राशि से बनने वाले सामुदायिक भवन एवं पार्किंग का शिलान्यास किया था जिसका सुचारु निर्माण कार्य अभी भी ठेकेदार द्वारा शुरु नहीं किया गया है। इसके अलावा ऐंबुलैंस भी कोमली बैंक में नहीं आ पा रही है क्योंकि रोड़ के दोनों ओर गाड़ियां बेतरतीब तरीके से खड़ी रहती है। महापौर ने कहा कि कोमली बैंक में करोड़ो के विकास कार्य करवाए गए हैं और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। उन्होंने महिलाओं को आश्वस्त किया कि उन्हें उज्जवला योजना और स्वास्थ्य कार्ड सुविधा से जोड़ा जाएगा। उन्होंने कोमली बैंक के लिए टैक्सी सेवा से जोड़ने पर भी लोगों को आश्वासन दिया। उद्घोष संस्था की संस्थापक एव अध्यक्ष हेम राज चौहान ने महापौर का स्वागत किया और कोमली बैंक की समस्याओं से अवगत करवाया ।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

चिंतपूर्णी में स्थानीय निवासी नहीं लगेंगे कतार में

द रीव टाइम्स ब्यूरो, ऊना

शक्तिपीठ चिंतपूर्णी मंदिर में माता रानी के दर्शन करने के लिए अब स्थानीय लोगों को भी पास की सुविधा दी जाएगी। चिंतपूर्णी मंदिर ट्रस्ट जल्द ही स्थानीय दुकानदारों और रूटीन में मंदिर आने वाले स्थानीय लोगों को दर्शन पास बनाकर देगा। इससे इन लोगों को माता के दर्शनों को लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा।

डीसी और मंदिर आयुक्त राकेश कुमार प्रजापति ने स्थानीय लोगों की परेशानी को देखते हुए यह फैसला लिया है। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से चिंतपूर्णी मंदिर में बैक डोर एंट्री की शिकायतें उपायुक्त को मिली थीं। इसके बाद उपायुक्त ने चिंतपूर्णी

पहुंचकर बैकडोर एंट्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए थे। इसके बाद व्यवस्था में काफी सुधार देखने को मिला। डीसी के इन आदेशों के बाद नियमित मंदिर जाने वाले स्थानीय दुकानदारों और लोगों को काफी परेशानी हुई। मौजूदा दौर में स्थानीय लोगों को श्रद्धालुओं के साथ लाइनों में लगने को कहा जा रहा है। इससे स्थानीय लोगों ने मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ रोष भी जताया।

डीसी राकेश कुमार प्रजापति ने बताया कि स्थानीय दुकानदारों के जो खुद दुकान के मालिक हैं उन्हीं के दर्शन पास बनाएं जाएंगे। इनकी दुकानों पर काम करने वाले कर्मचारियों के पास नहीं बनेंगे। डीसी ने कहा कि आगामी ट्रस्ट की बैठक में इसको लेकर चर्चा की जाएगी फिर इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। डीसी ने कहा कि फिहलाल नवरात्रों में स्थानीय लोगों को लाइन में लगकर दर्शन न करने पड़ें, इसको लेकर मंदिर अधिकारी से बातचीत की जा रही है। चौत्र नवरात्रों में स्थानीय लोगों को मंदिर जाने में कोई परेशानी न हो इसका समाधान भी निकाला जा रहा है।

मनमानी फीस वसूली के खिलाफ अभिभावकों का स्कूल के बाहर धरना

द रीव टाइम्स ब्यूरो, ऊना

टाहलीवाल नगर पंचायत के एएनएम इंटरनेशनल स्कूल द्वारा कथित रूप से मनमानी वसूली किए जाने को लेकर अभिभावकों ने मोर्चा खोल दिया है। बीते दिनों छात्रों के अभिभावकों ने स्कूल परिसर में रोष प्रदर्शन करते हुए जोरदार नारेबाजी की। अभिभावकों का आरोप है कि स्कूल प्रबंधक मनमाने तरीके से बच्चों से फीस आदि की वसूली कर रहे हैं। इसे सहन नहीं किया जाएगा। अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधन को चेताया कि बच्चों के स्कूल चार्ज वसूलने पर मनमानी नहीं करने दी जाएगी।

टाहलीवाल के निजी स्कूल में रोष प्रदर्शन कर रहे अभिभावकों में कृष्ण राणा, संजीव कुमार, सतनाम सिंह, ईशु कंवर, अवतार सिंह, गुरनाम सिह, राजेंद्र राणा, संजीव धीमान, अनिल कुमार, रणवीर सिंह, रामस्वर्ण, निर्मल राणा, चनन सिंह, मीना कुमारी, अमनदीप, नीलम, सीमा देवी ने बताया कि नए शैक्षणिक सत्र में बच्चों के दाखिले के समय बस किराया, मासिक फीस एवं अन्य चार्ज पर बढ़ोतरी कर मनमाने ढंग से वसूली कर रहे हैं।

अपने मोबाइल से करें मतदाता सूची में नाम दर्ज

द रीव टाइम्स ब्यूरो , सिरमौर

मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए वोटर को इधर-उधर नहीं भटकना होगा। अपने मोबाइल पर ही वह राष्ट्रीय मतदाता सेवा की वेबसाइट पर जाकर मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकृत करवा सकता है। पोर्टल पर नाम दर्ज कराते समय कुछ प्रमाण पत्रों की आवश्यकता पड़ेगी, जिन्हें अपलोड करने के बाद प्रक्रिया आसानी से संपन्न हो जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त सिरमौर ललित जैन ने बताया कि युवा मोबाइल के माध्यम से भी अपना नाम मतदाता सूची में पंजीकृत करने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के एनवीएसपी डाट इन पोर्टल और वोटर हेल्पलाइन पर भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए राशन कार्ड, बिजली, पानी, टेलीफोन बिल, गैस, बैंक अथवा डाकघर की पासबुक, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी एक प्रमाण पत्र के अतिरिक्त एक फोटोग्राफ और आयु प्रमाण पत्र की प्रति की आवश्यकता होगी। उपायुक्त कार्यालय के सभागार में सिरमौर जिले के महाविद्यालयों और आईटीआई के मतदाता साक्षरता क्लबों के नोडल अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त ललित जैन ने कहा कि मजबूत लोकतंत्र के लिए सबकी भागीदारी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जिन युवाओं ने पहली जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है और जिन पात्र लोगों ने अभी तक किन्हीं कारणों से अपना नाम वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं करवाया है, वह अपना नाम मतदाता सूची में 19 अप्रैल तक अपने निकटतम बीएलओ या एसडीएम कार्यालय जाकर अवश्य पंजीकृत करवाएं।

बरसात में 372 स्कीमों को गाद से बचाने की तैयारी, 12.73 करोड़ रूपये होंगे खर्च

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सोलन

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग ने बरसात में पेयजल समस्या से निपटने का प्रस्ताव तैयार किया है। आईपीएच विभाग 12.73 करोड़ रुपये पेयजल स्कीमों पर खर्च करने की योजना तैयार की है। इससे गाद की समस्या पर रोक लगेगी और लोगों को पानी की नियमित सप्लाई होती रहेगी। बरसात के दिनों में अकसर पानी की स्कीमों में गाद की समस्या गंभीर रूप धारण कर लेती है। स्कीमों में गाद के आने से पानी की लिफ्टिंग भी नहीं हो पाती है। इसके चलते लोगों को पानी के लिए भटकना पड़ता है। कई बार पानी के लिए कोहराम मच जाता है। अब सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग ने बरसात के मौसम में स्कीमों में आने वाली गाद की समस्या को लेकर प्रपोजल बना कर भेज दिया है। इस पर मुहर लगने के बाद गाद की समस्या काफी हद तक हल हो जाएगी।

सोलन मंडल में सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की कुल 372 स्कीमें हैं। इनमें से 317 स्कीमें पेयजल और 55 स्कीमें सिंचाई की हैं। इनसे लोगों को पेयजल और सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस प्रपोजल को स्वीकृति मिलने के बाद शहर के लोगों को पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा।

सोलन अस्पताल में अब अलग-अलग दवा ले पाएंगे महिला, पुरुष और बुजुर्ग

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सोलन

क्षेत्रीय अस्पताल में मरीजों को दवा लेने के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अस्पताल में दवा काउंटर पर बने सिंगल विंडो सिस्टम को खत्म कर ट्रिपल विंडो सिस्टम कर दिया गया है। अस्पताल प्रशासन ने सिंगल विंडो की जगह तीन विंडो तैयार कर दी हैं। इससे मरीजों को दवाई लेने में आसानी होगी, वहीं समय की बचत भी होगी। अब अस्पताल में दवा काउंटर पर महिला, पुरुष और बुजुर्गों के लिए अलग से विंडो बना दी गई हैं। इससे पहले अस्पताल में दवाई काउंटर पर सिंगल विंडो सिस्टम होने से अकसर मरीजों को दवाई को लेने के लिए घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ रहा था। इससे महिलाओं और बुजुर्गों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था।

व्यावसायिक माल की ढुलाई के दौरान कोई बाधा डाली तो होगी कानूनी कार्यवाही

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सोलन

औद्योगिक क्षेत्र परवाणू में व्यावसायिक वाहनों को किराये पर लेने संबंधित आदेश पारित किए गए हैं। जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त सोलन विनोद कुमार की ओर से पारित इन आदेशों के मुताबिक परवाणू में औद्योगिक विभाग, औद्योगिक इकाइयों, व्यावसायिक इकाइयों, बिजनेस इकाइयों और अन्य को राज्य में और राज्य के बाहर से ट्रक, लॉरी, पिकअप किराये पर लेने की छूट होगी। व्यावसायिक माल की ढुलाई के दौरान यदि कोई भी संगठन, यूनियन, सोसायटी या कोई अन्य सुचारु यातायात को बाधित करता पाया गया तो, दोषी के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति, संगठन, यूनियन और सोसायटी किसी भी ट्रक, लॉरी और पिकअप मालिक, ऑपरेटर या ड्राइवर से किसी भी प्रकार की अनाधिकृत कर वसूली या शुल्क नहीं करेगा। जिला दंडाधिकारी ने कहा कि यदि किसी भी संगठन की ओर से इस आदेश की उल्लंघना की गई तो उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

नघेता स्कूल की दो छात्राएं खेलेंगी राष्ट्रीय हॉकी स्पर्धा

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सिरमौर

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नघेता की दो छात्राओं का चयन राष्ट्रीय हॉकी के लिए हुआ है। उनके चयन से स्कूल और क्षेत्र में खुशी का माहौल है। नघेता विद्यालय के डीपीई मनीष टंडन ने बताया कि अंडर-19 वर्ग की राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता पंजाब के लुधियाना में होगी जो सात से 12 अप्रैल तक आयोजित होगी।

डीईपी ने बताया कि स्कूल की दो छात्राओं आशु पुंडीर और आमीषा शर्मा का चयन इससे पहले कांगड़ा जिले में हुई राज्य स्तरीय हहकी स्पर्धा के लिए हुआ था। यहां इन दोनों छात्राओं ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। इसके आधार पर ही अब उनका चयन राष्ट्रीय स्पर्धा के लिए हुआ है।

कृषि विभाग में कृषि प्रसार अधिकारी के 36 पद खाली, किसानों को झेलनी पड़ रही है परेशानी

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सोलन

कृषि विभाग सोलन में कृषि प्रसार अधिकारियों के पद खाली होने से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इससे न केवल किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है बल्कि उन्हें विभाग की ओर से मिलने वाले बीज, उपकरण, कीटनाशक सहित अन्य विभागीय जानकारी जुटाने में आए दिन समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है।

कृषि विभाग के अनुसार सोलन के विभिन्न क्षेत्रों में कृषि प्रसार अधिकारियों के 36 पद खाली हैं। पदों के खाली होने से इसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। पद खाली होने से कई जगह कार्यालयों में ताले लटके हैं। इसके चलते किसानों को कृषि संबंधी सामान लेने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ रहा है। इससे किसानों को मानसिक एवं आर्थिक परेशानी भी झेलनी पड़ रही है। गौरतलब है कि सोलन में अधिकतर किसानों की रोजी-रोटी का सहारा कृषि है। काफी लंबे अरसे से खाली पदों को भरने के लिए कोई भी पहल नहीं की जा रही है। किसानों को अधिक पैसा और सफर तय कर दूसरे प्रसार कार्यालयों व सोलन कृषि विभाग ही आना पड़ रहा है।

वोटर आईडी नहीं तो अन्य दस्तावेजों से होगा मतदान

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सिरमौर

मतदान के समय मतदाता 11 तरह के वैकल्पिक दस्तावेजों में से एक दिखाकर अपना वोट डाल सकता है। वैकल्पिक दस्तावेजों की जानकारी के पोस्टर जिले के मतदान केंद्रों, सरकारी और निजी कार्यालयों, स्कूलों, महाविद्यालयों, अस्पतालों, बैंकों, डाकघर, खंड और राजस्व उपमंडलों के कार्यालयों के सूचना पट्ट पर भी लोगों की जानकारी के लिए चस्पा किए जाएंगे, जिससे कोई भी मतदाता वोटर आईडी के अभाव में मतदान से वंचित न रहे। लोकसभा चुनाव के सफल आयोजन को लेकर उपायुक्त कार्यालय के बचत भवन में आयोजित बैठक में नायब तहसीलदार निर्वाचन विजय कुमार शर्मा ने सेक्टर अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया संबंधी विस्तृत जानकारी दी।

नालागढ़ अस्पताल में स्टाफ का टोटा

द रीव टाइम्स ब्यूरो, षिमला

नालागढ़ उपमंडल के सबसे बड़े 100 बेडिड नालागढ़ अस्पताल में खासतौर पर अल्ट्रासाउंड करवाने और अपनी आंखों की जांच करवाने वाले लोगों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। अस्पताल में दो सालों से रेडियोलॉजिस्ट का पद खाली चल रहा है, जबकि एक वर्ष से नेत्र रोग विशेषज्ञ का पद भी यहां रिक्त चला हुआ है। ऐसे में आम लोगों सहित गर्भवती महिलाओं को अल्ट्रासाउंड करवाने, जबकि लोगों को अपनी आंखों की जांच करवाने के लिए बाहर का रुख करना पड़ रहा है। हालांकि अस्पताल प्रशासन की ओर से गर्भवती महिलाओं के अल्ट्रासाउंड बेशक बाहर करवाए जा रहे हैं, लेकिन इसका खर्च अस्पताल प्रशासन की ओर से दिया जा रहा है। जानकारी के अनुसार नालागढ़ अस्पताल में कई विशेषज्ञ चिकित्सकों के महत्त्वपूर्ण पद खाली चल रहे है, जिसमें से बाल रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ व रेडियोलॉजिस्ट का पद खाली चल रहा है।

फीस, फंड की जानकारी न देने वाले स्कूलों की एनओसी होगी रद्द

द रीव टाइम्स ब्यूरो, ऊना

निजी स्कूलों की मनमानी और हाई कोर्ट के निर्देश न मानने पर शिक्षा विभाग ने नाराजगी जताई है। इसके लिए अप्रैल के पहले सप्ताह तक का समय दिया गया था। इस अवधि में जानकारी न देने वाले स्कूलों की एनओसी रद की जाएगी।

हाई कोर्ट ने दो साल पहले निजी स्कूलों को फीस और फंड में पारदर्शिता लाने के लिए निर्देश जारी किए थे। इसमें स्कूल प्रबंधनों को विद्यार्थियों से हर वर्ष, हर माह और हर दिन ली जाने वाली नामों से फीस और फंडों की रिपोर्ट को वेबसाइट और डिस्पले बोर्ड में दर्शानी थी। साथ ही जिन सुविधाओं के नाम पर स्कूल प्रबंधन फीस और फंड ले रहा है, वह उनको विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध करवा रहा है या नहीं।

पांवटा को नहीं मिली हेलिकाप्टर सुविधा

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सिरमौर

विश्व भर में प्रसिद्ध गुरु गोबिंद सिंह जी की पावन नगरी पांवटा साहिब को हेलि सेवा की सुविधा नहीं मिल पाई। नगर के बुद्धिजीवी सरकार से मांग करते रहे, लेकिन पांवटा नगर को इस सेवा में दो वर्ष बाद भी शुमार नहीं किया गया, जिससे पांवटा के पर्यटन को धक्का लगा है। लोगों का कहना है कि अगर यह सेवा पांवटा साहिब में भी शुरू होती तो इससे जहां सरकार की आय बढ़ती, वहीं लोकसभा चुनाव में भी केंद्र की योजना से भाजपा लाभ ले सकती थी, और राज्य के लिए राजस्व एकत्रित होता। लेकिन यह सेवा शुरू नहीं हुई जिस कारण जनता हताश है। जानकारी के मुताबिक केंद्र द्वारा दो वर्ष पूर्व शुरू की गई इस योजना से पांवटा साहिब नगर को भी जोड़ने की मांग की जा रही थी।

औद्योगिक शिकायतों के निपटारे की प्रक्रियाओं का हो सरलीकरण

द रीव टाइम्स ब्यूरो, सिरमौर

औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब के फार्मास्यूटिकल जगत से जुड़े संगठन हिमाचल ड्रग्स मेनुफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने हिमाचल भवन चंडीगढ़ में प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री विपिन परमार के सामने अपनी समस्याएं रखीं। प्रतिनिधिमंडल में हिमाचल ड्रग्स मेनुफैक्चरिंग एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सीएस पुष्करणा, महासचिव संजय आहूजा, केशव सैनी, मनोज गर्ग व संजय सिंगला ने स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के दौरान नए उद्यमियों को पेश आने वाली समस्याओं जैसे उत्पाद सत्यापन, पैकिंग मेटेरियल रूल्स, प्रोसेक्यूशन पहलिसी में बदलाव और दवा निर्माण से संबंधित अन्य समस्याओं पर बातचीत की। उद्यमियों ने प्रदेश सरकार को एक ज्ञापन भी भेजा, जिसमें औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने के लिए उद्यमियों व औद्योगिक शिकायतों के निपटारे की प्रक्रियाओं का सरलीकरण करने, मूल्यवर्धित कर, केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम के लंबित कार्यों, माल व सेवाकर में कर संबंधी सुधारों आदि कार्यों को कम समय में करने की मांग की है।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

चुनाव बहिष्कार की चेतावनी से जागा जिला प्रशासन

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगड़ा

सरकार की अनदेखी से खफा ग्रामीण अब चुनावों का ही बहिष्कार करने लगे हैं। पिछले कुछ समय से हिमाचल के विभिन्न क्षेत्रों से लोगों की ओर से सरकार को चेताने के लिए चुनाव बहिष्कार करने के समाचार मिल रहे हैं।

लोकसभा चुनावों के बहिष्कार की चेतावनी देने के बाद सुर्खियों में आए धंगड़ गांव में लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए सरकारी अधिकारियों ने खुद धंगड़ जाकर लोगों की समस्याओं को सुना। लोगों ने कहा कि १९७० से सड़क निकाली गई है, तब से आज दिन तक इसे पक्का नहीं किया गया। इसलिए अब एकजुट होकर ग्रामीण इसी मांग पर अड़े हैं कि सड़क बनाओ और वोट ले जाओ।

इस पर एसडीएम देहरा ने इस मामले में ग्रामीणों की मांग को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया और कहा कि संबंधित विभाग से इस बारे में बात की जाएगी।

इस बारे में उपमंडल अधिकारी देहरा (नागरिक) का कहना था कि वह खुद धंगड़वासियों की समस्या को सुनने गए थे, क्योंकि लोगों ने चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी थी। लोगों से उन्होंने कहा कि वह खुद लोक निर्माण विभाग देहरा के अधिकारियों से बात कर समस्या का हल निकाला जाएगा।

सरकार ने भाखड़ा विस्थापितों की समस्याओं को उलझाया- समिति

द रीव टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर

सर्वदलीय भाखड़ा विस्थापित समिति ने इस बात पर रोष व्यक्त किया है कि सरकार विस्थापितों के मामले पर गंभीरता से विचार नहीं कर रही है।

समिति सदस्यों ने कहा कि वर्तमान में सरकार ने प्रथम एक वर्ष के कार्यकाल में ही जिले के तीनों भाजपा विधायकों के साथ मिलकर विस्थापितों की समस्याओं पर समिति द्वारा बार-बार चर्चा करने व मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासनों के बावजूद भी उनकी कठिनाइयों व समस्याओं को सुलझाने की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

बैठक में अतिरिक्त डॉक्टर एनके सांख्यान, जेके नड्डा, ओमप्रकाश मेहता, अमृतलाल नड्डा, राम सिंह, अमर सिंह, नंदलाल कौंडल, प्रताप सिंह भल्ला, रशीद अहमद, रशिम महाजन, मनोज कुमार, पुरुषोत्तम शर्मा, ओपी गर्ग, ओंकार कौशल, राज कुमार, उपेंद्र गौतम, अशोक कौंडल, कांशीराम चौधरी, महेंद्र कुमार शर्मा, कृष्णा चौहान, कमलेंद्र कश्यप, सुखराम, राजेंद्र शर्मा, देशराज जम्वाल, कृष्णलाल, एसएल कालिया, लोकनाथ व भूपेंद्र सिंह ने भाग लिया।

सैंकड़ों लोग करेंगे लोस चुनाव में नोटा का प्रयोग

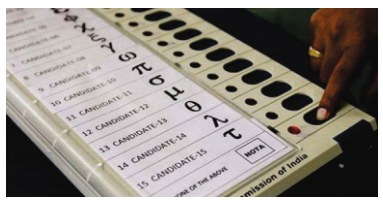

द रीव टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर

एसीसी सीमेंट फैक्ट्री बरमाणा माइनिंग क्षेत्र से सटे कुनणु गांव के करीब 250 लोगों ने लोस चुनाव में नोटा का प्रयोग करने का फैसला लिया है। इसके अलावा ग्रामीण आसपास लगते चार और गांवों के विस्थापितों और प्रभावितों को भी नोटा का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसका फैसला बीते दिनों आयोजित बैठक में ग्रामीणों ने लिया।

बैठक में प्रभावित और विस्थापितों का कहना है कि माइनिंग के कारण कुनणु, धौनकौठी, बलोह, बरयाही में भी लोगों के घरों में ब्लास्टिंग से दरारें आ चुकी हैं लेकिन इसके बाद भी लोगों की समस्या का समाधान कोई नहीं कर पाया। हालांकि एसडीएम से लेकर उपायुक्त तक सब क्षेत्र का दौरान कर चुके हैं। लोगों का कहना है कि ग्रामीणों की मांगों की अनदेखी के बाद कुनणु गांव के लोगों ने बैठक कर यह फैसला लिया है। वहीं लोग धौनकौठी, बलोह, बरयाही के लोगों को भी नोटा का प्रयोग करने के लिए प्रेरित करने को वीरवार से अभियान चलाएंगे। वहीं लोगों ने साफ किया कि कुनणु में किसी भी नेता की एंट्री नहीं होने दी जाएगी। लोगों ने बताया कि एसीसी की भारी ब्लास्टिंग से उनके घर में दरारें आ चुकी हैं। ब्लास्टिंग से होने वाले प्रदूषण से न जाने लोग कितनी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। बैठक में बीडीसी भुवनेश गौतम, विस्थापित समिति के उपाध्यक्ष भारत भूषण गौतम, वार्ड सदस्य सुनील गौतम, शिव कुमार, अंकुल गौतम, रमेश कुमार, रामदास शास्त्री, अतुल गौतम, नरोत्तम दत्त शास्त्री, श्याम लाल गौतम, आशीष गौतम, विवेक गौतम, कुलभूषण गौतम, अनीश गौतम, स्वतंत्र गौतम, पुरुषोत्तम दत्त, राकेश कुमार, पुष्पा देवी, जीत राम, पंकज कुमार, सावित्री देवी, विमला देवी, मीना कुमारी, अर्चना देवी, कांता देवी, जयदेई, श्यामली, शशि कांत, रीता देवी, विशाल कुमार, काली दास, पूजा देवी और कला देवी सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

फ्रॉड के मामलों से निपटने को तैयार होगी विशेष टीम

द रीव टाइम्स ब्यूरो, हमीरपुर

फ्रॉड के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए पुलिस विशेष दल तैनात करेगी। जिला में फ्रॉड के मामलों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं फ्रॉड फाइंनास कंपनियों पर भी नजर रखी जाएगी। सूचना मिलने पर त्वरित कार्रवाई होगी। यह निर्णय मासिक क्राइम मीटिंग में लिया गया। हमीरपुर पुलिस की मासिक संयुक्त सलाहकार समिति एवं अपराध समीक्षा बैठक पुलिस लाइन हमीरपुर में अर्जित सेन ठाकुर, पुलिस अधीक्षक जिला हमीरपुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई ।जिसमें लगभग 40 पुलिस कर्मचारियों ने भाग लिया। इस बैठक में विजय सकलानी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला हमीरपुरए हितेश लखनपाल उपपुलिस अधीक्षक जिला हमीरपुर एवं जसबीर सिंह उपपुलिस अधिकारी बड़सर जिला हमीरपुर भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर अर्जित सेन ठाकुर, पुलिस अधीक्षक जिला हमीरपुर ने सभी थाना प्रबंधक अधिकारियों एवं चौकी प्रभारियों को आगामी लोकसभा चुनाव से संबंधित आवश्यक दिशा-निर्देश दिए तथा ये भी निर्देश जारी किए कि इस जिला में तैनात समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों का पोस्टल बैलेट पेपर बनाना सुनिश्चित करें ताकि आगामी लोकसभा चुनाव में इस जिला के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों का शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित किया जा सके।

मैक्लोडगंज में बड़े वाहनों की आवाजाही पर रहेगा नियंत्रण
पर्यटन सीजन के चलते जिला और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगड़ा

अप्रैल में धर्मशाला और मैक्लोडगंज में भारी तादात में घरेलु और विदेशी पर्यटक पहुंचत हैं। ऐसे में पर्यटन सीजन को देखते हुए कांगड़ा जिला प्रशासन सहित पुलिस प्रशासन भी प्लान बनाने में जुट गए हैं। पर्यटन सीजन के दौरान क्षेत्र की सड़कों पर जाम न लगे और पर्यटकों को परेशानी का सामना न करना पड़े, इसके लिए पुलिस विभाग योजना तैयार कर रहा है। पर्यटन सीजन के दौरान सुरक्षा-व्यवस्था के लिहाज से मैक्लोडगंज में अतिरिक्त पुलिस जवान तैनात किए जाएंगे, जिसके लिए पुलिस प्रशासन आवेदन करेगा। इसके अलावा मैक्लोडगंज की सर्पीली सड़कों पर बड़े वाहनों के कारण कोई दिक्कत पेश न आए, इसके लिए बड़े वाहनों की मैक्लोडगंज में आवाजाही नियंत्रित की जाएगी।

पर्यटकों की सुरक्षा-व्यवस्था और अन्य सुचारु यातायात के लिए अतिरिक्त पुलिस जवानों की तैनाती की जाएगी।

बगड़ोली के ग्रामीण करेंगे लोकसभा चुनाव का बहिष्कार

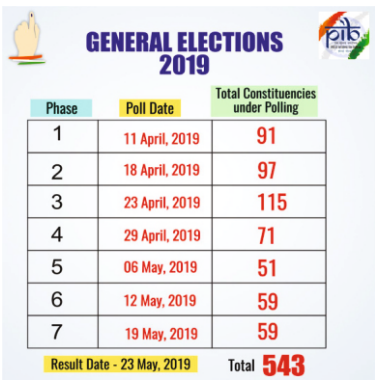

GENERAL ELECTIONS 2019

Phase	Poll Date	Total Constituencies under Polling
1	11 April, 2019	91
2	18 April, 2019	97
3	23 April, 2019	115
4	29 April, 2019	71
5	06 May, 2019	51
6	12 May, 2019	59
7	19 May, 2019	59
Result Date - 23 May, 2019		Total 543

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कांगड़ा

फतेहपुर विकास खंड के बगड़ोली गांव के लोगों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। ग्रामीणों ने रोष जताया कि करीब नौ महीने पूर्व बरसात में भूस्खलन से क्षतिग्रस्त संपर्क मार्ग बंद हो गया था। लेकिन इसे अभी तक दुरुस्त नहीं किया गया है।

बगड़ोली के पूर्व कैप्टन रमेश चंद धीमान, पूर्व प्रधान फलातू राम, पूर्व उपप्रधान सोमदत्त, ठाकुर दास, गोरखी राम, लाठी राम, पूर्ण चंद, ज्ञान चंद, कर्म चंद, रवि कुमार, देसराज ने कहा कि अगस्त 2018 से बंद पड़े रास्ते के कारण सारा सामान उठाकर ले जाना पड़ रहा है। वहीं, बच्चों, बुजुर्गों को बड़ी परेशानियां का सामना करना पड़ रहा हैं। ग्रामीणों ने ठेहड़ पंचायत के प्रधान से भी गुहार लगाई, लेकिन आश्वासन के सिवा लोगों को कुछ नहीं मिला। इसके चलते लोग लोकसभा चुनाव का विरोध कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि क्षतिग्रस्त संपर्क सड़क की मरम्मत के लिए तीन लाख रुपये मंजूर हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका कार्य शुरू नहीं हो सका है।

गलत तरीके से किया गया राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त

द रीव टाइम्स ब्यूरो, बिलासपुर

कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन निर्माण के दौरान राजस्व रिकॉर्ड में सभी नियमों को ताक पर रख कर दुरुस्ती की गई है। जबकि राजस्व रिकॉर्ड में किसी भी प्रकार की दुरुस्ती का अधिकार भूमि अधिग्रहण की विशेष इकाई के तहसीलदार को नहीं था। यह अधिकार केवल भू राजस्व अधिनियम 1954 की धारा-16 में दर्ज राजस्व अधिकारियों को ही दुरुस्ती करने की शक्तियां प्रदान हैं। इसके लिए पहले अधिग्रहण की गई भूमि को पहले डी-नोटिफाइड किया जाएगा जिसके बाद रिकहर्ड दुरुस्ती हो सकता है लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस पूरे मामले का खुलासा जन सूचना अधिकारी एवं जिला राजस्व अधिकारी देवी राम द्वारा राज्य सूचना आयुक्त हिमाचल प्रदेश को भेजी गई जानकारी से हुआ है। उल्लेखनीय है कि कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन निर्माण के दौरान कई बार राजस्व रिकॉर्ड को दुरुस्त किया गया। सूत्रों के मुताबिक 21-12-2016 एजेंडा फॉर मीटिंग में भी तत्कालीन उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर ने इसकी पुष्टि की थी। उन्होंने आदेश भी दिए थे कि पूरे के पूरे रिकॉर्ड को नियम अनुसार दुरुस्त किया जाए क्योंकि रिकॉर्ड में कई अनियमितताएं हैं लेकिन उसके बाद भी एनएचएआई के तहसीलदार ने इस संबंध में नियम अनुसार कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि अपने स्तर पर कई स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त कर डाला। नियम अनुसार रिकॉर्ड दुरुस्त न होने के कारण सालों से विस्थापितों और प्रभावितों को यह पता नहीं लग पा रहा है कि उनकी जमीन कहां शेष बची है और किस जमीन का अधिग्रहण हुआ है। इस कारण लोग लगातार सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। विस्थापितों में सीता राम, महेंद्र सिंह, रणजीत सिंह, बाबू राम, बलदेव, वनबारी लाल, बृज लाल, देवेंद्र कुमार, देस राम, देव राज, देवी राम और फोरलेन विस्थापित एवं प्रभावित समिति के महा सचिव मदन लाल शर्मा ने बताया कि रिकॉर्ड नियम अनुसार दुरुस्त न होने से लोगों को अपनी जमीन तक की सही जानकारी नहीं मिल पा रही है। जनसूचना अधिकारी एवं जिला राजस्व अधिकारी देवी राम ने बताया कि राज्य सूचना आयुक्त हिमाचल प्रदेश को पूरी जानकारी भेज दी गई है।

ब्रांडेड दवाएं लिखने पर नपेंगे डाक्टर

द रीव टाइम्स ब्यूरो, हमीरपुर

ब्रांडेड दवाइयां लिखने वाले डाक्टरों पर अब खुफिया जांच तंत्र नजर रख रहा है। इंटेलिजेंस एजेंसी को ऐसे डाक्टरों का पता लगाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है जो जेनेरिक की बजाय ब्रांडेड दवाइयां लिखकर गरीब मरीजों पर आर्थिक बोझ डाल रहे हैं। अपने कमीशन के चक्कर में कई डाक्टर जेनेरिक दवाइयां लिखने की बजाय ब्रांडेड मेडिसिन लिख रहे हैं, जो जन औषधि केंद्र की बजाय बाहरी मेडिकल स्टोर पर मिलती हैं। हालांकि नियमों के तहत चिकित्सकों को अस्पताल के जन औषधि केंद्र में उपलब्ध दवाइयां लिखने के निर्देश हैं। डाक्टरों को जन औषधि केंद्र में उपलब्ध दवाइयों के नाम सहित साल्ट भी लिखना अनिवार्य है। नियमों की अवहेलना करने वाले चिकित्सकों पर खुफिया एंजेसियां दिन-रात नजर गड़ाए हुए है। मेडिकल कालेजों में तैनात कई चिकित्सकों पर ब्रांडेड दवाइयां लिखने का शक है। ऐसे डाक्टरों के खिलाफ शिकायत के बाद मामले की जांच का जिम्मा इंटेलिजेंस को सौंपा गया है।

जांच एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। अब इसे सरकार के समक्ष प्रेषित किया जाएगा। वहीं कुछ अन्य मेडिकल कालेजों से भी चिकित्सकों द्वारा ब्रांडेड दवाइयां लिखने बारे शिकायतें मिली थीं। इसके बाद सरकार ने खुफिया एजेंसी को जांच के लिए लगाया है। जांच रिपोर्ट पुख्ता होने के बाद इन चिकित्सकों पर जांच की गाज गिरेगी। नियम फहलो न करने पर इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई होगी।

मेडिकल कालेज व सरकारी अस्पतालों में स्थापित किए गए जन औषधि केंद्रों में जेनेरिक दवाइयां सस्ती दरों पर मिलती हैं। बाहरी दुकानों से कई गुना सस्ती दरों पर यहां बेहतर क्वालिटी की मेडिसिन उपलब्ध रहती हैं। डाक्टरों को भी सरकार ने जेनेरिक दवाइयां लिखने के ही निर्देश दिए हैं। निर्देशों में कहा गया है कि चिकित्सक सिर्फ जन औषधि केंद्र में उपलब्ध होने वाली दवाइयां ही लिखेंगे। पर्ची पर दवाई के नाम सहित इसका साल्ट भी दर्शाना होगा। बावजूद इसके कुछ चिकित्सक मोटी कमाई के चक्कर में नियम दरकिनार कर रहे हैं।

पर्यटन निगम दे रहा है 50 प्रतिशत की छूट

द रीव टाइम्स ब्यूरो

पर्यटन निगम अपने होटलों में सीजन के दौरान पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 50 प्रतिशत की छूट दे रहा है। पर्यटन निगम के एजीएम कांगड़ा अश्वनी सोनी की मानें तो पर्यटन निगम के प्रत्येक होटल में सैलानियों के लिए वाई-फाई की सुविधा है। इसके अलावा अन्य सुविधाएं भी पर्यटन निगम के होटलों में ठहरने वाले पर्यटकों को मिलेंगी।

दस साल में 50 किलोमीटर की दूरी तय नहीं कर पाई रेल

द रीव टाइम्स ब्यूरो, हमीरपुर

करीब दस साल पहले यानी वर्ष 2009 में जब लोकसभा चुनाव आए, तो अचानक हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के गलियारों में चर्चा निकली कि ऊना से हमीरपुर तक रेल पहुंचाई जाएगी। लेकिन यह चर्चा ही रही। उसके बाद वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव आए तो एक बार फिर से हमीरपुर के लोगों को उम्मीद जागी। वादे भी किए गए कि अगले पांच सालों में ऊना से हमीरपुर तक न केवल पटरी बिछवा देंगे, बल्कि रेल भी हमीरपुर में पहुंचेगी।

यही नहीं, वर्ष 2018 में दीपावली के अवसर पर यह कहा गया कि रेलवे ट्रैक का शिलान्यास होने वाला है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। केंद्रीय रेल राज्य मंत्री राजेन गोहने ने लोकसभा में बताया कि हिमाचल में रेल नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए चार परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

कुल्लू से होगा पोलिथीन का सफाया

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

पोलिथीन-प्लास्टिक के कचरे को खत्म करने के लिए प्रदेश भर में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कुल्लू जिला में भी 12 से 20 अप्रैल तक पोलिथीन हटाओ, पर्यावरण बचाओ अभियान चलाया जा रहा है।

इस अभियान को सफल बनाने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार की जा रही है। उपायुक्त ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करके इस अभियान की तैयारियों की समीक्षा की। उपायुक्त ने कहा कि अभियान के दौरान जिला के घनी आबादी वाले क्षेत्रों विशेषकर चारों नगर निकाय क्षेत्रों कुल्लू, मनाली, भुंतर, बंजार और इनके साथ सटी ग्राम पंचायतों से पोलिथीन-प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा किया जाएगा और इसकी छंटाई की जाएगी। कचरे की छंटनी के बाद यह लोक निर्माण विभाग को दिया जाएगा तथा इसका प्रयोग सड़कों की टायरिंग के लिए किया जाएगा। उपायुक्त यूनुस ने बताया कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी तथा उन्हें ठोस कचरे के सही प्रबंधन के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने सभी कुल्लूवासियों से अपने घरों में ही कूड़े की छंटाई करके पोलिथीन-प्लास्टिक को अलग करने की अपील भी की।

अनावश्यक फीस वसूली तो स्कूल की मान्यता रद्द

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

जिला कुल्लू में चल रहे निजी स्कूलों की मनमानी को लेकर मिल रही शिकायतों के चलते उपायुक्त कुल्लू ने निजी स्कूलों के साथ एक बैठक की।

इसकी अध्यक्षता उपायुक्त यूनुस ने की। उपायुक्त ने निजी स्कूलों को फीस के नाम पर वसूली जा रही राशि को लेकर फटकार लगाई। इसके साथ कई दिशा-निर्देश भी दिए। उपायुक्त यूनुस ने कहा कि फीस व अन्य फंड के नाम पर किसी न किसी रूप में की जा रही भारी भरकम वसूली को तुरंत प्रभाव से बंद कर दें, अन्यथा उनके संस्थानों की मान्यता भी रद्द की जा सकती है।

फीस के अलावा अन्य माध्यमों से भी विद्यार्थियों के अभिभावकों से वसूली को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उपायुक्त यूनुस ने कहा कि निजी शिक्षण संस्थान सोसायटी पंजीकरण अधिनियम या इंडियन ट्रस्ट एक्ट के तहत पंजीकृत किए जाते हैं और ये भारी भरकम व्यावसायिक मुनाफा हासिल करने के साधन नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जिन संस्थानों में फीस व अन्य फंड के नाम पर अतिरिक्त वसूली की जा रही है, ऐसे संस्थानों का स्पेशल ऑडिट करवाया जाएगा तथा अनियमितताएं पाए जाने पर इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फीस और अनावश्यक फंड में कटौती के लिए निजी स्कूल स्वयं पहल करें। बैठक में उपस्थित कुछ स्कूल संचालकों ने 10 प्रतिशत कटौती का आश्वासन भी दिया।

स्कूलों को 15 दिन की मोहलत

शिक्षण संस्थानों में बच्चों की सुविधा, सुरक्षा, परिवहन व्यवस्था और अन्य आवश्यक प्रबंधों में कोताही नहीं होनी चाहिए तथा सभी नियमों का पूरी तरह पालन सुनिश्चित किया जाए। अगर किसी स्कूल में ये आवश्यक सुविधाएं नहीं हैं तो वे 15 दिन के भीतर इन कमियों को पूरा करें। इसे लेकर एक निर्धारित समय सीमा में पूरा करने का लिखित आश्वासन दें। अन्यथा उनकी मान्यता रद्द की जा सकती है।

खस्ताहाल मिनी सचिवालय में पानी का रिसाव

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

जिला मुख्यालय ढालपुर स्थित मिनी सचिवालय कभी भी खंडहर में तबदील हो सकता है। जिला प्रशासन के समाने मिनी सचिवालय की छत से लगातार पानी का रिसाव हो रहा है। हालांकि उपायुक्त कुल्लू ने पिछले साल इसका निरीक्षण कर जल्द दुरुस्त करने का आश्वासन दिया था। लेकिन कोई पहल नहीं हो सकी। ऐसे में लोकसभा चुनाव में यह मुद्दा उठेगा। इस पर जवाब भी मांगा जाएगा।

मिनी सचिवालय की दीवार ढहने से यहां न केवल सरकारी संपत्ति को नुकसान होगा, बल्कि बड़े स्तर पर जानमाल का नुकसान हो सकता है। जिला मुख्यालय ढालपुर स्थित उपायुक्त कार्यालय के साथ चार मंजिला मिनी सचिवालय की एक दीवार के साथ इसकी सीढ़ियों में लगातार पानी का रिसाव हो रहा है। इससे भवन के ढहने का डर है। हालांकि 2018 में उपायुक्त कुल्लू यूनुस ने मिनी सचिवालय के सरकारी दफ्तरों का औचक निरीक्षण किया था और इस दौरान कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने इस समस्या से उन्हें अवगत करवाया था।

इसके बाद उपायुक्त ने जल्द ही इस समस्या को दूर करने का आश्वासन दिया था। शहरवासी तेज राम, राजेंद्र सिंह, विशाल ठाकुर, रूपेश शर्मा तथा शेर सिंह ने कहा कि लोक सभा चुनावों में इस मुद्दे को राजनीतिक दलों के समक्ष उठाया जाएगा। मिनी सचिवालय की चौथी मंजिल की छत से पिछले दो सालों से लगातार पानी रिसाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि मिनी सचिवालय में एक दर्जन से अधिक विभागों के दफ्तर हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन को इस पर ध्यान देने की जरूरत है।

थल्ली सियुका के बच्चे स्मार्ट क्लास रुम में करेंगे पढ़ाई

द रीव टाइम्स ब्यूरो, चंबा

राजकीय प्राथमिक पाठशाला थल्ली सियुका के विद्यार्थियों को स्मार्ट क्लास रूम की सुविधा मिलेगी। इसका शुभारंभ हाल ही में किया गया। स्कूल प्रबंधन ने नौनिहालों की पढ़ाई के लिए एक एलईडी कंप्यूटर भी खरीदा है। ऐसे में अब बच्चे एक नए नवाचार का उपयोग करेंगे। यह कंप्यूटर वायरलेस सिस्टम से लैस है।

अब बच्चे पहली कक्षा से ही कंप्यूटर का ज्ञान हासिल करने के साथ-साथ कंप्यूटर का उपयोग और अन्य पाठ्य क्रियाओं में करेंगे। बच्चों को दृष्य श्रव्य साधन उपलब्ध होगा।

नौ साल बाद भी नहीं पहुंचा सूखाग्रस्त पंचायत को पानी

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

वर्ष 1993 में सूखाग्रस्त घोषित हो चुकी ग्राम पंचायत पलाहच में ग्रामीणों को पेयजल समस्या से जूझना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत के गांवों को पानी की समस्या से निजात दिलवाने के लिए न तो पानी की स्कीम पूरी हो पाई और न ही पेयजल के भंडारण के लिए स्टोर टैंक का निर्माण हुआ।

पेयजल आपूर्ति को लेकर बन रही इस योजना पर जन प्रतिनिधियों की अनदेखी के बाद ग्रामीणों में काफी गुस्सा है। पिछले चुनावों में इस मुद्दे को जनता ने सभी राजनीतिक दलों के सामने रखा था। लेकिन किसी ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। अब फिर से ग्रामीण लोकसभा चुनावों में उठाने जा रहे हैं। ग्रामीणों ने दो टूक कहा है कि जो पार्टी उनकी समस्या को दूर करने का आश्वासन देगी वोट उसी को दिया जाएगा। पिछले माह मंगलौर पंचायत में हुए जनमंच के दौरान भी पलाहच पंचायत के ग्रामीणों ने इस समस्या को रखा था। पलाहन पंचायत की प्रधान फुला देवी नेगी, पदम सिंह, वेद प्रकाश, नागेंद्र नेगी, तेजा सिंह, मैना देवी, रीना देवी, निधि सिंह, खेम चंद, बुद्धि सिंह, लाल सिंह, गुमत राम, केसरी लाल, दुर्गा सिंह तथा ज्ञान चंद तथा अन्य लोगों का कहना है कि वर्ष 2010 में कलवारी पलाहच पेयजल योजना को मंजूरी मिली थी और निर्माण कार्य भी शुरू किया गया था। लेकिन नौ साल बीतने पर भी यह योजना पूरी नहीं हो सकी। इससे सूखाग्रस्त पंचायत को पानी की एक बूंद भी नहीं मिली है।

गर्मियों में और भी बढ़ जाती है समस्या

1993 में सूखा ग्रस्त घोषित पंचायत में गर्मी के दिनों पेयजल की भारी किल्लत हो जाती है। ऐसे में यहां प्रशासन की ओर से टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई दी जाती है। लेकिन वह खपत के मुकाबले नाकाफी है और ग्रामीणों को नाले ओर बावड़ियों से पानी ढोना पड़ता है।

कुल्लू में ग्लाइडर क्रैश , पायलट व केरल के सैलानी की मौत

द रीव टाइम्स ब्यूरो, कुल्लू

कुल्लू के डोभी के पास बीते दिनों एक ग्लाइडर क्रैश हो गया। हादसे में सैलानी समेत पायलट की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 7 अप्रैल की सुबह फलाइन पैराग्लाइडिंग प्वाइंट से ग्लाइडर ने उड़ान भरी थी। इसमें पायलट स्थानीय निवासी नरेश कुमार (25) था, जबकि पैराग्लाइडिंग का लुत्फ केरल का एक युवा उठा रहा था। बताया जा रहा है कि जब डोभी के पास ग्लाइडर ने लैंडिंग करनी थी, तो उससे ठीक पहले ग्लाइडर का संतुलन बिगड़ा और पायलट और पर्यटक अनार के बागीचे में जा गिरे। क्षेत्र के लोगों ने उन्हें गिरते हुए देखा और तुरंत मौके पर पहुंचे। दोनों को गंभीर चोटें आई थीं। इसके बाद दोनों को क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू लाया गया, जहां डाक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों युवकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। दुर्घटना की सूचना मिलते ही पायलट के परिजनों के साथ-साथ केरल के पर्यटक भी क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू पहुंचे। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के बाद दोनों शव परिजनों के हवाले कर दिए हैं। पतलीकूहल थाना प्रभारी दया राम ने मामले की पुष्टि की। हादसे में पायलट और पर्यटक की मौत हो गई है। हादसे में स्थानीय निवासी पायलट नरेश कुमार (25) और केरल के युवा पर्यटक अल्थोबचू (23) की मौत हो गई है। थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।

स्कूली बसों को जीपीएस कैमरे से लैस करें प्रबंधन

रीव टाइम्स ब्यूरो, मंडी

उपमंडल के सभी निजी स्कूलों की बैठक उपमंडलाधिकारी कार्यालय पधर में हुई। बैठक की अध्यक्षता एसडीएम पधर डॉक्टर विशाल शर्मा ने की। उन्होंने सभी स्कूल प्रबंधकों को स्कूल सेफ्टी और बच्चों को सकुशल ढंग से बच्चों को परिवहन सुविधा मुहैया करवाने के बारे में जानकारी दी। एसडीएम पधर ने कहा कि सरकार के आदेशानुसार बसों में पैनिक बटन, सीसीटीवी कैमरे लगाने की व्यवस्था की जाए। कैमरे जीपीएस से जुड़े होने चाहिए। ड्राइवर और कंडक्टर वर्दी में होने चाहिए। उन्होंने आदेश दिए कि चालक-परिचालक की वर्दी में नेम प्लेट होनी चाहिए। स्कूल बसों में फायर उपकरण लगा होना चाहिए। बसों में इस प्रकार की सुविधा मई की प्रथम तारीख तक होनी चाहिए। शर्मा ने कहा कि प्रथम मई के बाद सभी स्कूल बस वाहनों की पासिंग होगी।

डेवरवाला-जवोठ रुट पर उद्घाटन के दिन ही देखी बस

द रीव टाइम्स ब्यूरो

फतेहपुर-चंदैश सड़क मार्ग से डेबरवाला से जवोठ वाया अपर बरोट-वनमघोह संपर्क सड़क का उद्घाटन वर्ष 2007 में किया गया था था और उसी दिन बस भी चलाई गई थी और तब से लेकर आज तक ग्रामीणों की जोरदार मांग के बावजूद न ही इस संपर्क सड़क पर बस चली न ही आज तक इस सड़क को पक्का करना तो दूर मरम्मत करवाने की जहमत किसी ने जरूरी नहीं समझी, जबकि क्षेत्र की तीन पंचायतों के आधा दर्जन गांवों के पांच हजार लोग बस सुविधा से वंचित हैं। जबोठ से वनमघोह के लिए संपर्क सड़क पर बस भी चली, लेकिन एक ही दिन। उसके बाद अनदेखी के चलते सड़क की हालत ऐसी हो गई है कि सड़क खड्ड का रूप धारण कर चुकी है और पिछले कई वर्षों से इस सड़क पर ट्रैक्टर, कार, जीप और दोपहिया वाहन चलाना मुश्किल हो गए हैं और पिछली बरसात के बाद तो सड़क बिलकुल ही बंद हो गई और स्थानीय लोगों के वाहन घरों में जंग खा रहे हैं और अब तो पैदल चलना भी जोखिम भरा है। गोपालपुर के अपर डोल, पौंटा पंचायत के अपर बरोट, बल्ह, मैरा और सुलपुर पंचायत के वन मघोह, अल्वाय, जवोठ के बृजलाल राव, निहाल चंद, संजय कुमार, सुभाष चंद, मलराम, वसंता राम, रोशन लाल, भीम सिंह, कन्हैया लाल, पीरू राम, राम लाल, हरवंश राम, शेर सिंह और जोगिंद्र सिंह आदि ग्रामीणों ने कई बार लोक निर्माण विभाग से ही नहीं स्थानीय विधायक से भी सड़क की मरम्मत व पक्का करने की मांग कर चुके हैं, लेकिन किसी को इस सड़क ख्याल नहीं आया और यह सड़क खड्ड बन चुकी है।

जोगिंद्रनगर में धूमधाम से मना पारंपरिक मेला

द रीव टाइम्स ब्यूरो, मंडी

जोगिंद्रनगर में बीते दिनों पारंपरिक मेले की धूम रही। पांच दिनों तक चले इस राज्य स्तरीय मेले की शुरूआत देवताओं के पधारने से हुई और समूचा माहौल देवमय हो गया है। शहर में ढोल-नगाड़ों की थाप पर देवताओं ने पदार्पण किया। चौहारघाटी के देवाधिदेव हुरंग नारायण व देव पशाकोट सहित देव गहरी व देव सूत्रधार ब्रह्मा आदि देवताओं ने जहां मेला जोगिंद्रनगर में शिरकत की वहीं क्षेत्र के अन्य भागों से भी भारी संख्या में देवी-देवताओं ने मेले में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। क्षेत्र के सभी छोरों से एकत्रित देवी-देवताओं के संगम पर कर्णप्रिय संगीत की ताल पर थिरकते देवी-देवताओं के साथ मानों समूचा जनमानस ही थिरक उठा हो, कुछ ऐसा ही नजारा देखने में लग रहा था। लगभग 72 वर्ष पूर्व 1937 में मंडी रियासत के तत्कालीन नरेश जोगिंद्र सेन द्वारा स्थानीय सनातन धर्म मंदिर में शिवलिंग की स्थापना के साथ शुरू हुआ जोगिंद्रनगर मेला आज भी अपनी परंपरा को कायम रखे हुए है। मेला जोगिंद्रनगर के विधिवत शुभारंभ से पूर्व मुख्यातिथि उपायुक्त मंडी ऋग्वेद ठाकुर ने पुराने मेला मैदान में देवी-देवताओं की पूजा-अर्चना की व तत्पश्चात देवताओं की शोभायात्रा (जलेब) में भाग लिया। शोभायात्रा के मेला मैदान में पहुंचने पर मुख्यातिथि द्वारा मेला का ध्वज फहरा कर मेले की विधिवत शुरुआत की। मेला कमेटी के अध्यक्ष एवं उपमंडल अधिकारी (ना.) अमित मेहरा द्वारा मुख्यातिथि सहित अन्य अतिथियों को शाल, टोपी व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। पांच दिवसीय राज्य स्तरीय मेला जोगिंद्रनगर की पहली सांस्कृतिक संध्या पुलवामा शहीदों को समर्पित करते हुए स्थगित की गई है। पांच दिनों तक चले इस मेले विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई।

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

जलियांवाला बाग नरसंहार:शताब्दी वर्ष

फूलों के बाग में अभी भी खून की खुशबु आती है

एक संकरी गली.....गली के आगे एक बड़ा मैदान जिसमें हज़ारों भारतीय अपनी बात को रखने, दो लोकप्रिय नेताओं और रॉलेट एक्ट के विरोध में एकजुट हो रहे थे । गुरुद्वारा में दर्शन के बाद पंजाब और भारत के अन्य राज्यों के लोग इस जनसभा में एकत्रित हो रहे थे। दिन भी कौन सा....बैसाखी.....इस दिन पंजाब, हरियाणा राज्यों में फसलों का कटान होता है जो अन्नपुर्णा के आशीर्वाद से परिपूर्ण है। इसके अलावा कहा जाता है कि इसी दिन सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गोविन्द सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। किसे पता था कि दुनिया इस दिन को एक जघन्यता और क्रूर नृशंस हत्याकांड के लिए भी याद करेगी। 13 अप्रैल 1919 की तारीख़ कुछ ही देर में रक्तरंजित हो गई जब उस संकरी गली से तत्कालीन ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपनी पुलिस टुकड़ी से घुसा और बाहर जाने के सारे रास्ते बंद हो गए। शांतिप्रिय तरीक़े से जनसभा कर रहे लोग अगले पल की जघन्यता से अनभिज्ञ थे। एक आदेश हुआ....फायर.....और मैदान चीखोपुकार से गूंज उठा। भगदड़ इतनी कि क्या युवा, क्या बुजुर्ग, क्या महिलाऐं..... दनदनाती गोलियों से बचने के लिए बेसुध भागने लगे। पास में ही एक कुंआ जिसमें न जाने कितने असहाय लोगों ने छलांग लगा दी। लोगों ने दीवार फांदकर अपनी जान बचाने की कोशिश की लेकिन सब व्यर्थ.....आज भी उस दीवार पर गोलियों के निशान इस बर्बरता को ब्यान करते हैं । कुछ ही क्षणों में मैदान लाशों से भर गया और एक कलंक को माथे पे लिए वो कुंआ भी जो रोज़ की तरह लोगों की प्यास नहीं बुझा पाया बल्कि उस दिन उसका पानी भी रक्त से लाल था और लाशों से भरा हुआ भी ।

एक रिपोर्ट में 1650 राउंड गोलियां चलाने के बाद डायर इसलिए रुका क्योंकि उसके सिपाहियों के पास गोलियां ख़त्म हो गई थी। इस नृशंस हत्याकांड के बाद भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का रुख बदल गया। मरने वालों का आंकड़ा ब्रितानिया हुकुमत ने जो भी बताया हो....संख्यां हज़ारों में थी। सैंकड़ों लाशों का संमदर लिए गवाह बेजान कुंआ आज भी वहीं मूक हैं । इस घटना को 100 साल हो गए हैं लेकिन ज़ख्म ऐसा कि शायद अभी सदियां लगे इसे भरने में। घटना के बाद शहीद भगत सिंह जब उस बाग में गए तो वहीं से उन्होंने उस रक्त से सनी मिट्टी को मुट्ठी में उठाकर सौगंध ली थी। यही जज़्बा आज भी हर उस हिंदुस्तानी के मन होता है जब वह जलियांवाला बाग में जाता है। वहां की मिट्टी और फूलों के बागों से देशवासियों के रक्त की खूश्बु आती है ।

अभी हाल ही में ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा ने इस जघन्य घटना को उनके इतिहास की बहुत बड़ी भूल कहा था । लेकिन इस पर क्षमा याचना नहीं की। तो क्या ब्रिटेन को इस घटना का अफसोस दस्तावेज़ों की काली अक्षरावली में ही है ? हर बार की तरह ब्रितानिया हुकुमत इसकी निंदा तो करती है लेकिन क्षमायाचना करने से उसे परहेज़ है। इससे पूर्व भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कैमरुन जब भारत आए तो उन्होंने भी निंदा की चुटकियां तो ली लेकिन स्पष्ट क्षमा याचना कभी नहीं की। पंजाब सरकार ने विधानसभा में बाक़ायदा प्रस्ताव पारित कर ब्रिटेन से इस जघन्य अपराध के

लिए स्पष्ट माफी मांगने की बात दोहराई लेकिन क्या इतनी बर्बरता और नृशंसता के लिए ब्रिटेन पर दबाव बनाकर माफी मंगवानी पड़ेगी ? क्या ब्रिटेन नहीं जानता कि उसने क्या किया है ?

आज 100 वर्ष यानि शताब्दी वर्ष के इस स्मरणीय अवसर पर मन व्यथित होने के पीछे बाहरी और आंतरिक दोनों को कारणों का समावेश व्यथित करता है। बाहरी कारण तो ये कि ब्रिटेन गाहे-ब-गाहे इस ज़ख्म पर निंदा करने के बाद क्षमा नहीं मांगने पर ऊंगली करता है और आंतरिक कारण ये कि सरकार इस घटना को इतिहास से एक क्रूरता के साथ जोड़कर सटीक एवं सत्यता के साथ सामने नहीं आती है। आज भी जलियांवाला बाग में कितने शहीद हुए....इसकी सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है। और सरकार ने कितने मृतको को शहीद का दर्ज़ा दिया है, यह भी प्रश्नवाचक चिन्ह के दायरे में आता है। पंजाब सरकार ने चुनिंदा लोगों की पहचान कर उन्हें शहीद के दायरे में लाकर एक कार्ड दे दिया और अन्य शहीदों की उन्हें या तो जानकारी नहीं है या उन्हें इस विषय की गंभीरता नहीं है।

जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए मुख्यतः जिम्मेवार दो लोग जिनमें सबसे बड़े गुनहगार ब्रिगेडियर जनरल रेजीनॉल्ड डायर तो गंभीर बीमारी के कारण मर गया था लेकिन दूसरा दोषी ले० गवर्नर माइकल ओ डायर ब्रिटेन चला गया। वो बेख़बर था कि उसका लगातार एक आदमी पीछा कर रहा है जो इस नृशंसता की आग में जल रहा था। उधम सिंह....वो नाम जो शहीदों में एक विशेष मुक़ाम रखता है । उधम सिंह ने वर्षों तक माइकल का पीछा किया और 21 वर्ष बाद एक सभा में गोली मार कर जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उधम सिंह हमारे लिए ही नहीं अपितु हमारी आने वाली सभी पीढ़ीयों के लिए मिसाल बन गए । यहां दुःख तो तब होता है जब ये ख़बरें सुर्ख़ियां बनती है कि शहीद उधम सिंह की समाधि पर कई दिनों तक सफाई तक नहीं की जाती है । यानि हमारे लिए भाषणों, संसद के गलियारों और जनता के बीच सहानुभूति के लिए शहीदों का सम्मान बनाए रखना है.....अन्यथा वास्तविकता तो कुछ और ही है। नहीं भूलना चाहिए कि हमारी स्वतंत्रता इन्हीं बलिदानियों की रक्तगंगा से तैर कर हमें प्राप्त हुई है। क्या जन्मदिवस या शहीदी दिवस पर ही इनकी समाधि पर स्वच्छता का लेपन करने की औपचारिकता होगी ?

यहां एक बात दीगर है जो पीड़ा देती है । क्या हमारी भावी पीढ़ी इस बलिदान को आत्मसात कर इस परंपरा का निर्वहन करने में सक्षम है ? क्या शहीदों के बलिदान की कीमत इस नई पीढ़ी को देशभक्त बनाने में कोई योगदान देगी ? मुझे याद है जब मैं पहली बार जलियांवाला बाग गया था तो उसी संकरी गली को पार करते हुए रोंगटे खड़े होते हैं और यदि थोड़ी भी देश और शहीदों के बलिदान को महसूस करने की संवेदना हो तो उन गोलियों की दनदनाहट सुनाई देती है। मैदान बेशक़ आज एक बाग में बदल गया है और स्मारक स्थल पर सेल्फी मोड़ की भीड़ रहती है...लेकिन मिट्टी आज भी रक्त लालिमा लिए हुए है और कुंए से मानो बेबसी की चीखें चित्कार कर रही हों कि ... हमें मत भुलाना...हम देश के लिए ही शहीद हुए थे ...। मैंने उस पावन धरती से एक मुट्ठी मिट्टी की लेकर जब शिमला के समीपवर्ती अपने गांव में खेत में फैंकी तो मेरी 4 वर्ष की बेटी ने मुझसे पूछा था कि इस लाल मिट्टी को यहां खेतों में क्यों फैंक रहे हो ? मैने कहा कि यह मिट्टी हमारे शहीदों के खून से रंगी है...इसे खेत में डालने से हमारे खेत से उगने वाली फसलों में देशभक्ति का जज़्बा और राष्ट्रप्रेम की ऊर्जा का संचार हमें कभी इस माटी से पृथक नहीं होने देगा । उस बच्ची का यही प्रश्न ही हम सभी के लिए पहेली है क्योंकि हम बच्चों को रोज़ गार्डन, रॉक गार्डन के बारे में तो घंटों बताते हैं लेकिन जलियांवाला बाग में ले जाने या इसके स्वर्णिम शहीदी इतिहास को इस नई पीढ़ी को बताने में गुरेज़ करते हैं । अगले वर्ष उस बच्ची को जब जलियांवाला बाग में जाने का अवसर मिला तो शहीदी कुंए में झांककर 5 वर्ष की बच्ची की आंखों में आंसू देखकर जो सुकून मिला उसका वर्णन किसी भी शब्दावली और परिभाषा में व्यक्त नहीं हो सकता.....

गुनाह में जो शामिल हैं
केवल है वो गुनहगार नहीं
है गुनहगार वो भी जिसको
'हेम' स्वदेशनिज से प्यार नहीं

हेम राज चौहान
संपादक, द रीव टाइम्स
Chauhan.hemraj09@gmail.com,94184 04334

पीलिया : असावधानी जानलेवा

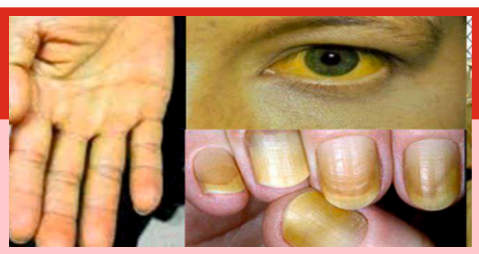

पीलिया एक ऐसी अवस्था को कहते हैं, जब मरीज के त्वचा और आंख का सफेद हिस्सा पीला पड़ने लगता है। खून में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। यह अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन यह एक बीमारी या परिस्थिति का लक्षण है, जिसमें तत्काल चिकित्सकीय मदद लेने की जरूरत पड़ती है।

बिलिरुबिन एक पीले रंग का पदार्थ है, जो खून में मौजूद लाल रक्त कणिकाओं के 120 दिन के साइकिल के पूरे होने पर टूटने से बनता है। बिलिरुबिन में बिलि होता है, जो लिवर में बनने वाला पाचक तरल पदार्थ होता है और यह गोल ब्लेडर में रहता है। यह भोजन के अवशोषण और मल के उत्सर्जन में मदद करता है। जब बिलिरुबिन किसी कारण से बिलि के साथ मिश्रण नहीं बना पाता या जब लाल रक्त कणिकाएं सामान्य से कम अवधि में टूटने लगती है तो खून में बिलिरुबिन का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है। यह अन्य अंगों में पहुंचकर उनमें भी पीलापन पैदा कर सकता है।

पीलिया इस तरह कई बीमारियों की वजह बन जाता है। मलेरिया, सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया जैसे रोग बिलिरुबिन के निर्माण की गति को तेज कर देते हैं, जबकि हेपेटाइटिस, अल्कोहलिक लिवर की बीमारी, ग्रंथियों का बुखार, लिवर का कैंसर, और यहां तक कि अत्यधिक मात्रा में शराब पीने से बिलिरुबिन को प्रोसेस करने की लिवर की क्षमता प्रभावित होती है। इसके अलावा अन्य परिस्थितियां, जैसे कि गॉल स्टोन्स और पैनक्रियाटिटिस, शरीर से बिलिरुबिन को बाहर निकालने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप करती हैं।

पीलिया के लक्षण

बिलिरुबिन का स्तर खून में बढ़ने से, त्वचा, नाखून और आंख का सफेद हिस्सा तेजी से पीला होने लगता है।

- लिवर की किसी भी अन्य परेशानी की ही तरह, पीलिया में भी स्पष्ट तौर पर लिवर में तकलीफ होती है। एक तरह से असुविधाजनक खुजली होती है।
- अक्सर फ्लू-जैसे लक्षण विकसित होते हैं और मरीज को ठंड लगने के साथ ही या उसके बिना भी बुखार चढ़ने लगता है।
- मतली, खाने के प्रति विरक्ति, भूख कम लगना।
- पेट में दर्द उठना, कभी-कभी मरोड़ उठना।
- वजन घटना
- गहरा-पीला पेशाब होना
- लगातार थकान महसूस करना

रोग की पहचान

एक डॉक्टर को मरीज की शारीरिक जांच से अंदाजा हो जाता है कि उसे पीलिया हो सकता है। खासकर आंखों और त्वचा के रंग से इसकी पहचान हो जाती है। फिर भी डॉक्टर पुष्टि और उसकी गंभीरता के लिए, इस तरह के ब्लड टेस्ट करवा सकता है-

- बिलिरुबिन टेस्ट
- फुल ब्लड काउंट (एफबीसी) या कम्प्लीट ब्लड काउंट (सीबीसी)
- हेपेटाइटिस ए, बी और सी के टेस्ट

पीलिया और हेपेटाइटिस

यह अक्सर कहा जाता है कि पीलिया की वजह से हेपेटाइटिस होने की आशंका बढ़ जाती है। हो सकता है कि यह बयान शत-प्रतिशत सही न हो। हालांकि, यह जानना बेहद जरूरी है कि (वयस्कों में) पीलिया एक लक्षण है, जबकि हेपेटाइटिस बी लिवर की एक बीमारी जो वायरस की वजह से होता है। पीलिया या हायपर बिलिरुबिनेमिया जरूरी नहीं कि हर बार हेपेटाइटिस की वजह से ही हो । लिवर की अन्य बीमारियों और जेनेटिक कारण भी खून में बिलिरुबिन के स्तर में अस्थिरता पैदा कर सकते हैं। हेपेटाइटिस या लिवर में जलन-सूजन पांच अलग-अलग तरह के वायरस की वजह से हो सकती है (इन्हें हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी या ई कहा जाता है)। वायरल हेपेटाइटिस सबसे ज्यादा संक्रमित भी होता है।

भारत में टीकाकरण

विश्व स्वास्थ्य संगठन के निर्देशों का पालन करते हुए भारत सरकार ने देश के हर हिस्से में हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किए हैं। हेपेटाइटिस बी का टीका सिर्फ नवजात शिशुओं को लगाया जाता है। हेपेटाइटिस ए का टीका बच्चों के साथ ही वयस्कों को भी लगाया जा रहा है।

टीकाकरण की सूची

हेपेटाइटिस ए टीका

- डोज 1– 12 से 23 माह उम्र के बीच
- डोज 2– पहले डोज से 6 से 18 माह बाद
- अतिरिक्त डोज- ऐसे बच्चों और वयस्कों को, जिन्हें यह होने का खतरा हो

हेपेटाइटिस बी टीका

- डोज 1– जन्म के 24 घंटे के भीतर
- डोज 2– जन्म के 6 हफ्ते बाद
- डोज 3– जन्म के 10 हफ्ते बाद
- डोज 4 -जन्म के 14 हफ्ते बाद
- किशोरों को 18 साल की उम्र होने तक टीका लगाया जा सकता है। खासकर यदि उन्हें शुरुआती उम्र में न लगा हो तो।

हेपेटाइटिस इंफेक्शन से बचाव के लिए स्वस्थ आहार लेना, साफ पानी पीना और साफ-सुथरे माहौल में रहना, नियमित कसरत करना और शराब पीने से दूर रहना जरूरी है।

डॉ0 के आर शांडिल
द रीव क्लिनिक, शिमला
अधिक जानकारी के लिए लिखें: therievtime@iirdshimla.org

EXERCISING UNCONSTITUTIONAL RIGHTS

There was a time when Election Commission was not known to anybody in general public. Thanks to Mr. T.N. Sheshan, the Former Chief Election Commissioner who brought this apex constitutional body into limelight by starting bringing electoral reforms. After his regime, every CEC continued maintaining the importance of this key institution of world's largest democracy. Today nobody can take this for granted but has to reveal accountability towards its regulations.

Similarly, the role of Supreme Court of India has also been seen pro-active in maintaining sanctity of our constitution more prominently for last 10- 15 years. Apart from issuing necessary directives to the Legislative and Executive, the apex body sometimes takes self-cognizance on the issues affecting natural justice. Such actions significantly increased faith of the common people in our Judiciary.

In the present scenario of elections in the country, the people of Republic of India are having full assurance that the above two constitutional authorities shall always work to safeguard the interest of the country especially when the political parties are limitlessly trying to allure the voters. Presently this allurement is going to have long lasting impact on our economy, people's aspirations and progress of the country.

The key factor of any nation's progress is its citizens who make the nation progressive if consciously attuned to become productive by creating such enabling environment. Japan is the live example of such citizen's consciousness where the country got elevated as technology and economy rich despite the fact that Japan does not have sufficient land even to create living space to its people and least resources except water with consistent challenges like high frequency of earthquake.

On the other hand, there is an example of Pakistan where the state created environment is disastrous to the humanity and the common people suffering at many fronts. The country's image as well as economy is sinking day by day. It is obvious that the people occupying decision making positions need to decide whether we need to cultivate the minds of the citizens towards more productivity in order to create more resources or we just need to make them habitual to wait for utilizing created resources.

The present election manifestos of both national parties i.e. Congress and BJP have made the people of this country rethink whether we actually need such parties or not. The most objectionable allurement of both the parties is their assurance to distribute money to the people once power captured. After analyzing the impact of BJP's bit different kinds of governance in recently completed tenure, the fearsome Congress had to come up with assurance touching extremities like money distribution to farmers. Without rationalizing this statement, BJP also had to issue its manifesto on the similar lines just to match with the expectations created by Congress because everything is justified in Love and War. But how can one justify such claims which are fully objectionable on the following grounds:

- **Promising for distributing money post-election is like issuing post dated cheques to the voters for buying votes.**
- **The money in the national treasury comes from the tax payers pocket. Have the tax payers been asked and have the tax payers approved for such "BANDAR BAANT" of the money collected through taxes?**
- **Until we delegate the powers by virtue of our votes and they take oath thereafter, taking such decisions and giving such assurances is illegal.**
- **If this trend continues, the rights of the voters will be auctioned in future.**
- **Instead we could have found the root causes of farmers suicides and supported them in more productions and better selling prices besides creating irrigation infrastructure and watersheds.**

1. Promising for distributing money post-election is like issuing post dated cheques to the voters for buying votes. When Election Commission and Supreme Court are silent on this, does it mean that we are allowing the political parties to buy votes for money? There have been many unofficial instances of money distribution for votes in many parts of the country and similar scenes are also seen in the movies too. In such instances, the money seems coming from the pockets of the political parties or the contestants. But this time the money is coming from the exchequer of the country. If it's so let's make it legitimate to use country's resources for buying votes. Keeping common people's mind-set in view, the parties and candidates that make tall claims or assure distribution of higher amount will win and govern. Such auction of the governance has to be stopped immediately.

2. Secondly, why are we becoming so innocent to know that money in the national treasury does not belong to political parties. Then how can these parties decide in the distribution style and volume. Let political parties pay the assured amount out of their pocket, not from the country's exchequer.

3. Thirdly, the money in the national treasury comes from the tax payers pocket. Have the tax payers been asked and have the tax payers approved for such "BANDAR BAANT" of the money collected through taxes? How can one take decision on others money, need to be taught to the political parties.

4. Fourthly, we the citizen give decision making rights to the government, not to the political parties. Whosoever sworn in has the right and powers to take all such decisions because citizens give all their rights to the elected representatives or the government. Until we delegate the powers by virtue of our votes and they take oath thereafter, taking such decisions and giving such assurances is illegal.

5. Fifthly, do we actually want government to distribute money like this? The role of the government is not to distribute money but to empower people so that they need not to live on others mercy and use money for such purposes as be deemed fit.

We have to teach people how to catch fish rather feeding them always with fish caught by someone else. There has been continuous suicides by the farmers in different regions especially in Vidarbha Region in Maharashtra. We, as a country and political parties as government, miserably failed to prevent such suicides. Do we expect by paying Rs.6000/ every month or every year will stop the farmer's suicides? Instead we could have found the root causes of farmers suicides and supported them in more productions and better selling prices besides creating irrigation infrastructure and watersheds.

The political parties seem driving country towards wrong directions. We have experienced the people served with food for two rupees or five rupees have stopped working. Such practices convert people as non-performing assets (NPA) which is not good sign for any economy.

It is high time that the Election Commission, Supreme Court and the High Courts take sou-moto cognizance of the matter and issue directions to the political parties to delete such clauses from their manifestos. Otherwise this trend will continue and the rights of the voters will be auctioned in future.

Dr. L.C. Sharma
Editor in Chief
Mob.94180 14761, md@iirdshimla.org

अश्वथामा हतो नरो वा कुंजरो....

वनों पर अर्धसत्य को आधार मानना भविष्य के लिए चुनौती / पेड़ बचाने के अलावा और कोई विकल्प है ही नहीं

महाभारत में गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर के मुख से मात्र इतना सुनकर कि अश्वथामा हतो नरो व कुंजरो....., अपने हथियार त्याग दिए। उनके इस अर्धसत्य को सुनने के बाद हताशा ने उनके प्राण ले लिए। एक तो कहने वाला कोई और नहीं स्वयं धर्मराज और सत्यनिष्ठ युधिष्ठिर थे और दूसरे उनकी एक ही पंक्ति को यानि अर्धसत्य को सुनकर विश्वास करने वाले द्रोणाचार्य निराशा में डूब गए। यहां इस उदाहरण से यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे देश में वनों के संरक्षण और पर्यावरण को लेकर भिन्न-भिन्न तरह की सर्वेक्षण रिपोर्ट आती रहती है जिससे ज्ञात होता है कि भारत में वनों की स्थिति बहुत ही अच्छी है और लगातार वनों का घनत्व बढ़ता जा रहा है। वन संपदा कई गुना बढ़कर रिकॉर्ड बना रही है।

वनों पर आई रिपोर्टस को देखें और पढ़ें तो देश में हरियाली में सम्मानजनक इज़ाफा हुआ है। यह गर्व की बात हो सकती है। पिछली एक रिपोर्ट में सरकार ने आंकड़े प्रस्तुत कर बताया कि देश में कुल जंगलों का क्षेत्रफल बढ़कर 7,08,273 वर्ग किलोमीटर हो गया है। ये देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.54 प्रतिशत है। ट्री कवर शहरी क्षेत्रों में समम्मानजनक स्थिति में है। शहरों में लगे पेड़ों को कवर 1243 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। हमारे देश में सभी राज्यों में कर्नाटक और केरल में जंगलों की बढ़ौतरी में सर्वाधिक योगदान आंका गया है।

पहाड़ी राज्यों का फॉरेस्ट कवर क़रीब 2 लाख 83 हज़ार वर्ग किलोमीटर है जो कि देश के कुल क्षेत्रफल का 40 प्रतिशत से अधिक है। यहां यह सोचने का विषय है कि जिस प्रकार के आंकड़ें सरकार समय-समय पर वनों को लेकर सामने आती है..क्या वास्तविकता भी इस सांचे में ढली हुई है? बहुत से जानकार एवं बुद्धिजीवी इन आंकड़ों को सैंप्लिंग त्रुटि कह कर सत्य आधारित नहीं मानते। इस पर कुछ बातें तो ग़ौर करने योग्य है क्योंकि आंकड़ें हरियाली और वनों की सघनता को तो बताते हैं लकिन लगातार काटे गए पेड़ों के स्थान पर कितने पेड़ लगाए गए...इसका जवाब नहीं आता है।

इस बात को समझने का समय आ गया है कि **वन नही तो जीवन नही** यानि हमारा जीवन वृक्षों के एहसानों पर ही बचाया जा सकता है। मनुष्य ने प्रकृति के साथ जिस बेरहमी से व्यवहार किया है उसका ख़ामियाज़ा आने वाली पीढ़ीयों को भुगतना ही पड़ेगा और इसके संकेत यह धरती देना आरम्भ भी कर चुकी है। हमारी आवश्यकताओं की समस्त पूर्ति का संवाहक वृक्ष ही है। केवल हरियाली, आच्छादित धरती का स्वप्न नहीं अपितु सुरक्षित एवं सुखमय जीवन की आशाओं का सागर भी है। हम इस बात को वैश्विक स्तर पर विकास की गति के साथ-साथ निरंतर असंख्य पेड़ों की बलि चढ़ाते गए और लगाने के नाम पर चिरस्थाई खामोशी घने जंगलों को मैदान बनाती गई। सरकारी रिपोर्टस और सर्वेक्षणों को एक किनारे रखते हुए यदि हम वनों की स्थिति देखें तो हैरत होती है कि हमने अपनी सुख-सुविधाओं के लिए पेड़ों से लदे जंगल भी मैदान बना दिए...और बनाते चले गए। आज पहाड़ नंगे हैं और मैदान बनते जा रहे हैं साथ ही वनों का अंधाधुंध दोहन हमें बर्बादी के कगार पर ले आया है। इस बर्बादी का सबसे अधिक प्रभाव हिमालय यानि पहाड़ों पर पड़ा है। विकास हमेशा विनाश की सान पर चलता है लेक़िन ऐसा नहीं कि उससे सबक लेते हुए सुधार न हो सके। पेड़ों ने बलि दी तो उसके स्थान पर यदि पेड़ों का लगाने की प्रक्रिया को भी उसी अनुपात में अपनाया जाता तो स्थिति कुछ और होती। निर्माण कार्य की विनाशकारी दौड़ का ख़ामियाज़ा किसी ने यदि स्वयं को मिटा कर भुगता है तो वो वन है, पेड़ हैं। पेड़ों को काटा तो व्यवहारिकता में गया लेक़िन उन्हें लगाने की प्रक्रिया अधिकतर कागज़ी दस्तावेज़ों में ही क़ैद रही। सेटेलाईट व्यू एवं रिपोर्ट को आधार नहीं माना जा सकता हैं क्योंकि भारत के बड़े भूभाग पर हरियाली दिखने का अर्थ यह नहीं कि वहां वन ही है और यदि वन है तो किस प्रकार के वन? यानि वनों में भी कौन से वृक्ष और किस गुणवत्ता के वृक्ष विद्यमान हैं? क्योंकि जीआईएस या सेटेलाईट आधारित रिपोर्ट में तो झाड़ियों से ढके क्षेत्र भी हरियाली आच्छादित दिखाई देते हैं।

जल हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है इसे इस बात से समझा जा सकता है कि यदि तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो वो पानी के लिए होगा। नीति आयोग की माने तो लगातार घट रहा भूजल स्तर 2030 में किसी आपदा से कम स्थिति को पैदा करने वाला नहीं होगा। भूजल स्तर को बिना वृक्षों के कभी भी नहीं बढ़ाया जा सकता है। वर्षा के लिए वृक्ष सीधे तौर पर जिम्मेवार है। भूमि के क्षरण व बहाव को रोकने में भी वृक्ष ही भूमिका निभाते हैं। जहां वृक्ष नहीं होंगे वहां उपजाऊ मिट्टी वर्षा जल के साथ ही बह जाती है। ज़मीन में नमी के लिए हरियाली और पेड़ों का होना अनिवार्यता है। ऐसे में इस बात को सहजता से समझा जा सकता है कि एक वृक्ष कितना अनमोल है जिसे धराशायी करने में हमें कुछ ही पल लगते हैं।

पर्यावरणविद प्रोफेसर आर के गुप्ता अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि धरती का विनाश हो जाएगा एक दिन अगर शीघ्र ही वृक्षों को नहीं बचाया गया। वृक्ष प्राणवायु का सबसे बड़ा स्रोत है। ऑक्सीजन का दूसरा कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। इसके अलावा जल के संरक्षण और पीने के पानी की भविष्य में भयावकता से अगर बचना है तो वृक्षों को कटने से तो बचाना ही होगा साथ ही एक अभियान के तहत निरंतर वृक्षारोपण की प्रक्रिया को जारी रखने की आवश्यकता है। लोग पहाड़ों की चोटियों पर घर बनाने की होड़ में पहाड़ों का सीना चीर कर सड़कें और अन्य सुविधाओं के लिए प्रकृति का शोषण मनमुताबिक कर रहे हैं। ऐसे में पेड़ों की बलि कानूनन एवं ग़ैर कानूनन चढ़ाई जा रही है।

मेरे द्वारा आरटीआई के तहत मांगी गई एक सूचना में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। विकास की अंधी दौड़ में पीछे सब कुछ बर्बाद होता जा

रहा है। सूचना के अधिकार में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से प्राप्त सूचना में खुलासा हुआ कि परमाणु से ढली के बीच बन रहे फोरलेन में असंख्य पेड़ों को धराशायी कर दिया गया है। 4 सितंबर 2018 तक परमाणु से ढली के बीच 40 हज़ार से अधिक पेड़ों को ज़मींदोज़ किया जा चुका है और अब तक न जाने कितने और पेड़ बल चढाए जा चुके होंगे। इन आंकड़ों को राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग प्राधिकरण ने प्रदान किया जबकि राज्य सरकार के अधिकार तो इससे भी अधिक पेड़ काटे जाने की बात को कबूलते हैं।

सूचना के अनुसार सूचना में एनएचएआई ने बताया कि एनएचडीपी-111 (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) ईपीसी मोड़ के आधार पर परमाणु से सोलन अनुभाग एनएच 22 में 67.00 किलोमीटर से 106.139 किलामीटर का निर्माण हो रहा है।

एनएचडीपी-111 (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) ईपीसी मोड़ के आधार पर ही सोलन से कैथलीघाट अनुभाग एनएच 22 में 106.139 किलामीटर से 129.05 किलोमीटर का निर्माण हो रहा है।

एनएचडीपी-111 (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) एन्यूटी (वार्षिकी) हाईब्रिड मोड़ के आधार पर ही कैथलीघाट से ढली अनुभाग एनएच 22 में 129.05 किलामीटर से 156.507 किलोमीटर का निर्माण हो रहा है।

परमाणु से सोलन में वन विभाग की ज़मीन पर 12 हज़ार 508 पेड़ काटे गए हैं जबकि डिफेंस भूमि पर 1 हज़ार 882 तथा निजी भूमि पर 7 हज़ार 807 पेड़ काटे गए हैं। जिनका कुल योग 22 हज़ार 197 बनता है।

सोलन से कैथलीघाट के बीच वन विभाग की ज़मीन पर 1 हज़ार 150 पेड़ काटे गए हैं।

कैथली घाट से ढली के बीच वन विभाग की ज़मीन पर 9 हज़ार 576 पेड़ काटे गए और निजी भूमि पर 7 हज़ार 173 पेड़ों को कटना पड़ा है। जिसका कुल योग 16 हज़ार 749 है। यानि सितंबर प्रथम सप्ताह तक 40 हज़ार से अधिक पेड़ ज़मींजोद हो चुके हैं।

जो समझौता हुआ उसके अनुसार काटे जाने वाले पेड़ों के एवज़ में कई गुना पेड़ लगाए जाने की बात की गई थी जबकि अभी तक एक भी पेड़ नहीं लगाया गया। सरकार को अभी लैंड बैंक ही नहीं मिल रहे हैं। उधर एनएसएआई द्वारा पेड़ लगाने और उसके संरक्षण हेतु निर्धारित राशि सरकार यानि वन विभाग को दे रखी है जिससे पेड़ लगाए जाने थे और उनका संरक्षण भी किया जाना था। सरकार इस मुद्दे पर बिल्कुल भी गंभीरता से क़दम नहीं उठा रही है जिसका ख़ामियाज़ा भविष्य में सबको ही उठाना पड़ेगा क्योंकि अगर पेड़ कम होते गए तो जीवन भी शिथिल होता जाएगा।

हमारे देश की आबादी जिस तेजी से बढ़ रही है उससे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कहीं न कंही जंगलों और पेड़ों पर निर्भर है। कागज़ से लेकर ईधन और श्वास से लेकर जीवन तक वृक्ष ही आधार है। ऐसे में सरकार को इसे एक महा जन अभियान और अभियान को आंदोलन में परिवर्तित कर वनों के संरक्षण में सार्थक पहल करने की प्रबल आवश्यकता है। वन कैसे हो, किस गुणवत्ता के वृक्ष हों...इस पर जानकारी का अभाव देहात से शहर तक

प्रकृति प्रेमी पर्यावरणविद प्रो० आर के गुप्ता के अनुसार पृथ्वी पर सब कुछ ठीक नहीं है। भविष्य ख़तरे में आ रहा है। हमने विकास के नाम पर जीवनदायी वृक्षों को कतारबद्ध काट-काट कर जंगलों साफ करने का कार्य किया और पहाड़ों को विकास की बलि पर मैदान बनाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है। चोटी पर बसने की लालसा ने पहाड़ों को धरातल से ही कमज़ोर कर दिया है और घर तक सड़कों के जंजाल में वृक्षों की बलि दी जा रही है। विकास का यह कभी भी तात्पर्य नहीं निकाला जाना चाहिए कि हम विनाश को न्यौता दें। वनों पर सरकारी आंकड़ों के विपरीत अपने आस-पास की स्थिति बड़ी भयावक लग रही है। जंगल नहीं बचेंगे तो जल भी नहीं होगा। जल नहीं होगा तो जीवन की परिकल्पना व्यर्थ है। हम घर बनाते हैं या सड़क निकालते हैं....तो पेड़ों की जड़ों को खोखला कर देते हैं जिससे पेड़ गिरने लगता है। इसे बचाना आवश्यक है न कि गिरते पेड़ को काट दो या गिरा दो।

हैं। हमें उच्च गुणवत्ता वाले वृक्षों को रोपित करने व संरक्षित करने पर विचार करना चाहिए। पेड़ हमारे संसाधन है जिनसे हमारे समाज की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है। परन्तु क्या हम इस बात को समझ पा रहे हैं कि इसे परिवार के सदस्य से भी अधिक स्नेह और सुरक्षा की आवश्यकता है।

सामान्य लापरवाही से बड़े विनाश के संकेत

गर्मियां शुरु हो चुकी है और इसके साथ ही वनों में आग लगने की घटनाऐं भी। क्या जंगल में आग खुद ही लगती है? नहीं, यह हमारी ही लापरवाही है जो इतनी अमुल्य संपदा को नष्ट करने के लिए जिम्मेवार है। स्कूल जाते बच्चे खेल-खेल में माचिस की तिल्ली झाड़ियों में फैंकते हैं जिससे सैंकड़ों बार पूरा का पूरा जंगल स्वाहा हो जाता है। अनेकों बार बीड़ी-सिगरेट पीने वाले जलती बीड़ी या सिगरेट रास्ते में फैंक देते हैं जिससे आग की घटनाऐं बढ़ जाती है। गांव में जलाने के लिए लकड़ियों के काटे जाने के बाद उसकी झाड़ियों को आग लगाई जाती है जिससे वही आग पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लेती है। आग लगने के बाद नए पौधे तो जल कर नष्ट हो ही जाते हैं साथ ही ज़मीन पर पेड़ और घास नहीं बल्कि कांटेदार झाड़ियां ही उगती है।

लकड़ी के तस्करों ने भी जंगलों को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। सरकार इस तस्करों पर लगाम लगाने की बात तो करती है लेक़िन स्थितियां बहुत अधिक नहीं बदली है। देवदार के दरख़्तों को मिनटों में गिरा दिया जाता है। इसके अलावा कानून तो अपनी मलक़ियत में भी पेड़ काटने की स्वीकृति व नियमावली में बना हुआ है लेक़िन क्या लोग इसका अनुपालन करते हैं? बेतहाशा निर्माण कार्यों के चलते बड़े से बड़े पेड़ों को काट दिया जाता है।

यहां उन लोगों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है जो समाज में वनों के महत्व और वृक्षों के संरक्षण में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। वर्ष में वन महोत्सव के नाम पर पौधा रोपण हमारे जीवन में एक निरंतर प्रक्रिया का रुप धारण कैसे करे...इस पर मंथन करना आवश्यक है। बहुत सारी संस्थाऐं पौधा रोपण और वन संरक्षण में सराहनीय कार्य तो कर रही है लेक़िन आवश्यकता है उन्हें प्रोत्साहित करने और उनके अभियान को जन आंदोलन बनाने की।

समाज के लिए आदर्श हैं सामूलरदा थिमक्का

एक महिला का जज़्बा समाज में परिवर्तन लाने में किस प्रकार प्रेरणा बन सकता है यह बात उम्र से बुजुर्ग और हौंसले से युवा सामूलरदा थिमक्का ने साबित कर दिखाया है। कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर 384 बरगद के वृक्षों व हज़ारों अन्य वृक्षों को रोपित और संरक्षित कर मिसाल कायम कर दी है। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए कभी पेड़ लगाने का शौक उनकी जीवन की शैली बन गया। उन्हें इसके पुण्य कार्य के लिए अनेकों बार सम्मानित किया जा चुका है। हमें उनसे यह सीख लेने की आवश्यकता है कि समाजहित एवं मानव कल्याण में एक छोटा सा क़दम भी मीलों तय कर सकता है।

पेड़ सबसे बड़ा कार्बन शोषक है और ऑक्सीजन का स्रोत है। ग्लोबल वार्मिंग पूरे विश्व के लिए एक चुनौती बन चुकी है। धरती गर्म हो रही है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं। बाढ़ और आपदाओं का दौर पूरे विश्व में तबाही मचा रहा है। प्रकृति का दोहन मनुष्य के लिए अब विनाश का कारण बन चुका है। ये पेड़ ही हैं जो इस असंतुलित हो रही प्रकृति में संतुलन बना सकते हैं। उपजाऊ मिट्टी को बहने से रोक सकते हैं। ज़मीन में नमी के साथ ही हमारे भोजन, फसलें और परिवार का लालन-पालन जुड़ा हुआ है। ज़मीन में नमी होने से हरियाली होगी और पानी की क़िल्लत का सामना भी नहीं करना होगा। ये सब वृक्ष द्वारा ही संभव हो पाता है अन्य कोई विकल्प है ही नहीं। सरकार की एक वृहद् परियोजना जलागम विकास से देश में बड़ी आशाऐं बंधी थी, लेक़िन वांछित परिणाम नहीं आ सके। पानी को छोटे-छोटे नालों में रोकना और वहां वृक्षारोपण कर उस स्थान को हरियाली में बदलने के बाद इसके दूरगामी परिणाम भी कमाल के थे। जहां जलागम क्षेत्र में बारिश के पानी को चैक डैम आदि बनाकर रोका जाना था वहां से आसपास के क्षेत्रों में नमी से न केवल प्राकृतिक स्रोतों का पुनर्भरण होगा बल्कि घास, हरियाली भी वर्ष भर रहेगी। लेक़िन इसके वांछित परिणाम नहीं मिल सके।

मुझे याद है एक समाजसेवी ने मुझे वृक्षों पर एक उम्दा उदाहरण देते हुए कहा था कि हम जब तक वृक्षों को अपने परिवार में शामिल नहीं करते, उनका संरक्षण संभव नहीं है। उनसे प्रेरणा लेकर घर पर जन्म दिवस के अवसर पर दो वृक्ष लगाए तो एक का नाम अपनी स्वर्गवासी दादी और एक का नाम दादा जी के नाम पर रखा। आज घर पर उन दोनों वृक्षों में पूरा परिवार दादा-दादी के दर्शन करता है और उन पेड़ों की देखभाल इसी भावना के साथ कर रहा है। ऐसा व्यवहार और बर्ताव हम पौधों के साथ करना आरम्भ कर देंगे तो न केवल पेड़ लगाने की प्रवृति बढ़ेगी बल्कि उनका संरक्षण भी संभव हो पाऐगा।

क्या सरकारी आंकड़ों को मानकर हमें यहां प्रसन्न होने का अधिकार मिल जाता है? एक छोटा सा उपरोक्त उदाहरण यह समझने के लिए काफी नहीं है कि हम वनों के साथ बलात्कार करना छोड़ दें। हज़ारों पेड़ दिन-दिहाड़े काटे जा रहे हैं और लगाने के नाम पर सरकार लैंड बैंक ढूंढ रही है। एक पेड़ की कीमत आंकने में हम असफल हैं और यहां तो हज़ारों-लाखों पेड़ बलि चढ़ रहे हैं। अब समय है कि हम गंभीरता से इस विषय पर चिंतन, मंथन करें और भावी पीढ़ी को भी इससे अवगत करवाऐं। पेड़ लगाने से पेड़ को संरक्षित करने तक हम अपना उत्तरदायित्व और कर्तव्य निश्चित करें। यदि रालेगण सिद्धी जैसी सूखी और बंज़र धरती पर हरियाली और पानी की कूलें बह सकती है अपने आस-पास हम इस प्रकार का प्रयास क्यों नहीं कर सकते हैं? ऐसा न हो कि श्वास और पानी की बूंदों के लिए विकास की ईमारतों से हमारी चीख कोई सुन ही न पाए... जब भी हो जैसे भी हो, पौधा लगाऐं...

हेम राज चौहान
संपादक, द रीव टाइम्स
Chauhan.hemraj09@gmail.com,94184 04334

हिमाचल प्रदेश में अब तक 50 हजार लीटर शराब जब्त, आयोग के पास 13 शिकायतें

द रीव टाइम्स ब्यूरो, शिमला

चुनाव आचार संहिता लागू रहने के दौरान हुई नाकेबंदी में पुलिस, आबकारी विभाग तथा आयकर विभाग के दस्तों ने प्रदेश में 49,902.253 लीटर शराब, बीयर तथा लाहण के अतिरिक्त 415 किलोग्राम हेरोइन और 14477 किलोग्राम चरस जब्त की।

हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अतिरिक्त निर्वाचन कार्यालय को आचार संहिता उल्लंघन की 13 शिकायतें मिलीं, जिनमें से एक राजनीतिक दल की और 12 आम जनता की ओर से आई। इन शिकायतों के अलावा 149 शिकायतों में से 85 का शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है।

मुख्य निर्वाचन कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बीते दिनों शिमला में बताया कि चुनाव आचार संहिता लागू रहने के दौरान हुई नाकेबंदी में पुलिस, आबकारी विभाग और आयकर विभाग के दस्तों ने प्रदेश में करीब 50 हजार लीटर शराब, बीयर व लाहण के अतिरिक्त 415 किलोग्राम हेरोइन और 14477 किलोग्राम चरस जब्त की।

प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस के पास गुरुवार को 1965 लाइसेंसधारी हथियार जमा हुए हैं, वहीं असामाजिक गतिविधियों में संलिप्त 11 लोगों की पहचान भी कर ली गई हैं। इसी प्रकार जिलों की कुल 82 शिकायतों में से 58 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। वहीं बाकी बची हुई शिकायतों को संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए भेजा गया हैं।

बता दें कि चुनाव कार्यक्रम के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीटों पर अंतिम और 7वें चरण 19 मई को वोट डाले जाएंगे।

शादी में वोट मांगे तो प्रत्याशी के खर्च में जुड़ेगा समारोह का आधा खर्च

रीव टाइम्स ब्यूरो, शिमला

चुनावी मौसम में शादी, मुंडन या अन्य समारोहों की दावतों और धाम में प्रचार करना प्रत्याशियों को भारी पड़ सकता है। नामांकन के बाद अगर नेताओं ने यहां प्रचार किया तो समारोह की आधी राशि चुनावी खर्च में जुड़ जाएगी। शादियों के सीजन को देखते हुए चुनाव आयोग ने सख्ती बरतना शुरू कर दी है। आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (उपायुक्तों) को निगरानी के निर्देश दिए हैं।

जिलों में गठित विभिन्न टीमें नेताओं की हर मूवमेंट पर नजर रखेंगी। इन दिनों पार्टियों के बड़े आयोजन भी आयोग के राडार पर हैं। चुनाव के दौरान प्रत्याशी ऐसे समारोहों में भीड़ को देखते हुए फायदा उठाने की ताक में रहते हैं।

इनमें धार्मिक अनुष्ठानों से लेकर छोटे-बड़े घरेलू कार्यक्रम शामिल हैं। प्रत्याशी को बिना समर्थकों के ही ऐसे निजी कार्यक्रमों में शिरकत करने की अनुमति रहेगी। इसमें वोट मांगने या चुनावी बैठक करने की इजाजत नहीं होगी। मुख्य निर्वाचन कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि नेताओं की मूवमेंट पर विभिन्न टीमों की नजर रहेगी। साथ ही उनकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी

मंदिरों में फूलों के चढ़ावे का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने मांगा ब्योरा

द रीव टाइम्स ब्यूरो, शिमला

मंदिरों में चढ़ने वाले फूलों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नया तरीका निकाला है। इसके तहत अब फूलों से धूप व अगरबत्ती बनाने का काम किया जाएगा। शुरूआती दौर में कांगड़ा के ब्रजेश्वरी देवी मंदिर में सफल ट्रायल के बाद अब बोर्ड ने इस प्रक्रिया को सभी मंदिरों के सहयोग से विस्तृत रूप से संचालित करने की ठानी है। इसी के तहत बोर्ड ने भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग को पत्र लिखकर मंदिरों में चढ़ने वाले फूलों का ब्यौरा मांगा है। दरअसल, सूबे के मंदिरों में हर रोज करीब बीस टन फूलों का चढ़ावा चढ़ाया जाता है। इन फूलों को अभी तक मंदिर प्रशासन मंदिर की सफाई के नाम पर नदियों, नालों व आसपास के खाली मैदानों में फेंक देते थे।

इससे नदियों के प्रदूषण की समस्या पैदा हो रही थी। पीसीबी ने हाल में सीएसआईआर व एक निजी कंपनी के सहयोग से बृजेश्वरी देवी मंदिर में शुरू किए गए प्रोजेक्ट के सफल संचालन के बाद इसे विस्तृत रूप देने की कवायद शुरू की है।

इसके तहत मंदिरों से फूल इकट्ठा कर उन्हें प्रोजेक्टों को दिया जाएगा जहां हर्बल सुगंधित धूप बनाए जाएंगे। बोर्ड इन प्रोजेक्टों को लगाने व स्थापित करने में आर्थिक मदद भी करेगा।

582 दिन बाद जेल से रिहा हुए आईजी जहूर जैदी

द रीव टाइम्स ब्यूरो, शिमला

हिमाचल के बहुचर्चित गुड़िया दुष्कर्म एवं हत्या मामले से जुड़े सूरज हत्याकांड में गिरफ्तार आईजी जहूर हैदर जैदी 582 दिन बाद को कंडा जेल से रिहा हो गए।

5 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई कर उसे मंजूर कर दिया था, जिसके बाद 6 अप्रैल को स्थानीय अदालत ने उनकी रिहाई की शर्तें तय कर आदेश जारी कर दिए।

6 अप्रैल को शाम करीब साढ़े पांच बजे कोर्ट से रिहाई आदेश जैसे ही जेल पहुंचे, आधे घंटे में कागजी कार्रवाई पूरी कर जेल प्रशासन ने उन्हें रिहा कर दिया।

बता दें, 6 जुलाई 2017 को दसवीं की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म हत्या के आरोप में गिरफ्तार सूरज की 18-19 जुलाई की रात पुलिस हिरासत के मौत हो गई थी।

हाईकोर्ट के आदेश पर मामले की जांच में जुटी सीबीआई ने 29 अगस्त 2017 को आईजी जैदी, ठियोग के तत्कालीन डीएसपी मनोज जोशी, कोटखाई थाने के एसएचओ राजिंद्र सिंह समेत आठ पुलिस कर्मी गिरफ्तार किये थे।

25 नवंबर 2017 को सीबीआई ने अदालत ने इन सभी के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। इससे पहले जांच एजेंसी ने घटना के समय शिमला के एसपी रहे डीडब्ल्यू नेगी को भी 16 नवंबर 2017 को गिरफ्तार कर लिया। 19 जनवरी 2018 को आईजी जैदी ने

चार्जशीट दाखिल होने का हवाला देते हुए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में जमानत की याचिका दायर की लेकिन कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। इसके बाद 23 मार्च 2018 को वह सुप्रीम कोर्ट चले गए। इसके बाद को उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देने का फैसला सुनाया था।

शहरी निकायों को पूरा करने होंगे मानदंड : अग्रवाल

ठोस कूड़ा प्रबंधन और स्वच्छता को लेकर बैठक आयोजित

द रीव टाइम्स ब्यूरो, शिमला

शहरी निकायों में स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर आयोजित बैठक में मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने निर्देश जारी किए कि स्वच्छता के लिए सभी शहरी निकायों में गठित वार्ड कमेटियों की नियमित तौर बैठकें आयोजित की जाएं।

इसके साथ ही इन कमेटियों के माध्यम से ठोस तरल कूड़ा पृथकीकरण के बारे में जागरूक किया जाए। इस बाबत धर्मशाला के डीआरडीए के सभागार में ठोस कूड़ा कचरा प्रबंधन को लेकर शहरी निकायों और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी आयोजित की गई। इसमें शहरी निकायों में ठोस कूड़ा कचरा प्रबंधन को लेकर उठाए गए कदमों की समीक्षा भी की गई।

उन्होंने कहा कि शहरी निकायों के लिए ठोस कूड़ा प्रबंधन और स्वच्छता के लिए निर्धारित मापदंडों को पूरा करना अनिवार्य है। स्वच्छता के लिए डोर-टू-डोर स्तर पर ही तरल और ठोस कूड़ा कचरा अलग-अलग से एकत्रित करना जरूरी है, ताकि संयंत्र में तरल तथा ठोस कूड़ा कचरे का सही तरीके से उपयोग हो सके।

स्कूलों में छात्रों को बनाएं स्वच्छता प्रहरी

प्रदेश का स्वच्छ के लिए स्कूलों में छात्रों को स्वच्छता प्रहरी भी बनाया जाए, जो अपने अपने घरों में स्वच्छता को लेकर अभिभावकों सहित आस पास के लोगों को जागरूक कर सकें। सभी शहरी निकायों को आधुनिक तकनीक के ठोस कूड़ा कचरा निष्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए कदम उठाने चाहिए। निजी शैक्षणिक संस्थानों, शापिंग मॉल और होटल प्रबंधन संस्थानों को भी अपने स्तर पर ठोस कूड़ा कचरा प्रबंधन के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रेरित किया जाए। खड्डों और नदियों में भी किसी तरह से पानी के बहाव के साथ कूड़ा कचरा नहीं पहुंचे इसके लिए आवश्यक प्लान तैयार किया जाए।

सीवरेज से जोड़े जाएं सभी शहरी निकाय

सभी शहरी निकायों में शत प्रतिशत सीवरेज कनेक्शन के लिए उचित कदम उठाए जाएं। शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों और पर्यटन स्थलों के लिए भी कूड़ा एकत्रीकरण की दिशा में प्लान तैयार किया जाना जरूरी है। इससे पहले उपायुक्त संदीप कुमार ने कांगड़ा जिले में स्वच्छता और कूड़ा कचरा प्रबंधन के लिए उठाए गए कदमों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई।

हिमाचल में भाजपा ने मनाया 39वां स्थापना दिवस

द रीव टाइम्स ब्यूरो, शिमला

भाजपा ने बीते 6 अप्रैल को 39वां स्थापना दिवस हिमाचल के सभी 7,723 बूथों पर मनाया। इसी कड़ी में शिमला स्थित पार्टी के प्रदेश मुख्यालय दीपकमल में स्थापना दिवस मनाया गया। स्थानीय बूथों के भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में बतौर मुख्यातिथि शामिल हुए प्रदेश महामंत्री चंद्रमोहन ठाकुर ने सभी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी, प्रदेश और राष्ट्र के लिए बिना रुके-थके कार्य करने के लिए बधाई दी।

प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती ने ऊना स्थित भाजपा कार्यालय में स्थापना दिवस मनाया। सत्ती ने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर कहा कि प्रदेश की चारों लोकसभा सीटों पर भाजपा की जीत का दावा किया गया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रेमकुमार धूमल ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के पांच बूथों पर स्थापना दिवस मनाया। कहा कि 39 साल पूर्व समाजसेवा और देश को ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से भाजपा की स्थापना हुई और हमारी पार्टी इस राह पर अग्रसर है।

इसी महीने खुलेगी रोहतांग टनल

सासे की टीम ने बर्फ हटाने को भरी हामी बीआरओ ने शुरु किया काम

द रीव टाइम्स ब्यूरो

लाहुल-स्पीति के लोग इसी महीने रोहतांग टनल से गुजरेंगे। चुनाव आयोग के आदेशों के बाद जहां टनल खोलने की प्रक्रिया को अंजाम देने में बीआरओ जुट गया है, वहीं 8 अप्रैल को हिम आवधाव अनुसंधान संस्थान (सासे) की एक टीम ने रोहतांग टनल का निरीक्षण किया है। यही नहीं, सासे की टीम हर दस दिन के बाद टनल के नॉर्थ पोर्टल का निरीक्षण करेगी। लिहाजा बीआरओ ने जहां चुनाव आयोग के आदेशों के बाद लाहुल के लोगों की आवाजाही के लिए रोहतांग टनल को बहाल करने के लिए कसरत शुरू कर दी है, वहीं नहर्थ पोर्टल से बर्फ हटाते हुए बीआरओ की टीम सिस्सू तक जाएगी, जबकि बीआरओ की दूसरी टीम केलांग से सिस्सू की तरफ बर्फ हटाते हुए आ रही है। रोहतांग टनल के नहर्थ पोर्टल के पास जहां ग्लेशियर्ज के गिरने का खतरा बना हुआ है, वहीं सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों ने सासे के विशेषज्ञों को रोहतांग टनल के नॉर्थ पोर्टल का निरीक्षण करने का आग्रह किया था।

हाईकोर्ट के आदेश से हुए तबादले में चुनाव आयोग की मंजूरी जरुरी नहीं

द रीव टाइम्स ब्यूरो, शिमला

हिमाचल हाईकोर्ट ने चुनाव आचार संहिता के दौरान कर्मचारियों के तबादले पर महत्वपूर्ण आदेश देते कहा कि कोर्ट के निर्देशों से हुए तबादले में चुनाव आयोग की इजाजत लेना जरूरी नहीं है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश संदीप शर्मा की खंडपीठ ने वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बिलासपुर की प्रधानाचार्य राकेश कुमारी की याचिका का निपटारा करते यह व्यवस्था दी।

मामले के अनुसार हाईकोर्ट ने प्रार्थी की याचिका पर शिक्षा विभाग को आदेश दिए थे कि वह प्रार्थी को बिलासपुर के नजदीक किसी स्कूल में स्थानांतरित करे। इसके बाद प्रार्थी ने 25 मार्च को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया कि उसे वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला हवां जिला बिलासपुर में स्थानांतरित किया जा सकता है। वहां के प्रधानाचार्य अपनी इच्छा से तलवाड़ा में सेवाएं देने पर राजी हो गए हैं। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया कि प्रार्थी की आपसी सहमति से तबादला आग्रह मंजूर कर लिया गया है, लेकिन चुनाव आचार संहिता के कारण तबादला आदेश जारी करने से पहले चुनाव आयोग की मंजूरी लेना बाकी है। कोर्ट ने शिक्षा विभाग को आदेश दिए कि वह एक सप्ताह के भीतर जरूरी आदेश जारी करे। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि तबादला कोर्ट के आदेश के तहत होना है, ऐसे में चुनाव आयोग की मंजूरी जरूरी नहीं है।

लेखपाल, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी रखेंगी नजर

वीडियो में अगर पाया गया कि कार्यक्रम का उपयोग जनता से जुड़ने, चुनावी अपील के लिए किया है तो प्रत्याशी की मुश्किल बढ़ना तय है। आम तौर पर नेता कार्यकर्ताओं के साथ ऐसे कार्यक्रमों के जरिये लोगों से जुड़ने की रणनीति बनाते हैं।

मुख्य निर्वाचन कार्यालय के अनुसार बड़े कार्यक्रमों के अलावा जन्मदिन, मुंडन जैसे छोटे आयोजनों पर भी नजर रखने के लिए लेखपाल व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद ली जाएगी। कोशिश यह है किसी भी ऐसे कार्यक्रम में प्रत्याशी मतदाता को किसी भी तरह के लालच या आश्वासन के जरिये प्रभावित न कर सके।

राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में हिमाचल ने जीता स्वर्ण पदक

द रीव टाइम्स ब्यूरो, शिमला

अंडर-14 वर्ग में हिमाचल टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। फाइनल में हिमाचल टीम ने दिल्ली को 29-10 अंकों से हराया। प्रतियोगिता स्टूडेंट्स गेम्स एंड स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ (उत्तर प्रदेश) में करवाई गई।

स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली हिमाचल टीम में कप्तान जसकरण मिन्हास, उप कप्तान हरिश कुमार, दीपक रणौट, शिवम पांडे (नालागढ़), अमन ठाकुर, सुजल ठाकुर (जमथल), अंचित ठाकुर, मोहित ठाकुर (जयनगर), ओम दुर्वासा (जुखाला) और ऋषभ जगोता (जयनगर) शामिल रहे।

यूनिक स्पोर्ट्स एंड एजुकेशनल स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी के महासचिव राजेश शर्मा, मुख्य खेल प्रशिक्षक हरिश मिन्हास (नालागढ़) और दाड़लाघाट के नरेंद्र चौधरी

हिमाचल का सबसे तेज़ गति से उभरता पाक्षिक समाचार पत्र द रीव टाइम्स में मार्केटिंग हेतु युवाओं (लड़के/लड़कियों) की आवश्यकता है। एक स्थाई रोजगार एवं बेहतर वेतनमान के साथ आकर्षक कमीशन का प्रावधान रहेगा। इच्छुक शीघ्र ही संपर्क करें।
द रीव टाइम्स, दूरभाष : 9418404334, Chauhan.hemraj09@gmail.com, hem.raj@iirdshimla.org

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

प्रधानमंत्री को मिले अतंर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से बढ़ी देश की साख

द रीव टाइम्स ब्यूरो

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक विभिन्न अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। विश्व के अलग-अलग मंचों पर प्रधानमंत्री मोदी दिए गये इन पुरस्कारों के कारण न केवल उनकी बल्कि भारत की साख में भी बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी को हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'जायेद मेडल' से नवाजे जाने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान भारत और यूएई के आपसी संबंधों को मजबूत करने के लिए दिया गया है।

भारत ने लगातार तीसरे साल आईसीसी टेस्ट चौंपियनशिप का खिताब बरकरार रखा

International Cricket Council

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारतीय क्रिकेट टीम ने लगातार तीसरे साल आईसीसी टेस्ट चौंपियनशिप अपने पास ही बरबरार रखी है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने 01 अप्रैल 2019 को इस बात की जानकारी दी। यह गदा उस टीम को दी जाती है जो एक अप्रैल की कट ऑफ तारीख तक टेस्ट रैंकिंग (ICC Ranking) में नंबर-वन स्थान पर रहती है। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम फिलहाल पहले नंबर पर है। न्यूजीलैंड की टीम दूसरे नंबर पर है।

भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड बने

द रीव टाइम्स ब्यूरो

हॉकी इंडिया ने 08 अप्रैल 2019 को आस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी एवं कोच ग्राहम रीड को भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया हैं। वे जल्द ही बेंगलुरू स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) में जारी कैम्प में भारतीय टीम से जुड़ेंगे। इस कैम्प के लिए 60 खिलाड़ियों का चयन किया गया है।

ग्राहम रीड ने कहा की भारतीय हॉकी टीम का मुख्य कोच बनना मेरे लिए गर्व और सम्मान की बात है। इस खेल में किसी टीम के इतिहास की तुलना भारत से नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा की मुझे भारतीय टीम की तेज और आक्रामक हॉकी पसंद है।

नक्सली हमले में विधायक समेत चार की मौत

द रीव टाइम्स ब्यूरो

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा में 9 अप्रैल को नक्सलियों ने प्रदेश में प्रथम चरण के मतदान का प्रचार थमने से कुछ समय पहले भाजपा के काफिले पर हमला कर दिया। उन्होंने विधायक भीमा मंडावी का वाहन आइईडी (इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) विस्फोट कर उड़ा दिया। इसमें मंडावी की मौत हो गई, जबकि उनकी सुरक्षा में तैनात चार जवान शहीद हो गए।

गौरतलब है कि 25 मई 2013 को झीरम घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस के काफिले पर हमला किया था। इसमें प्रदेश कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, उनके पुत्र दिनेश पटेल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष महेंद्र कर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल समेत करीब 31 लोगों की मौत हो गई थी।

भारतीय सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल किए विमान का मलबा ढूंढा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारतीय सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल किए गए अमेरिकी वायुसेना के एक विमान का मलबा खोजा है। भारतीय सेना ने 04 अप्रैल 2019 को ट्वीट कर यह जानकारी दी। भारतीय सेना के 12 सदस्यीय गश्ती दल ने पुलिस के साथ मिलकर 30 मार्च 2019 को अरूणाचल प्रदेश के रोइंग जिले से अमेरिकी वायुसेना के एक विमान का मलबा खोज निकाला, जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय का है।

ओडिशा के कंधमाल हल्दी को जीआई टैग प्रदान किया गया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

ओडिशा की कंधमाल हल्दी को विशिष्ट भौगोलिक पहचान के लिए भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग प्रदान किया गया। कंधमाल की लगभग 15 प्रतिशत आबादी हल्दी की खेती से जुड़ी हुई है। जीआई टैग प्राप्त हो जाने से इसे विश्व बाजार में एक स्वतंत्र स्थान मिल जायेगा। इसके पंजीकरण हेतु कंधमाल अपेक्स स्पाइसेज असोसिएशन फॉर मार्केटिंग द्वारा प्रयास किया गया था। इसके पंजीकरण आवेदन को वस्तु भौगोलिक संकेतक (पंजीकरण एवं संरक्षण) अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 1 के तहत मंजूरी दी गई है।

विश्व होम्योपैथी दिवस 2019: नई दिल्ली में दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन

द रीव टाइम्स ब्यूरो

विश्व होम्योपैथी दिवस पर केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सीसीआरएच) की ओर से 9 अप्रैल और 10 अप्रैल 2019 को नई दिल्ली के डॉ. अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केन्द्र में दो-दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।

होम्योपैथी के संस्थापक डॉ. क्रिश्चियन फ्रेडरिक सेमुएल हनीमैन के जन्मदिवस के अवसर पर विश्व होम्योपैथी दिवस आयोजित किया जाता है। सम्मेलन में होम्योपैथी से संबंधित अनेक विषयों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। समारोह में होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के प्रचार-प्रसार तथा इसकी विशेषताओं और विकास पर चर्चा करेंगे।

लक्ष्मी विलास बैंक एवं इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस के विलय को मंजूरी

लक्ष्मी विलास बैंक तथा इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के विलय को हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई है। विलय के तहत लक्ष्मी विलास बैंक के मंजूर योजना के तहत बैंक के शेयरधारकों को प्रति १०० शेयर के बदले इंडियाबुल्स के १४ शेयर मिलेंगे। गौरतलब है कि इससे पूर्व वर्ष २०१४ में भी लक्ष्मी विलास बैंक ने इंडियाबुल्स के साथ विलय की घोषणा की थी लेकिन उस समय भारतीय रिजर्व बैंक ने इस विलय को नामंजूर कर दिया था।

विश्वभर में 11 करोड़ 13 लाख लोग भुखमरी से प्रभावित: UN रिपोर्ट

द रीव टाइम्स ब्यूरो

विश्वभर में करीब 11 करोड़ 13 लाख लोगों को पिछले वर्ष घोर भुखमरी जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा था। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ की एक नई रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार युद्ध, जलवायु से जुड़ी आपदाओं और आर्थिक अशांति जैसे कारणों से पैदा हुए खाद्य संकट की वजह से दुनिया के 53 देशों के लोगों को पिछले साल घोर भुखमरी जैसी स्थिति का सामना करना पड़ा था।

सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन से संबंधित केरल हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

सुप्रीम कोर्ट ने 01 अप्रैल 2019 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) की याचिका को खारिज करते हुए केरल हाई कोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें कर्मचारियों को उनकी पूरी सैलरी के हिसाब से पेंशन देने का आदेश दिया गया था। इस फैसले के बाद निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी ज्यादा पेंशन मिलेगी। केरल हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में ईपीएफओ को कहा था कि रिटायर होने वाले कर्मचारियों को उनकी अंतिम सैलरी के आधार पर पेंशन मिलनी चाहिए। ईपीएफओ ने केरल हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

आंध्र में जन सेना प्रत्याशी मधुसूदन ने ईवीएम तोड़ी, गिरफ्तार

द रीव टाइम्स ब्यूरो

आंध्र प्रदेश में अनंतपुर जिले के गुंताकल विधानसभा क्षेत्र के पोलिंग बूथ पर जन सेना के उम्मीदवार मधुसूदन गुप्ता ने ईवीएम को फर्श पर पटककर तोड़ दी। वह इस बात से नाराज थे कि विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों के नाम सही तरीके से नहीं प्रदर्शित किए जा रहे हैं। इसको लेकर वह मतदान कर्मियों पर बरस पड़े। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान उनकी पुलिस से भी कहासुनी हुई।

वायु प्रदूषण से जीवन प्रत्याशा 20 महीने कम हुई-ग्लोबल रिपोर्ट

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अमेरिका के दो संस्थान हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टिट्यूट एवं इंस्टिट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन ने हाल ही में विश्व भर में वायु की गुणवत्ता से सम्बंधित रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट का शीर्षक है - स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर-2019 । रिपोर्ट के अनुसार भारत और चीन में विश्व भर में वायु प्रदूषण से होने वाली 5 मिलियन मौतों का 50 प्रतिशत मौजूद है। रिपोर्ट में कहा गया है कि लंबे समय तक घर से बाहर रहने या घर में वायु प्रदूषण के चलते वर्ष 2017 में स्ट्रोक, डायबिटीज, हार्ट अटैक, फेफड़े के कैंसर या फेफड़े की पुरानी बीमारियों से करीब पूरी दुनिया में करीब 50 लाख लोगों की मौत हुई है।

कंगला टोंगबी की ऐतिहासिक लड़ाई का प्लेटिनम जुबली समारोह मनाया गया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मणिपुर स्थित कंगला टोंगबी में हुए भीषण युद्ध की याद में तथा सैनिकों के सम्मान में प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को कंगला टोंगबी यादगार समारोह मनाया जाता है। एडवांस ऑर्डिनेन्स डिपो (एओडी) के 221 आयुध कर्मियों द्वारा 6-7 अप्रैल 1944 की रात को लड़े गए कंगला टोंगबी के युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध के भयंकर युद्धों में से एक माना जाता है।

इस लड़ाई में 221 अग्रिम आयुध डिपो के आयुध कार्मिकों के सर्वोच्च बलिदान को सम्मान देने के लिए इम्फाल के निकट कंगला टोंगबी वहर मेमोरियल पर सेना आयुध कोर द्वारा 07 अप्रैल 2019 को प्लेटिनम जयंती के तौर पर मनाया गया।

घाटी में बुलेट पर भारी बैलेट ईवीएम खराबी की शिकायत

द रीव टाइम्स ब्यूरो

आतंकवाद प्रभावित बारामूला लोकसभा सीट पर बुलेट पर बैलेट भारी पड़ा। लोगों ने लोकतंत्र पर विश्वास जताते हुए जमकर वोट डाले। हालांकि हाजिन और सोपोर में कम मतदान हुआ। बाकी इलाकों में महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों में वोट को लेकर काफी उत्साह देखा गया। जम्मू में भी लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। बारामूला में 35.01 और जम्मू में 72.16 फीसदी वोट पड़े। पिछली बार यह 69.17 फीसदी था। हालांकि कई जगहों पर ईवीएम खराबी की शिकायत भी मिली। नेशनल कहन्फ्रेंस अध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर बताया कि कांग्रेस का बटन ही नहीं काम रहा है।

पहले चरण में 20 राज्यों की 91 सीटों पर 65.77 फीसदी मतदान

द रीव टाइम्स ब्यूरो

दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में नई सरकार चुनने के लिए लोगों ने मतदान के रूप में प्रथम आहुति डाली। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर समेत 20 राज्यों की 91 सीटों पर बृहस्पतिवार को 65.77 फीसदी मतदान हुआ। इस दौरान यूपी के शामली में फायरिंग, आंध्र प्रदेश में दो राजनीतिक दलों के नेताओं की आपसी झड़प में टीडीपी नेता समेत दो लोगों की मौत हो गई। वहीं महाराष्ट्र में एक मतदान केंद्र के पास आईईडी धमाका किया गया। इसके अलावा इन राज्यों में कई जगहों पर ईवीएम में गड़बड़ी और मतदाता सूची में नाम नहीं होने की शिकायत भी मिली।

यूपी की आठ सीटों पर कुल 63.69 फीसदी ही मतदान हुआ जबकि 2014 में 65.76 प्रतिशत मतदान हुआ था। कैराना लोकसभा सीट के शामली में रसूलपुर गुजरान गांव में कुछ लोगों ने पूरे परिवार का वोट खुद डालने का मतदान कर्मियों पर दबाव बनाया। इससे इनकार करने पर भीड़ ने पथराव कर दिया और बूथ के अंदर घुसकर मतदान सामग्री को नष्ट करने की कोशिश की।

बीएसएफ जवानों ने लोगों को संभालने के लिए पहले लाठीचार्ज किया और फिर हवाई फायरिंग कर भीड़ को खदेड़ा। वहीं आंध्र प्रदेश के अनंतपुर के ताडीपत्री में टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प में टीडीपी नेता एस. भास्कर रेड्डी और एक वाईएसआर कांग्रेस कार्यकर्ता की मौत हो गई। टीडीपी ने रेड्डी की हत्या का आरोप लगाया है। विधानसभा अध्यक्ष कोडेला शिवप्रसाद राव समेत 10 लोग घायल भी हुए। राज्य में कई जगहों पर टकराव के हालात को देखते हुए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में वाघेजरी में एक मतदान केंद्र के पास नक्सलियों ने आईईडी धमाका किया। विस्फोट के वक्त मतदान हो रहा था। हालांकि इसमें किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। छत्तीसगढ़ से भी हिंसा की खबर है।

अमेरिका ने भारत को सीहॉक हेलिकॉप्टर बेचने को मंजूरी दी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अमेरिका ने भारत को 24 एमएच-60 आर रोमियो सीहॉक हेलिकॉप्टरों को बेचे जाने को मंजूरी दे दी है। भारत को पिछले एक दशक से अधिक समय से इन हंटर हेलिकॉप्टर की आवश्यकता थी।

अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मुताबिक-भारत को ये हेलीकॉप्टर 2.4 अरब डॉलर (लगभग 16 हजार करोड़ रुपए) में बेचे जाएंगे। हेलिकॉप्टर दुश्मन की पनडुब्बियों को नष्ट करने के अतिरिक्त जहाजों को खदेड़ने और समुद्र में तलाश एवं बचाव अभियान में कारगर साबित होंगे।

देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय प्रभावी हुआ

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

देना बैंक DENA BANK

विजया बैंक VIJAYA BANK A friend you can bank upon

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारत के दो सरकारी बैंकों - देना बैंक तथा विजया बैंक का 01 अप्रैल 2019 से बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय प्रभावी हो गया है। इन दोनों बैंकों के विलय के बाद बैंक अहफ बड़ौदा देश का तीसरा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। तीनों बैंकों के विलय के उपरांत विजया बैंक और देना बैंक की सभी शाखाएं बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखाओं के तौर पर काम करना आरंभ करेंगी।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी जानकारी में कहा गया है कि विजया बैंक और देना बैंक के उपभोक्ताओं को 01 अप्रैल 2019 से बैंक ऑफ बड़ौदा का उपभोक्ता माना जाएगा। विदित हो कि केंद्र सरकार ने बैंक ऑफ बड़ौदा को अतिरिक्त खर्च की भरपाई के लिये 5,042 करोड़ रुपये देने का हाल ही में निर्णय लिया था।

चुनाव आयोग ने पीएम मोदी पर बनी बायोपिक की रिलीज पर लगाई रोक

द रीव टाइम्स ब्यूरो

चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बायोपिक के रिलीज पर 10 अप्रैल 2019 को रोक लगा दी है। यह फिल्म 11 अप्रैल 2019 को रिलीज होनी थी। चुनाव आयोग ने कहा कि है कि जब तक लोकसभा चुनाव खत्म नहीं हो जाते, तब तक इस फिल्म पर रोक लगी रहेगी।

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक पीएम नरेंद्र मोदी की रिलीज पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका को 09 अप्रैल 2019 को खारिज कर दिया था।

द रीव टाइम्स संस्थापक: डॉ. एल.सी. शर्मा, द रीव टाइम्स पब्लिकेशन के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक श्री प्रदीप कुमार जरेट द्वारा एसोसिएट प्रैस सायबू निवास समीप सेक्टर -2, बस स्टैंड मिडल मार्केट न्यू शिमला-9, हि.प्र. से प्रकाशित एवं मुद्रित
प्रधान सम्पादक: डा. एल.सी. शर्मा
फोन न. 0177 2640761, मेल: editor@themissionriev.com
Title Code : HPBIL00313
RNI Reference No. 1328500

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

अमेजन के मालिक का 'मोबाइल हैक' सऊदी अरब पर डेटा चुराने का आरोप

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अमेजन के मालिक जेफ बेजोस के निजी संदेश नेशनल एंक्वायर टैबलॉयड के पास कैसे पहुंच गए, इसको पता लगाने के लिए जेफ ने एक पेशेवर को तैनात किया।

इस पेशेवर इंवेस्टीगेटर ने इस मामले का कनेक्शन सऊदी अरब से जोड़ा है। उनके मुताबिक अमेजन के मालिक जेफ बेजोस का मोबाइल हैक किया और उसमें मौजूद जानकारियों को टैबलॉयड को मुहैया कराया गया।

गेविन डी बेकर, बेजोस की तरफ से यह जांच कर रहे हैं कि आख़िर कैसे उनकी बेहद निजी जानकारियां लीक हो गईं और नेशनल एंक्वायर टेब्लॉयड को मुहैया कराई गईं।

इलेक्ट्रिक टैक्सी हेतु वायरलेस चार्जिंग देने वाला ओस्लो विश्व का पहला शहर

द रीव टाइम्स ब्यूरो

नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में इलेक्ट्रिक टैक्सियों के लिये वायरलेस चार्जिंग की सुविधा उपलब्ध कराने वाला यह दुनिया का पहला शहर बन गया है। नॉर्वे सरकार ने एक परियोजना के तहत ओस्लो शहर की सड़कों पर इंडक्शन टेक्नोलॉजी के साथ चार्जिंग प्लेट इंस्टॉल किया है, जहां इलेक्ट्रिक कार को चार्ज किया जा सकता है। नॉर्वे की कुल आबादी भारत से कहीं ज्यादा कम है। वहाँ की सरकार ने देश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिये एक परियोजना तैयार की है। सरकार की योजना के अनुसार ओस्लो में इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन का पुख्ता इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराकर लोगों में इलेक्ट्रिक कार खरीदने को बढ़ावा दिया जा रहा है।

आज नॉर्वे दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक कारें रखने वाला देश है और वहाँ 2023 तक शून्य उत्सर्जन प्रणाली कायम करने का लक्ष्य रखा गया है।

सूडान में 30 साल के शासन का अंत, आपातकाल लागू

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अफ्रीकी देश सूडान में राष्ट्रपति ओमर अल-बशीर का 30 साल का लंबा शासन 11 अप्रैल 2019 को समाप्त हो गया। सेना ने राष्ट्रपति ओमर अल-बशीर को 30 सालों के शासन के बाद इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया।

सूडान के रक्षा मंत्री अहमद अवद इब्न औफ के अनुसार, सेना ने राष्ट्रपति ओमर अल-बशीर को गिरफ्तार कर लिया है। रक्षा मंत्री ने सरकारी टीवी पर अपने संदेश में कहा कि, अगले तीन महीने तक देश में आपातकाल लागू किया जा रहा है। साल 1989 से सूडान की सत्ता संभाल रहे बशीर के खिलाफ कई महीनों से प्रदर्शन जारी था। सूडान सरकार द्वारा ब्रेड की कीमत तीन गुणा करने के बाद दिसंबर में यह प्रदर्शन शुरू हुए थे। सूडान में लोग महंगाई से जूझ रहे है।

अमरीका ने एंटी-सैटेलाइट परीक्षण पर भारत को किया आगाह

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारत के एंटी-सैटेलाइट मिसाइल परीक्षण के बाद अमरीका के कार्यवाहक रक्षा मंत्री पैट्रिक शानाहान ने अंतरिक्ष में कचरा बढ़ने को लेकर आगाह किया है।

पैट्रिक का कहना है कि इस तरह के परीक्षण से अंतरिक्ष में 'कचरा' पैदा होता है। बुधवार को भारत ने अपने ही उपग्रह को मार गिराया था। पैट्रिक का कहना है कि अमरीका इस बात का अध्ययन कर रहा है, जिसमें भारत ने कहा है कि उसने अंतरिक्ष में कचरा नहीं छोड़ा है।

अमरीका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश है जिसने इस तरह का परीक्षण किया है। चीन ने साल 2007 में एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया था, जिसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी काफी आलोचना हुई थी।

स्लोवाकिया के इतिहास की पहली महिला राष्ट्रपति

द रीव टाइम्स ब्यूरो

एंटी-करप्शन कैंडिडेट जुजाना कैप्यूटोवा ने स्लोवाकिया में हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है।

चुनाव जीतने के साथ ही जुजाना कैप्यूटोवा स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति भी बन गई हैं।

जुजाना कैप्यूटोवा के पास राजनीति को लेकर लगभग किसी भी तरह का अनुभव नहीं है। वहीं उनके सीधे प्रतिद्वंद्वी उच्च स्तरीय राजनयिक मारकोस सेफ्कोविक थे। मारकोस मौजूदा सत्तारुढ़ पार्टी की ओर से उम्मीदवार थे।

चीन ने साल 2007 में एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया था, जिसके बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी काफी आलोचना हुई थी।

यूरोप और ओशिनिया देशों के साथ व्यापार और आर्थिक सहयोग पर चर्चा

द रीव टाइम्स ब्यूरो

भारत ने हाल ही में नई दिल्ली में यूरोपीय और ओशिनियाई देशों के साथ आर्थिक सहयोग तथा व्यापार बढ़ाने के लिए उनके राजनयिकों के साथ चर्चा की है। इन देशों के साथ भारत ने हाल के दिनों में आर्थिक संबंधों को अगले स्तर तक ले जाने के प्रयासों के तहत कुछ व्यापारिक समझौते किए हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने बताया कि वाणिज्य सचिव अनूप वधावन ने यूरोपीय और ओशिनियाई देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत, यूरोपीय संघ और ओशिनिया में उपलब्ध अवसरों को समझने के लिए सरकार, निर्यात, व्यापार और निवेश से संबंधित संस्थानों, निर्यातकों और व्यवसायों आदि के हर स्तर पर संपर्क बनाए रखना जरूरी है। भारत और यूरोपीय देशों के बीच साल 2017-18 के दौरान 130.1 अरब डॉलर का व्यापार हुआ था। इसके निर्यात एवं आयात दोनों क्षेत्रों में दोहरे अंकों में वृद्धि दर्ज की गई। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक चौथाई हिस्सा यूरोपीय देशों से आता है। इसी तरह भारत की ओर से विदेशों में किए जाने वाले निवेश का लगभग 29.8 फीसदी हिस्सा यूरोप में जाता है।

इजरायल चुनाव 2019 बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी को बहुमत मिला

द रीव टाइम्स ब्यूरो

इजराइल में हुए आम चुनाव में मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की पार्टी ने जीत दर्ज कर ली है। चुनाव में उन्होंने वाम दलों के गठबंधन को हराया है। इस चुनाव में बेंजामिन नेतन्याहू को सेवानिवृत्त जनरल बेनी गैंट्ज से कड़ी टक्कर मिल रही थी। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू ने लगातार पांचवीं बार चुनाव जीत लिया है। चुनाव नतीजों का मतलब है कि नेतन्याहू इजराइल के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू की शानदार जीत पर पीएम मोदी ने बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेतन्याहू को टैग करते हुए लिखा कि आप भारत के सबसे बड़े मित्र हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी नेतन्याहू को प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है।

इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में केली रहे 340 दिन, बदल गया डीएनए

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अंतरिक्ष में करीब एक साल गुजारने वाले नासा के अंतरिक्षयात्री स्कॉट केली का शरीर पहले जैसा नहीं रहा। उनके शरीर में काफी बदलाव देखने को मिला है। उन्होंने धरती की परिक्रमा कर रहे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 340 दिन गुजारे थे। वह तीन साल पहले धरती पर लौट थे।

नासा के शोधकर्ताओं ने हाल ही में कक्षा में रहने के दौरान केली के शरीर ने कई बदलावों का सामना किया। उनकी कुछ कोशिकाओं में डीएनए परिवर्तित हो गया। उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली ने नए सिग्नलों की उत्पत्ति की, जबकि उनके शरीर में कुछ नए प्रकार के बैक्टीरिया पाए गए। इनमें से कई शारीरिक बदलाव नुकसानदेह नहीं पाए गए। लेकिन कुछ आनुवांशिक बदलाव और स्मृति संबंधी गिरावट दुरुस्त नहीं हो पाई है। इसके चलते वैज्ञानिकों में चिंता बढ़ गई है।

अमेरिका ने ईरानी सेना 'रिवॉल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स' को आतंकी संगठन घोषित किया

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अमेरिका ने 08 अप्रैल 2019 को ईरानी सेना रिवॉल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है. यह पहली बार है जब अमेरिका ने दूसरे राष्ट्र की सेना को आतंकवादी संगठन करार दिया है।

ईरान ने भी अमेरिका की 'सेंट्रल कमांड' को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। बहरीन ने अमेरिका के इस कदम का स्वागत किया है। अमेरिका ने आईआरजीसी और इससे जुड़े संस्थानों पर पहले से ही आतंकवाद को समर्थन देने और मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाता रहा है।

भारत और सिंगापुर के बीच 'बोल्ड कुरुक्षेत्र' युद्ध अभ्यास शुरु

द रीव टाइम्स ब्यूरो

इस युद्ध अभ्यास में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व कर्नल एस.पी. सिंह कर रहे हैं। जबकि सिंगापुर के दल का प्रतिनिधित्व लेफ्टिनेंट कर्नल टोंग चोंग कियात कर रहे हैं। यह १२वां अभ्यास है जो भारत-सिंगापुर के बीच किया जा रहा है।

भारत और सिंगापुर की सेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास 'बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास-२०१९' की बबीना में शुरूआत हुई। समारोह में दोनों सेनाओं की टुकड़ियों

डोनाल्ड ट्रंप के साथ तीसरी शिखर वार्ता के लिए किम जोंग ने रखी ये शर्त

द रीव टाइम्स ब्यूरो

उत्तरी कोरिया के प्रमुख किम जोन उन ने शनिवार को इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि अगर अमेरिका उचित और आपसी सहमति से समझौता करेगा, तो मैं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ तीसरी शिखर वार्ता करने के लिए तैयार हूं। कोरियन न्यूज एजेंसी के मुताबिक, उन्होंने कहा कि हनोई में हुई हमारी विफल शिखर सम्मेलन ने हमारे और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ वार्ता करने को लेकर संदेह पैदा किया हुआ था। अब यदि अमेरिका तीसरी शिखर वार्ता में सही तरीकों को अपनाएगा तो हम ये वार्ता करने के लिए तैयार है।

किम ने कहा कि मैं समझौते पर हस्ताक्षर करने में जरा भी संकोच नहीं करूंगा अगर यह ये डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक अहफ कोरिया (DPRK) और अमेरिका दोनों के हित में हो। इस बीच कोरियाई केंद्रीय समाचार एजेंसी ने कहा किम की टिप्पणी ने संकेत दिया कि प्योंगयैंड ने वॉशिंगटन की उस डील को खारिज कर दिया है, जिसमें सभी परमाणु कार्यक्रमों को खत्म करने की बात कही गई थी। किम ने यह भी कहा कि वॉशिंगटन को बात करने के लिए सहासी कदम उठाने की जरुरत है।

प्रधानमंत्री मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान

द रीव टाइम्स ब्यूरो

रूस के दूतावास की तरफ जारी बयान में कहा कि भारत के प्रधानमंत्री को भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को अभूतपूर्व तौर पर आगे बढ़ाने के लिए रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार (ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल) से सम्मानित किया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात के बाद रूस ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 'ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल' देने का फैसला लिया है। यह जानकारी नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास ने 12 अप्रैल 2019 को दी।

रूस के दूतावास की तरफ जारी बयान में कहा कि भारत के प्रधानमंत्री को भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी को अभूतपूर्व तौर पर आगे बढ़ाने के लिए रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार (ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल) से सम्मानित किया जाएगा।

जलियांवाला बाग में शहीदों को श्रद्धांजलि

द रीव टाइम्स ब्यूरो

13 अप्रैल 2019 को जलियांवाला बाग नरसंहार को 100 साल पूरे हो गए हैं। यह वही नरसंहार है जिसमें ब्रिटिश शासन में जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था। 13 अप्रैल को कई नेताओं ने जलियांवाला बाग के भीतर स्थित स्मारक स्थल पर सुबह श्रद्धांजलि अर्पित की साथ ही 13 अप्रैल 1919 को बर्बर तरीके से मौत के घाट उतारे गए लोगों की याद में दो मिनट का मौन भी रखा।

भारत को नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने की तैयारी में अमेरिका, संसद में अहम बिल पेश

द रीव टाइम्स ब्यूरो

अमेरिकी संसद में करीब आधा दर्जन प्रभावशाली सांसदों ने अमेरिका-भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक अहम बिल पेश किया है। अगर यह बिल लागू होता है तो अमेरिकी विदेश विभाग भारत को नाटो (नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन) के सहयोगी का दर्जा देगा। अमेरिका ऑर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट में भारत को नाटो सहयोगी देश के तौर पर तरजीह मिलेगी।

इस विधेयक पर काम कर रहे यूएस-इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम के मुताबिक, यह इस बात का प्रभावपूर्ण संकेत होगा कि रक्षा सौदों में भारत अमेरिका की प्राथमिकता में है। पिछले सप्ताह सांसद जो विल्सन ने बिल एचआर 2123 पेश किया था, वह हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी के वरिष्ठ सदस्य हैं। विल्सन ने कहा, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और क्षेत्र में स्थिरता का अहम स्तंभ है। भारत ने निर्यात नियंत्रण की नीतियों पर हमेशा प्रतिबद्धता दिखाई है।

युद्ध के मुहाने पर खड़े चीन-फिलीपींस

द रीव टाइम्स ब्यूरो

दक्षिण सागर में एक विवादित द्वीप पाग-असा पर चीनी दस्तक से बीजिंग और फीलिपींस के बीच तनाव बढ़ गया है।

फीलिपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने बीजिंग को आगाह करते हुए कहा कि उसे यहां से तत्काल वापस चले जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन का यह कदम सैन्य कार्रवाई को उकसाने वाला है। बता दें कि इस सप्ताह मनीला में स्थित पैग आसा द्वीप पर सैकड़ों चीनी तटरक्षक और मछुआरों की हलचल ने दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा था। इसके बाद इस विवादित द्वीप पर चीनी सक्रियता ने इस तनाव को और बढ़ा दिया है।

फीलिपींस के राष्ट्रपति ने कहा कि इस बाबत मैं न तो चीन से निवेदन करूंगा और न ही विनती। मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी सेना वहां मौजूद है। अगर चीन इस विवादित द्वीप का छूता है तो मेरे मेरे समक्ष केवल यही विकल्प है कि मैं अपने सैनिकों को आत्मघाती मिशन के लिए तैयार होने के लिए कहूंगा।

इंडोनेशिया में 6.8 तीव्रता के भूकंप से कांपी धरती, सुनामी की चेतावनी

द रीव टाइम्स ब्यूरो

इंडोनेशिया के सुलेवासी में 12 अप्रैल शाम 5.10 बजे (भारतीय समय के अनुसार) एक जोरदार भूकंप के साथ धरती कांप उठी। स्थानीय समय के अनुसार शाम 6.40 बजे आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.8 मापी गई। भूकंप के बाद इंडोनेशिया ने सुनामी की चेतावनी जारी की है। आपदा प्रबंधन विभाग ने सेंट्रल सुलेवासी के मोरोवली में लोगों से इलाका खाली करने के लिए कहा है।

भूकंप का केंद्र जमीन से 17 किलोमीटर की गहराई में बेंगई द्वीप से 85 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर बताया जा रहा है। जीओ फिजिक्स एजेंसी के प्रवक्ता के मुताबिक, इस भूकंप से सूनामी आने की आशंका है। एजेंसी समुद्री लहरों पर नजर बनाए हुए है। लोगों से इलाका खाली को कहा गया है। एजेंसी ने कहा है कि हो सकता है पहली लहर ज्यादा ऊंची न हो लेकिन उसके बाद आने वाली लहरें घातक हो सकती हैं।

द रीव टाइम्स
आपकी आवाज़ ही है
हमारी आवाज़

साभार : विभिन्न ऑन लाइन समाचार पत्र

करंट अफेयर्स

- फीफा द्वारा 04 अप्रैल 2019 को जारी विश्व रैंकिंग में जिस देश को 101वां स्थान प्राप्त हुआ है- भारत
- भारतीय सेना ने हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध में इस्तेमाल किए गए अमेरिकी वायुसेना के एक विमान का मलबा जिस राज्य में खोजा है- अरूणाचल प्रदेश
- वह देश जिसकी सरकार ने उत्तरपूर्वी तट के पांच शहरों और काउंटी में बड़े पैमाने पर लगी आग को 05 अप्रैल 2019 को राष्ट्रीय आपदा की स्थिति घोषित की- दक्षिण कोरिया
- जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमले के बाद प्रशासन ने बारामूला से उधमपुर तक के राष्ट्रीय राजमार्ग पर 31 मई तक प्रत्येक हफ्ते में नागरिक यातायात को जितने दिन बंद करने का फैसला किया गया है- दो
- भारत ने जिस देश के साथ लिथियम के विकास एवं औद्योगिक उपयोग हेतु एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं- बोलीविया
- वह देश जिसके लिए अमेरिका के हाउस ऑफ रीप्रेजेंटेटिव ने उसके गृह युद्ध से अमेरिका को अलग करने के पक्ष में मतदान किया - यमन
- एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने व्यापक आर्थिक चुनौतियों का हवाला देते हुए पाकिस्तान की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2018 में 5.2 प्रतिशत से गिरकर 2019 में इतना होने का अनुमान लगाया है - 3.9 प्रतिशत
- वैज्ञानिकों ने हाल ही में स्टीफन हॉकिंग के जिस सिद्धांत को मानने से इनकार किया है - डार्क मैटर
- वह आई आईटी जहां में बीआईएस मानकीकरण तथा अनुरूपता मूल्यांकन के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किये हैं -आईआईटी दिल्ली
- वह भारतीय दवा कम्पनी जिसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जापान की दवा कंपनी दाइची सैंक्यो के बकाया 4,000 करोड़ रुपये देने के लिए चेताया है-रैनबैक्सी
- एशियाई विकास बैंक ने 2019-20 के लिए जिस देश की जीडीपी विकास दर के अनुमान को घटाकर 7.2 प्रतिशत किया- भारत
- भारतीय सेना द्वारा हाल ही में जितने दिनों में जम्मू-कश्मीर के लेह में सिन्धु नदी पर सबसे लम्बे सस्पेंशन पुल का निर्माण किया गया-40
- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मार्च 2019 में जितने अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों (एपीए) पर हस्ताक्षर किए हैं-18
- हाल ही में वह देश जिसने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जायेद मेडल से नवाजने का फैसला किया है- संयुक्त अरब अमीरात
- वह देश जहां 5जी नेटवर्क विश्व में सबसे पहले लॉन्च होगा -दक्षिण कोरिया
- वह संस्थान जिसने हाल ही में scissors enzyme की खोज की है - सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी
- रिलायंस जियो ने हाल ही में चौटबोट बनाने वाली जिस कम्पनी का अधिग्रहण किया उसका नाम है -हैपटिक
- वह राज्य जहां भारतीय सेना के गश्तीब दल को अमेरिकी विमान का द्वितीय विश्व युद्ध के समय का मलबा मिला है -अरुणाचल प्रदेश
- भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में रेपो रेट में इतनी कमी की है - 0.25 प्रतिशत
- वह देश जिसके कृषि विभाग ने घोषणा किया है कि बिल्लियों पर जानलेवा प्रयोग अब नहीं किए जाएंगे जिनके कारण बीते 37 वर्षों में हजारों बिल्लियां मारी जा चुकी हैं- अमेरिका
- संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के मुताबिक, युद्ध, जलवायु आपदाओं जैसे कारणों से पैदा हुए खाद्य संकट के चलते पिछले वर्ष दुनिया के जितने देशों के करीब 11.13 करोड़ लोगों को घोर भुखमरी का सामना करना पड़ा-53
- गृह मंत्रालय ने साल 2018 का दिल्ली का सबसे अच्छा पुलिस स्टेशन जिसे घोषित किया है- कश्मीरी गेट पुलिस स्टेशन
- वह देश जिसके राष्ट्रपति अब्दुलअजीज बूतेफ्लीका ने 20 वर्षों के शासन के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है- अल्जीरिया
- राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नैशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंकिंग-2019 जारी कर दी जिसमें जिस आईआईटी ने ओवरऑल शीर्ष रैंकिंग हासिल की- आईआईटी मद्रास
- सेना द्वारा सिंधु नदी पर 40 दिन में बनाए गये 260 फुट लम्बे लोहे के सस्पेंशन पुल का नाम है - मैत्री ब्रिज
- वह रिपोर्ट जिसके अनुसार वायु प्रदूषण की वजह से 2017 में 50 लाख लोगों की मौत हुई है - स्टेट ऑफ द एयर-2019
- संयुक्त राष्ट्र द्वारा इन्हें हाल ही में म्यांमार के लिए स्वतंत्र जांच प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है -निकोलस कौमजियान
- सऊदी अरब की कम्पनी जो विश्व की एक साल में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कम्पनी बन गई है -सऊदी आरामको
- वह देश जिसने सीआरपीएफ कैंप पर हमले के साजिशकर्ता निसार अहमद को भारत को सौंप दिया है -यूएई
- सुप्रीम कोर्ट के अनुसार, जिस शहर को रहने लायक बनाने के लिए परिवार नियोजन की तरह कारों के लिए भी 'हम दो, हमारे दो' जैसी नीति लागू की जानी चाहिए- दिल्ली
- 20 ग्रैंड स्लैम विजेता रॉजर फेडरर ने 31 मार्च को फाइनल में जॉन इसनर को हराकर जितनी बार मियामी ओपन और करियर का 101वां सिंगल्स खिताब जीत लिया- चौथी बार
- विश्व ऑटिज्म जागरुकता दिवस जिस दिन को मनाया जाता है-02 अप्रैल
- सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ की याचिका को खारिज करते हुए जिस हाईकोर्ट के उस फैसले को बरकरार रखा है, जिसमें कर्मचारियों को उनकी पूरी सैलरी के हिसाब से पेंशन देने का आदेश दिया गया था- केरल हाईकोर्ट
- वह राज्य जिसकी कंधमाल हल्दी को विशिष्ट भौगोलिक पहचान के लिए भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग प्रदान किया गया- ओडिशा
- वह टीम जो आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप रैंकिंग में लगातार तीसरे साल पहले स्थान पर है-भारत
- उन तीन देशों को इस नाम से जाना जाता है जिनकी वित्तीय सहायता को हाल ही में ट्रम्प प्रशासन ने रोक दिया है - नॉर्दन ट्रायंगल
- वह देश जिसमें हुए आम चुनावों के दौरान वह विश्व का सबसे अधिक ऑनलाइन वोटिंग करने वाला देश बना-एस्टोनिया
- भारत का वह राज्य जहां जहर मिले हुए आहार खाने से तीन लुप्तप्राय प्रजातियों के लगभग 37 गिद्धों की मौत हो गई है -असम
- भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा देश भर में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए इतने रेडियो स्टेशनों के साथ मिलकर काम शुरू किया गया है -150
- वह महिला अधिकारी जिन्हें हाल ही में स्लोवाकिया की पहली राष्ट्राध्यक्ष के रूप में चुना गया है - जुजाना कैपुतोवा
- वह खिलाड़ी जिसने हाल ही में मियामी ओपन के फाइनल मुकाबले में जॉन इसनर को हराकर खिताब जीता है - रोजर फेडरर
- वह अंतरराष्ट्रीय संस्था जिसने हाल ही में माइंड द गैप -स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट नामक रिपोर्ट जारी की है - ऑक्सफैम
- वह देश जिसने हाल ही में सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है- दक्षिण कोरिया
- दिल्ली सरकार की स्कूल शिक्षक का नाम जिन्हें हाल ही में मार्था फेलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है -मनु गुलाटी
- पाकिस्तान ने इन्हें हाल ही में अपना नया विदेश सचिव नियुक्त किया है-सोहेल महमूद
- वह बैंक जिसमें हाल ही में देना बैंक और विजया बैंक का विलय कर दिया गया है -बैंक ऑफ बड़ौदा
- 'हादसे और आपहुदरी' नामक आत्मकथा की लेखिका का नाम जिनका हाल ही में निधन हो गया- रमणिका गुप्ता
- वह हवाई अड्डा जिसे स्काईट्रैक्स द्वारा विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया -चांगी एयरपोर्ट
- सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिए गये निर्देश में एक ईवीएम की जगह अब इतने ईवीएम व वीवीपैट पर्चियों का मिलान करने के लिए कहा है -पांच
- ईएसपीएन इंडिया मल्टी-स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2018 में इन्हें सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया -नीरज चोपड़ा
- ईएसपीएन इंडिया मल्टी-स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2018 में इन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया - पीवी सिंधु
- इन्हें हाल ही में विश्व बैंक का अध्यक्ष चुना गया है - डेविड माल्पास
- इन्होने हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के नए अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है -विक्रम किर्लोस्कर
- इन्हें हाल ही में पहले भारतीय सदस्य के रूप में पहली बार फीफा परिषद का सदस्य चुना गया -प्रफुल्ल पटेल
- वह फाइनेंसिंग कम्पनी जिसके साथ विलय हेतु लक्ष्मी विलास बैंक को मंजूरी मिल गई है - इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
- मणिपुर में वह स्थान जहां द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई की याद में 7 अप्रैल को प्लेटिनम जुबली समारोह मनाया गया- कंगला टोंगबी
- इन्होने सिविल सेवा परीक्षा -2018 में टॉप किया है - कनिष्क कटारिया
- वह राज्य जहां हाल ही में शोधकर्ताओं ने हैब्रोस्टेम प्रजाति की मकड़ी की खोज की है -केरल
- वह देश जहां हाल ही में सुरक्षित ऑनलाइन कंटेंट के लिए Online harms White Paper जारी किया गया है -ब्रिटेन
- वह भारतीय ऑनलाइन गेमिंग जिसे पहली बार गेमिंग यूनिकॉर्न प्राप्त हुआ है - ड्रीम-11
- वह कॉलेज जिसे NIRF रैंकिंग 2019 में पहला स्थान हासिल हुआ है - मिरांडा हाउस

हिमाचल सामान्य ज्ञान

- बिरशु मेले का आयोजन कहां किया जाता है-शमशी -कुल्लू
- गगल से कहां कहां के लिए स्पाइय जेट ने उड़ान शुरू की- पिंक सिटी जयपुर
- सरदार वल्लभाई क्लस्टर यूनिवर्सिटी मंडी के प्रथम कुलपति कौन है- डाक्टर सीएल चंदन
- सरदार वल्लभाई क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कौन से चार कॉलेजों में कैंपस बनाए गए हैं- मंडी, सुंदरनगर, द्रंग और बासा कॉलेज
- हिमाचल पारंपरिक लोक संस्कृति के संरक्षक लाल चंद प्रार्थी का संबंध किस जिले से है- कुल्लू
- कांगड़ा में भयंकर भूकंप कब आया था- 4 अप्रैल 1905
- रेड लिस्ट में शामिल बकरी की किस प्रजाति को हाल ही में कुल्लू के ग्रेट नेशनल पार्क में देखा गया है- सीरो
- हिमाचल प्रदेश का एससी और एससी और एसटी जनसंख्या प्रतिशत क्या है- 25.19 प्रतिशत और 8.88 प्रतिशत
- अनुभव स्कीम किस जिले से शुरू की गई थी-कुल्लू
- मुख्यमंत्री मंत्री युवा वन मित्र पुरस्कार योजना के तहत कितनी राशि मिलेगी-50,000
- प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व के तहत कितनी प्रतिशत महिलाओं ने 2016-2018 तक पंजीकरण करवाया- 68 प्रतिशत
- नई राहें नई मंजिलें कार्यक्रम के तहत कितने स्थानों को विकसित किया गया- 3- जंजैली, चांशल और बीड़ बिलिंग
- यमुना शरद महोत्सव किस जिले मे मनाया जाता है-सिरमौर
- जंगी थोपन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की कितनी क्षमता है-780 मेगावाट
- अटल मेडीकल एंड रिसर्च यूनीवर्सिटी किस जिले मे स्थापित की गई- मंडी
- ERRS की फुल फॉर्म क्या है-इमरजेंसी रिस्पांस सुपोर्ट सिस्टम
- हिमाचल में पहला नशीली दवाओं के दुरपयोग के खिलाफ अभियान केंद्र कहां खोला गया-बद्दी
- हाथीधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है - चंबा में
- कौन हिमाचल प्रदेश का 'राजपक्षी' है -जाजुराना
- सिरमौर राज्य का अंतिम शासक कौन था- राजेंद्र प्रकाश
- 'सोलंग' चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है-कुल्लू
- हिमाचल प्रदेश की कुल्लू घाटी को और किस नाम से जाना जाता है - देवघाटी
- हिमाचल प्रदेश की चिनाब नदी को और किस नाम से जाना जाता है- चंद्रभागा
- मध्य हिमालय क्षेत्र में निम्न में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है-पत्थरीली चिकनी मिट्टी
- हमीरपुर का संस्थापक कौन सा शासक था -हमीरचंद
- क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल का सबसे छोटा जिला - हमीरपुर
- 'रौरिक कला संग्रहालय' हिमाचल किस घाटी में स्थापित है- कुल्लू घाटी में
- 'कत्था उद्योग' हिमाचल प्रदेश के किस जिले में केंद्रित है-सिरमौर
- काँगड़ा घाटी रेल सेवा का परिचालन कब शुरू हुआ-1929 में
- 'ल्हाम' नामक वस्त्र हिमाचल के किस क्षेत्र में पहना जाता है- स्पिति
- हिमाचल निर्माता यशवंत सिंह के पैतृक गांव का नाम- चनालग
- कविराज के नाम से किसे जाना जाता है- पद्म देव
- प्रदेश के प्रथम कथक नर्तक कौन है-दिनेश गुप्ता
- रामपुर में कौन सा किला है- रैहण किला
- जमलू देवता की पूजा कहाँ पर की जाती है- कुल्लू
- मृकुला देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है-लाहुल-स्पीति
- हिमाचल का सबसे बड़ा मछली फार्म कहाँ पर है-दियोली (बिलासपुर)
- हिमाचल का कौन सा गांव देश का पहला हेरिटेज गांव है-परागपुर
- 'सिल्लिका' रेत हिमाचल प्रदेश में कहाँ पाई जाती है- बिलासपुर
- 'याक' प्रजनन फॉर्म हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर है-सांगला

अनुभव योजना

हिमाचल प्रदेश में पहली बार सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों से मिलने का समय और तारीख जैसी सुविधा मरीजों को घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से मरीजों की सुविधा के लिए अनुभव योजना शुरू की गई है।

वास्तव में यह एक डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म है। हिमाचल के नागरिक अनुभव योजना के तहत घर बैठे डॉक्टर से अप्वाइंटमेंट ले सकते हैं। यह व्यवस्था एक टोकन के जरिये होती है जिसमें आप डॉक्टर से समय लेकर अपनी सुविधा के हिसाब से उनसे दिखाने जा सकते हैं। अनुभव योजना अभी कुल्लु जिला अस्पताल में शुरू की गई है। जल्द ही इसे प्रदेश के सभी अस्पतालों में लागू करने की योजना है। हालांकि आईजीएमसी में कुछ समय पहले ऑनलाइन पर्ची बनाने की व्यवस्था भी शुरू की गई। अब अनुभव योजना से प्रदेश के अस्पतालों को जोड़ने का कार्य किया जा रहा हैं

हिमाचल सरकार नागरिकों के लिए डिजिटल हेल्थ सेवा को बढ़ावा देना चाहती है। डिजिटल हेल्थ सेवा की तरफ कदम बढ़ाते हुए पहले कदम के रूप में अनुभव योजना शुरू की गयी है।

कैसे काम करती है अनुभव योजना?

स्वास्थ्य विभाग की अनुभव योजना वास्तव में डिजिटल स्वास्थ्य सेवा की तरफ बढ़ता कदम है। ग्रामीण स्वास्थ्य विभाग की आशा वर्कर व स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से अनुभव योजना में मरीज ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से ही विशेषज्ञ डॉक्टर से अपनी सुविधा अनुसार अप्वाइंटमेंट ले सकते हैं। इसके साथ ही मरीजों को मोबाइल फोन पर एसएमएस के माध्यम से डॉक्टर से मिले समय की पुष्टि की जाएगी।

क्या होगा अनुभव योजना से लाभ?

अगर आपने ऑनलाइन सुविधा की मदद से किसी डॉक्टर से अप्वाइंटमेंट लिया है और किसी वजह से डॉक्टर से मिलने वाली तिथि या समय में कोई बदलाव किया गया तब भी आपको इसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा।

वास्तव में अनुभव योजना के तहत अप्वाइंटमेंट फिक्स करने के बाद आपके मोबाइल पर एक ई-पर्ची जेनरेट होगी। इसे दिखाकर डॉक्टर से इलाज कराया जा सकेगा।

कैसे लें डॉक्टर से अप्वाइंटमेंट?

अगर आपके पास स्मार्टफोन या कंप्यूटर या इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो अनुभव योजना के जरिये डॉक्टर से अप्वाइंटमेंट बुक करने के लिए आप आशा वर्कर की मदद ले सकते हैं।

अगर आपके पास स्मार्टफोन और इंटरनेट कनेक्शन है तो आप इस पेज की मदद से डॉक्टर से अप्वाइंटमेंट ले सकते हैं।

अनुभव योजना के अन्य फायदे

दूर दराज के इलाके से अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर से नहीं मिल पाने वाले मरीजों का समय और पैसा बचाने में मदद मिलेगी।

स्वास्थ्य सेवाओं को समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

स्वरोजगार के लिए हिमाचल सरकार से मदद

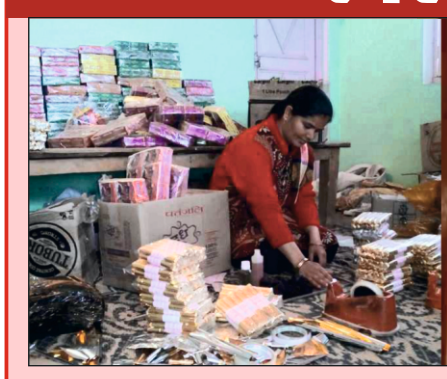

अगर कोई गरीब महिला छोटा-मोटा कारोबार करना चाहती हो उन्हें हिमाचल सरकार से स्व रोजगार सहायता योजना में मदद मिल सकती है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने महिलाओं को अपना रोजगार करने में मदद पहुंचाने के उद्देश्य से स्वयं रोजगार सहायता योजना शुरू की है। स्वयं रोजगार सहायता योजना में ऐसी महिलाओं को 2500 रुपये तक का अनुदान दिया जाता है जिनके परिवार की सालाना आय 35,000 रुपये से कम हो। इस आमदनी में हालांकि मनरेगा से हुई कमाई शामिल नहीं है। अगर ऐसी महिला अपना कोई छोटा-मोटा कारोबार करना चाहती हो उन्हें हिमाचल सरकार से स्वयं रोजगार सहायता योजना में मदद मिल सकती है।

ये है स्वयं रोजगार सहायता योजना का उद्देश्य

समाज के कमजोर तबके की महिलाओं को वित्तीय मदद देकर चाय-नाश्ते की दुकान, सिलाई मशीन, ब्यूटी पार्लर, कढ़ाई-बुनाई आदि जैसे काम करके अपने परिवार की आमदनी बढ़ाने में योगदान करने के उद्देश्य से स्वयं रोजगार सहायता योजना शुरू की गयी है।

क्या है रोजगार चुनने का ज़रिया?

हिमाचल में महिलाओं को स्व रोजगार के विकल्प उपलब्ध कराने के लिए ग्राम सभा आयोजित की जा रही हैं। ग्राम सभा में चर्चा का मुख्य मुद्दा रोजगार है। ग्राम सभा में जन-प्रतिनिधियों के सामने चर्चा कर महिलाएं अपने लिए रोजगार के अवसर और विकल्प पर बातचीत करेंगी। इसमें महिलाएं अपने लिए योजना बनाएंगी और इन योजनाओं को सिरे चढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार उन्हें वित्तीय मदद देगी। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। ग्राम सभा साल में दो बार आयोजित होगी महिला ग्राम सभा में पंचायत में सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर, बच्चों को खेलने के लिए मैदान, पार्क, पंचायतों का सौंदर्यीकरण, डेयरी फार्म, कढ़ाई-बुनाई, चाय-नाश्ते की दुकान जैसे स्व रोजगार के प्रस्ताव पर चर्चा की जा सकती है। इन प्रस्ताव को पारित करने के बाद मामला आम सभा में जाएगा, जहां इसे स्वीकृति दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश में 3226 ग्राम पंचायत हैं, जहां साल में दो बार यह सभा होनी है।

ऐसे करें आवेदन

हिमाचल सरकार की इस योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाएं अपने इलाके की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता या सुपरवाईजर से संपर्क कर सकती हैं। महिलाएं योजना का लाभ लेने के लिए सीधे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम अहफिसर (जिला कार्यक्रम अधिकारी) से भी मिल सकती हैं। हिमाचल प्रदेश के बाल विकास अधिकारी से भी योजना संबंधी मदद ली जा सकती है।

योजना में आवेदन करने के लिए योग्यता

महिला हिमाचल प्रदेश की मूल निवासी हो।

महिला की उम्र 18 साल से अधिक हो।

महिला के परिवार की कुल आमदनी 35,000 रुपये से कम हो।

परिवार का खर्च चलाने के लिए महिला काम करने की योजना बना रही हो।

इन दस्तावेजों की है जरुरत

फोटो आईडी कार्ड, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, निवास प्रमाण पत्र आधार कार्ड, आवेदन पत्र, हिमाचल सरकार वास्तव में स्व रोजगार, सहायता योजना के जरिये प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है। स्व रोजगार के प्रयास करने में प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गयी है। राज्य की कोई भी महिला इस योजना के तहत सरकार से मदद ले सकती है।

युवा आजीविका योजना

अगर आप भी अपना काम करना चाहते हैं और पूंजी की दिक्कत महसूस कर रहे हैं तो आप हिमाचल प्रदेश सरकार की युवा आजीविका योजना का लाभ उठा सकते हैं। प्रदेश में बेरोजगारी की समस्या दूर करने के हिमाचल सरकार ने स्वरोजगार स्कीम युवा आजीविका योजना शुरू की है। युवा आजीविका योजना नाम की इस स्कीम में सरकार बेरोजगार युवाओं को 30 लाख रुपये तक के लोन पर 25 फीसदी सब्सिडी और उसके ब्याज पर पहले साल 8 प्रतिशत की सब्सिडी देती है।

युवा आजीविका योजना में बेरोजगार युवक अपनी पसंद के किसी भी कारोबार के लिए सरकारी लोन योजना का लाभ उठा सकते हैं। युवा आजीविका योजना जुलाई 2018 में ही शुरू की गयी है।

युवा आजीविका योजना के तहत किसी युवा उद्यमी को 30 लाख रुपये तक के लोन के ब्याज पर 8 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलती है। दूसरे साल में ब्याज सब्सिडी छह फीसदी और तीसरे साल में चार फीसदी हो जाती है। युवा आजीविका योजना के तहत प्रदेश के 18 से 40 साल के युवाओं को खुदरा व्यापार, दुकान, रेस्टोरेंट, टूर ऑपरेटर, साहसिक पर्यटन (एडवेंचर टूरिज्म), परंपरागत शिल्प आदि कारोबार शुरू करने पर लोन मिलता है।

योजना में लोन की रकम पर 25 प्रतिशत तक की सब्सिडी (भूमि व मकान को छोड़कर) मिलती है। युवा आजीविका योजना में युवतियों व महिलाओं को लोन पर 30 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलती है।

अगर युवा आजीविका योजना के तहत कोई बेरोजगार युवा जमीन और भवन किराए पर लेता है तो उसकी प्रक्रिया में 6 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी की जगह 3 प्रतिशत की दर से ही ड्यूटी ली जाती है।

इस साल के बजट में जयराम ठाकुर की सरकार ने योजना के लिए 75 करोड़ का बजट प्रावधान किया है। सरकार का यह मानना है कि अगर कोई युवा इस योजना के तहत अपना कारोबार शुरू करता है तो 30 लाख रुपये के निवेश से शुरू होने वाले काम में कम से कम 5-10 और युवाओं को काम मिलेगा। इससे प्रदेश में बेरोजगारी दर को कम करने में खासी मदद मिल सकती है।

युवा आजीविका योजना के उद्देश्य हिमाचल प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश में पहले से कई मशहूर टूरिस्ट स्पॉट भी हैं। इनमें शिमला, कसौली, डलहौजी, धर्मशाला एवं कांगड़ा जैसी जगहें शामिल हैं। राज्य सरकार चाहती है कि युवा पर्यटकों को सुविधा पहुंचाने और उसके जरिये कमाई करने के हिसाब से अपना कारोबार शुरू करें। इसे देखते हुए सरकार ने बेरोजगार युवाओं को 30 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है।

मुख्यमंत्री युवा आजीविका योजना के लाभ हिमाचल के युवाओं को कारोबार के लिए कम ब्याज दर पर लोन मिलता है। लोन की रकम पर 25 प्रतिशत तक की सब्सिडी (भूमि व मकान को छोड़कर) मिलती है। बेरोजगार युवा कारोबार 'उद्यम' कामकाज के लिए राज्य सरकार से लोन ले सकते हैं।

युवा आजीविका योजना का लाभ उठाने की शर्त

युवा आजीविका योजना 18 से 40 साल के बेरोजगार युवाओं के लिए है। आवेदक हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी हो। आवेदक के पास आमदनी का कोई स्थायी स्रोत नहीं होना चाहिए। युवा आजीविका योजना में बेरोजगार युवाओं को 30 लाख रुपये के लोन पर ब्याज सब्सिडी मिलेगी। युवा आजीविका योजना में आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए। आवेदनकर्ता के पास आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए। बेरोजगार युवा का बैंक अकाउंट होना भी जरूरी है। आवेदक के पास हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। एक एफिडेविट जिसमें आपके जॉब नहीं करने का जिक्र हो।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पोषण मिशन वर्ष 2018 में शुरू किया है। यह मिशन कुपोषण, एनीमिया, जन्म के समय कम वजन और वृद्धि में रुकावट की समस्याओं से निपटने में मदद करेगा। इस मिशन के तहत गर्भवती महिलाएं और स्तनपान कराने वाली माताएं (जन्म के 6 महीने बाद), साथ ही ऐसी महिलायें जिनके बच्चे (6 महीने से 3 वर्ष के बीच) के हैं वे घर के लिए राशन ले सकती हैं। इस योजना से पूरे देश में लगभग 10 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।

राष्ट्रीय पोषण मिशन का मुख्य उद्देश्य बेहतर निगरानी, पर्यवेक्षण, लक्ष्य निर्धारण, समय पर कार्रवाई के लिए अलर्ट जारी करना और सभी मंत्रालयों में पोषण संबंधी मार्गदर्शन सुनिश्चित करना है द्य इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने प्रत्येक वर्ष कुपोषण और जन्म के समय कम वजन की समस्या की दर को 2 प्रतिशत कम करने का लक्ष्य तय किया है। 3 से 6 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों को गर्म-पका हुआ भोजन मिलेगा।

इस योजना का लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड एक अनिवार्य दस्तावेज है। वर्ष 2017–2020 तक अर्थात तीन वर्षों के लिए एनएनएम के सफल कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने 9046.17 करोड़ रुपये प्रति वर्ष का 3 वर्षों का बजट आवंटित किया है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन का उद्देश्य

केन्द्र सरकार महिलाओं, किशोर लड़कियों और युवा बच्चों (0–6 साल की आयु) को आवश्यक और पर्याप्त पोषण प्रदान करने के लिए इस मिशन का शुभारंभ करेगी। यह मिशन उन अन्य सभी संबंधित योजनाओं को उंच करेगा जो कुपोषण की समस्याओं से

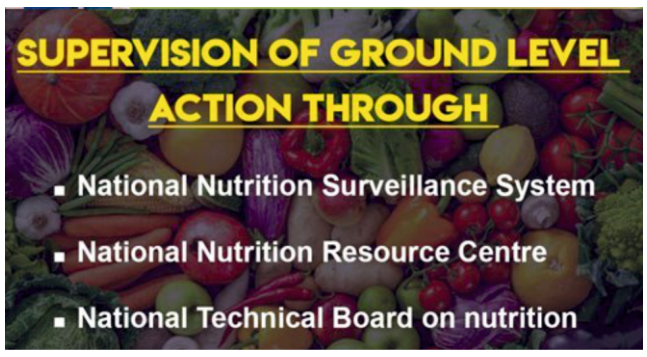

निपटने में योगदान देती हैं।

केंद्र सरकार कुपोषण, जन्म के समय कम वजन, अनीमिया और बृद्धि में रुकावट जैसी समस्याओं से निपटने के लिए एक मजबूत अभिसरण तंत्र बना रही है।

सरकार इस योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए Social Audit करवाएगी। इसके अलावा, Aadhaar के माध्यम से नामांकन सुनिश्चित करने के लिए सरकार सभी आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 500/- रुपये भी देगी।

सरकार एक ICT आधारित मानीटरिंग सिस्टम स्थापित करेगी। इससे आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के काम का बोझ कम होगा और रजिस्टरों को मेंटेन करने की मौजूदा प्रक्रिया का अंत होगा।

श्रमिकों का 'Smartphone' जैसे IT based tools के माध्यम से नवीनतम तकनीकों का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

केंद्र सरकार विभिन्न पोषण संसाधन केंद्र भी खोलेगी। इस प्रयोजन के लिए, सरकार जन आंदोलन के माध्यम से आम जनता की भागीदारी पर भी ध्यान केंद्रित करेगी।

ऐसे होगी मिशन की मॉनीटरिंग

केन्द्र सरकार की ओर से मिशन की सही मॉनीटरिंग करने के लिए एक 6 स्तरीय रियल टाइम रिपोर्टिंग सिस्टम का प्रावधान किया गया है। इसमें आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगबाड़ी सूपरवाइजर, शिशु विकास प्रोजेक्ट अधिकारी, जिला अधिकारी, राज्य स्तर पर मुख्य सचिव द्वारा नियुक्त अधिकारी और केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल हैं।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पोषण मिशन की फंडिंग

इस योजना के लिए 3 साल के लिए कुल बजटीय प्रावधान प्रति वर्ष 9046.17 करोड़ रुपये है। योजना के लिए आवश्यक 50 प्रतिशत धनराशि सरकारी बजट द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी और शेष 50 प्रतिशत निधि IBRD बैंक या किसी अन्य MDB बैंक से आयोजित की जाएगी।

सरकारी बजट समर्थन केंद्र और राज्यों - केंद्र शासित प्रदेशों के बीच 60:40 अनुपात में, पूर्वोत्तर क्षेत्र और हिमालयी राज्यों में यह अनुपात 90:10 का रहेगा, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में में यह अनुपात 100 प्रतिशत विधानमंडल के बिना रहेगा।

३ वर्षों की अवधि में इस मिशन में केन्द्र सरकार का हिस्सा 2849.54 करोड़ रुपये रहेगा।

हिमाचल प्रदेश वोटर लिस्ट में अपने नाम के जाँच कैसे करे

लोक सभा चुनाव 2019

यदि आप भारत के निवासी है तथा आप भारत के किसी भी राज्य में रहते है तो द रीव टाइम्स के इस अंक में आपको बता रहे हैं कि कैसे आप घर बैठे-बैठे ही अपना वोटर लिस्ट 2019 में नाम देखें सकते है। इसके लिए आपको किसी भी सरकारी कार्यालय जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्योकि हर वर्ष होने वाले चुनावो को ध्यान में रखते हुए भारतीय इलेक्शन कमीशन नई वोटर लिस्ट जारी करता है। यदि आपने भी नए वोटर आईडी कार्ड के लिए आवेदन किया था तो अब आप भी भारतीय इलेक्शन कमीशन की आधिकारिक वेबसाइट पर वोटर लिस्ट में अपने नाम की ऑनलाइन जाँच कर सकते है।

वोटर लिस्ट 2019

भारतीय मतदाता पहचान पत्र भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा 18 वर्ष की आयु के बाद ही जारी किया जाता है। इतना ही नहीं इस की मदद से देश के नगर पालिका, राज्य में अपने मतपत्र कास्टिंग करते समय भारतीय नागरिकों के लिए पहचान प्रमाण के रूप में कार्य करता है। वोटर कार्ड या पहचान पत्र की हमें हर किसी कार्य में जरूरत पड़ी है जैसे कि अगर आपको नया सिम कार्ड लेना है तो आपके पास वोटर कार्ड होना अनिवार्य है इसके साथ ही यह पता, और आयु प्रमाण के रूप में भी कार्य करता है।

हिमाचल प्रदेश वोटर लिस्ट में अपने नाम की जाँच कैसे करे

- यदि आप हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी है और अपने वोटर कार्ड के लिए आवेदन किया है तथा अब आप वोटर लिस्ट में अपने नाम की जाँच करना चाहते है तो इसके लिए सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट http://himachal.nic.in पर जाना होगा।
- फिर आपको Search your name in Electoral Rolls by Name के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जिसमे आपको निम्नलिखित विकल्पों को भरना होगा। जैसे कि

1	Select District*
2	Assembly Constituency*
3	Voter*s Name*
4	Father*s/Husband Name
5	Select Gender
6	Age (+/- 5 Years)
7	Enter Below Code

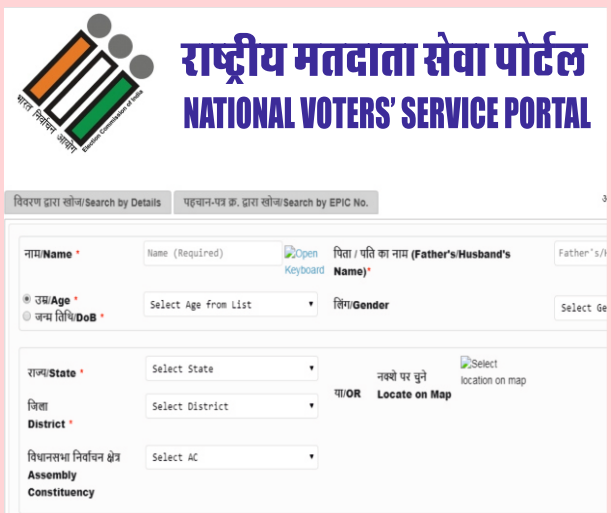

- यह सभी विकल्प भरने के बाद आपको Search के बटन पर क्लिक करना होगा। जिसके बाद आपके सामने हिमाचल प्रदेश वोटर लिस्ट दिखाई दे जाएगी।

इसके अलावा आप टोल फ्री नंबर 18003321950 पर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

मिशन रीव : भर्तियां

MISSION RIEV
Ruralising India- Empowering Villages

CERTIFIED NSDC TRAINING

प्रोग्राम ऑफिसर व सर्विस एसोसिएट के पदों को भरने कि लिए
NSDC प्रमाणित प्रथम प्रशिक्षण बैच हेतु
बड़ी संख्या में आवेदनकर्ताओं के उत्साह का स्वागत् है

15 अप्रैल को हिमाचल दिवस का अवकाश होने पर प्रशिक्षण बैच अब 22 अप्रैल से शुरू होगा

दूसरे बैच के लिए तुरंत आवेदन करें सीमित सीटें शेष

आवेदन करें
www.missionriev.in
www.recruitment.missionriev.in

★ प्रशिक्षण से पहले ऑफर लेटर दिया जाएगा
★ प्रथम बैच 22 अप्रैल 2019 से शुरु
★ सौ फीसद रोज़गार (प्रशिक्षण के बाद)

मात्र 25000/– रूपये प्रशिक्षण शुल्क जिसमें शामिल हैं
★ ऑनलाईन प्रशिक्षण ★ लैपटॉप/टेबलेट ★ संस्थागत प्रशिक्षण
NSDC प्रमाणित प्रमाण पत्र व रोज़गार
T&C Apply*

IIRD
हम जानते हैं गाँव को बेहतर
ISO 9001:2008 Certified

प्रशिक्षण शुल्क हेतु मिशन रीव देगा बैंक ऋण सहायता

For Detail Contact : 01772843528/2844073, 9816741687, 78760 52696, 82196 94079
MISSION RIEV SECRETARIAT, IIRD COMPLEX, BY PASS ROAD, SHANAN, SHIMLA-6, HIMACHAL PRADESH

40 से भी कम है इस देश की आबादी, सड़कों पर खुलेआम घूमते हैं राष्ट्रपति

क्या आप जानते हैं, दुनिया का सबसे छोटा देश कौन है? यहां की कुल आबादी कितनी है, ये जानकर तो आप आश्चर्य से भर जाएंगे। वैसे तो दुनियाभर में कुल कितने देश हैं, इसका सही अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है। कहा जाता है कि पूरे विश्व में 300 से भी अधिक देश हैं। हालांकि इसका कोई आधार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने जिन देशों को मान्यता दी है, सिर्फ उन्हें ही हम पूर्ण राष्ट्र के रूप में जानते हैं और संयुक्त राष्ट्र ने कुल 195 देशों को अपनी मान्यता दी है।

आमतौर पर देखा जाए तो किसी एक बड़े परिवार में 30-35 लोग होते हैं या इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन दुनिया के सबसे छोटे देश की ही कुल आबादी महज 33 है। हैरानी की बात तो ये है कि देश की कुल आबादी में जानवरों की संख्या भी शामिल है। इस देश का नाम मोलोसिया है। इतनी कम आबादी वाला यह देश अमेरिकी प्रांत नेवाडा के पास है। हालांकि अभी तक इस देश को दुनिया की किसी भी सरकार द्वारा मान्यता नहीं मिली है।

मोलोसिया के देश बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। हुआ यूं कि साल 1977 में केविन बॉघ और उनके एक दोस्त को अमेरिका से अलग एक नया देश बनाने का विचार आया, जिसके बाद उन दोनों ने मिलकर मोलोसिया नामक देश की नींव रखी। केविन बॉघ ही इस देश के राष्ट्रपति हैं। यहां रहने वाले ज्यादातर नागरिक केविन बॉघ के ही रिश्तेदार हैं।

इस देश में अन्य देशों की तरह ही कई सुविधाएं भी मौजूद हैं। यहां का कानून, परंपरा और करेंसी भी अन्य देशों से अलग है। दुनियाभर से लोग इस देश में घूमने के लिए आते हैं। अन्य देशों की तरह यहां भी पर्यटकों को अपने पासपोर्ट पर स्टांप लगवाना पड़ता है। इस देश की खासियत ये है कि यहां का राष्ट्रपति अकेले सड़कों पर घूमता है। यहां तक कि वो इस देश में आने वाले पर्यटकों को भी अपने साथ देश घुमाते हैं। यहां की मुद्रा भी अलग है। अगर कोई पर्यटक यहां घूमने आता है और उसे कुछ खरीदना होता है तो सबसे पहले उसे मोलोसियन बैंक से मुद्रा बदलवानी पड़ती है। उन्हें इसके बदले वालोरा मुद्रा दी जाती है। इस देश में पोस्ट ऑफिस भी मौजूद है।

यहां दिखावे के लिए होते हैं चुनाव

भारत में अप्रैल से लेकर मई महीने के बीच लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। कुल सात चरणों में चुनाव होंगे, जिसके नतीजों की घोषणा 23 मई को की जाएगी। चुनाव के बाद ही पता चलेगा कि सत्ता की चाबी इस बार किसके हाथ में होगी। इस मौके पर हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं, जहां सिर्फ दिखावे के लिए ही चुनाव कराया जाता है, क्योंकि यहां नतीजे पहले से ही तय होते हैं। इस देश का नाम है उत्तर कोरिया। यहां होने वाले चुनाव को दुनिया का सबसे अनोखा चुनाव कहा जाता है। हर पांच साल पर यहां सुप्रीम पीपुल्स असेंबली के लिए चुनाव होते तो हैं, लेकिन मतदान के दौरान हर मतपत्र पर केवल एक ही उम्मीदवार का नाम होता है और वो नाम है किम जोंग । इसको दुनिया उत्तर कोरिया के तानाशाह के तौर पर जानती है। कहा जाता है कि किम जोंग की इजाजत के बिना यहां कोई भी काम नहीं होता है। वो अगर कानून बना दे तो उसे तोड़ने या फिर उसके खिलाफ विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं है। 10 मार्च को उत्तर कोरिया में सुप्रीम पीपुल्स असेंबली के चुनाव को लेकर मतदान कराया गया, जिसके नतीजे पहले से ही तय माने जा रहे हैं। यहां के एक चुनाव अधिकारी का कहना है कि उत्तर कोरिया में चुनाव में हिस्सा लेना नागरिकों का कर्तव्य है और यहां ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो उम्मीदवार को नकार दे। यहां मतदाताओं को मतदान करते हुए मतपत्र पर केवल हां या नहीं ही लिखना होता है। उम्मीदवारों की अंतिम सूची से यह पता चलता है कि देश के नेतृत्व के साथ कौन है और कौन नहीं। आधिकारिक समाचार एजेंसी केसीएनए के मुताबिक, पिछले चुनाव में यहां 99.97 फीसदी मतदान हुआ था। सिर्फ उन लोगों ने चुनाव में मतदान नहीं किया था, जो देश से बाहर थे।

उत्तर कोरिया की खास बात ये भी है कि यहां साल में सिर्फ एक या दो बार ही संसद की बैठक होती है और वो भी तब जब बजट या फिर देश की सुरक्षा से संबंधित कोई दूसरे फैसले लेने होते हैं।

आवश्यक सूचना

हिमाचल का सबसे तेज़ गति से उभरता पाक्षिक समाचार पत्र द रीव टाइम्स में मार्केटिंग हेतु युवाओं (लड़के/लड़कियों) की आवश्यकता है। एक स्थाई रोजगार एवं बेहतर वेतनमान के साथ आकर्षक कमीशन का प्रावधान रहेगा। इच्छुक शीघ्र ही संपर्क करें।

द रीव टाइम्स
दूरभाष : 9418404334
Chauhan.hemraj09@gmail.com, hem.raj@iirdshimla.org

द रीव टाइम्स आपकी आवाज़ ही है हमारी आवाज़

राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिलों, गांव, स्वास्थ्य, कानून, समसामयिक विषयों पर संपादकीय एवं अभिव्यक्ति, सामान्य ज्ञान, प्रतियोगी परीक्षाओं का ज्ञान दर्पण, सरकारी जनपयोगी योजनाओं का संपूर्ण दस्तावेज़.....द रीव टाइम्स उत्कृष्ठ गुणवत्ता, संपूर्ण रंगीन पृष्ठ, शानदार विषयवस्तु के साथ प्रदेश का पाक्षिक समाचार पत्र द रीव टाइम्स अब आपको मिलेगा घर-द्वार पर ही। समाचार पत्र को लगाने के लिए आप हमारी वेबसाइट http://sub.missionriev.in पर लॉगइन कर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा मिशन रीव के कार्यकर्ता/अधिकारी से संपर्क कर भी आप कैशलैस भुगतान कर इसके वार्षिक सदस्य बन सकते हैं। अब आपके लिए आकर्षक ऑफर.....

अब वार्षिक सदस्य बनें केवल 500/रूपये, छः माह के लिए 250/रूपये में और घर बैठे पांऐ द रीव टाइम्स.....क्योंकि आपकी आवाज़ ही है हमारी आवाज़